butory fund. Otherwise, the term 'Provident Fund' means that it is contributory.

श्री मोरारजी देसाई : यह भी नान-कांट्रीब्यूटरी है। लेकिन इस वक्त यह सवाल यहां उपस्थित नहीं होता है। जब बिल चर्चा के लिए आए तब जरूर आप इस पर चर्चा कर सकते हैं और तब इसके बारे में सोचा जाएगा।

MR. SPEAKER : When we discuss the Bill, naturally these aspects also could be discussed. Now, we are only at the stage of leave being granted to introduce the Bill.

The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the institution of a provident fund for the general public."

The motion was adopted.

SHRI MORARJI DESAI : I introduce† of the Bill.

SHRI S. M. BANERJEE : Let them have 'Provident' and we will have the fund.

———

12.43 hrs.

MOTION RE : REPORT OF U.P. GOVERNOR TO PRESIDENT ON ISSUE OF PROCLAMATION

AND

RESOLUTION RE : PROCLAMATION BY PRESIDENT IN RELATION TO UTTAR PRADESH

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा खेद व्यक्त करती है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई दिनांक 10 अप्रैल, 1968 की रिपोर्ट को अस्वीकार नहीं किया जिसमें राज्य विधान सभा को विघटित करने और राज्य में मध्यावधि चुनाव करने के लिए उद्घोषणा, जो 16 अप्रैल, 1968 की सभा पटल पर रखी गई थी, जारी करने की सिफारिश की गई थी, चूंकि राज्य विधान सभा में संयुक्त विधायक दल को बहुमत प्राप्त था और उसके नेता को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया जाना चाहिए था।"

दोनों प्रस्तावों पर एक साथ विचार होना है तो वह भी मूव कर दें और मेरा भाषण बाद में हो।

MR. SPEAKER : The Home Minister may move his resolution...

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I shall move the resolution first.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : I think there is no separate discussion on the motion and the resolution.

SHRI Y. B. CHAVAN : I shall formally move the resolution. I shall move it but speak later on. Let him have his say now.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : May I submit that there is a mistake in the Order Paper ? First, the resolution should have been put in and then only this motion. But the two have appeared in the reverse order.

MR. SPEAKER : Shri A. B. Vajpayee is prepared to speak now on his motion. So, let not the hon. Member worry about it. Afterwards, the Home Minister will move his resolution.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, एक और, प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो गई और हम यहां शव परीक्षा के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक और गैर-कांग्रेसी सरकार केन्द्र की कुटिलता और कुचक्र का शिकार बना दी गई है और आज हम उसके ऊपर अपना रोष व्यक्त करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, गत बारह महीनों में यह चौथा अवसर है जब कि संविधान के अनुच्छेद

† Introduced with the recommendation of the President.

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

356 का दुरुपयोग करके केन्द्रीय सरकार ने प्रादेशिक स्वायत्तता का गला घोंटा है और दलगत और गुटगत स्वार्थों की रक्षा के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। पहले राजस्थान फिर हरियाणा, बाद में पश्चिमी बंगाल और अब प्रधान मंत्री का उत्तर प्रदेश। यह एक ही कड़ी की लड़ियां हैं, यह एक ही मनमानी की कहानी है। यह कहानी केन्द्र के अलोकतंत्रीय व्यवहार की है। यह कहानी राज्यपाल द्वारा अपने पद के दुरुपयोग और पक्षपातपूर्ण आचरण की है। यह कहानी भारतीय संविधान की खुली अवहेलना की कहानी है। यह कहानी भारतीय गणराज्य के आधार पर ही कुठाराघात करने वाली कहानी है। यह कहानी चौथे आम चुनाव के बाद देश में लोकतंत्र की शोकांतिका की कहानी है। इस सदन को इस कहानी पर आज गम्भीरता से विचार करना होगा।

जब संविधान निर्माण के समय संविधान परिषद इस 356 धारा के बारे में तीन और चार अगस्त 1947 को विचार कर रही थी तब डा० कुंजरू ने आपत्ति की थी कि केन्द्रीय सरकार को यह देखने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी राज्य में शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलता है या नहीं। उन्होंने यह तो माना था कि किसी विदेशी आक्रमण की स्थिति या घरेलू तोड़-फोड़ अथवा व्यापक उपद्रवों के समय केन्द्र को राज्यों के शासन में हस्तक्षेप करके उनका शासन अपने हाथ में लेने का अधिकार होना चाहिए। किन्तु संविधान के अनुसार शासन चलता है या नहीं चलता है यह एक बड़ी अस्पष्ट बात है। डा० कुंजरू ने कहा था कि यह बात संविधान में शामिल नहीं की जानी चाहिए। संविधान परिषद में इस बात पर चर्चा हुई थी और यह प्रश्न उठा था कि अगर किसी प्रदेश में अनेक दल हों और वे स्थायी सरकार नहीं बना सकते हों तो क्या केन्द्र को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उस क्षेत्र की जनता को अपने लोकतंत्रीय शासन के अधिकार से वंचित कर दे? मैं डा० कुंजरू का एक अंश सदन के सामने उद्धृत करना चाहता हूँ :

> "If there is a multiplicity of parties in any province, we may not welcome it. But is that fact by itself sufficient to warrant the Central Government's interference in the provincial administration? There are many parties in some countries making ministries unstable. Yet the governments of these countries are carried on without any danger to their security or existence. It may be a matter of regret if too many parties exist in a province and they are not able to work together or arrive at an agreement on important matters in the interests of their province. But however regrettable this may be, it will not justify, in my opinion, the Central Government in intervening and making itself jointly with Parliament responsible for the government of the province concerned".

डा० कुंजरू की इस आपत्ति का जवाब देते हुए डा० अम्बेदकर ने जो कुछ कहा था सदन को उसका भी स्मरण रखना चाहिए। चर्चा के दौरान प्रश्नोतर हुए थे। और डा० कुंजरू ने यह स्पष्ट प्रश्न किया था :

> "May I ask my hon. friend to make one point clear? Is it the purpose of article 278"—

संविधान के प्रारूप में अनुच्छेद इस प्रकार था :-

> "and article 278 (a) to enable the Central Government to intervene in provincial affairs for the sake of good government of a province?"
>
> "*Dr. Ambedkar* : No, no. The Central Government is not given that authority.
>
> "*Pandit Kunzru* : Or only when there is such misgovernment in the province as to endanger the public peace or...

इसका डा० अम्बेदकर ने जो जवाब दिया था वह भी मैं पढ़ना चाहता हूँ :

"In regard to the general debate which has taken place, it has been suggested that these articles are liable to be abused. I may say that I do not altogether deny that there is a possibility of these articles being abused or employed for political purposes. But that objection applies to every part of the Constitution which gives power to the Centre to override the provinces. In fact, I share the sentiments expressed by my hon. friend, Mr. Gupta, yesterday that the proper thing we ought to expect is that the articles will never be called into operation and they would remain a dead letter".

भारतीय संविधान के निर्माण में जिन्होंने निर्णायक भाग लिया, उन डा० अम्बेदकर का यह कहना था कि अनुच्छेद 356 जैसे प्रावधान को कभी प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, उसका उपयोग करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पिछले अठारह साल के उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, जब बारह बार इस अनुच्छेद का उपयोग करके प्रान्तीय सरकारें तोड़ी गई और राष्ट्रपति राज लागू किया गया। इस में एक बात स्मरण रखने वाली है वह यह है कि इन बारह अवसरों में से केवल दो अवसर ऐसे हैं जिन में इस धारा का उपयोग किये जाने के कारण कांग्रेस दल को नुकसान हुआ। शेष दस बार विरोधी दलों को शासन से वंचित करने के लिए ही इस अनुच्छेद का उपयोग किया गया है। चौथे आम चुनाव के बाद अब चौथी बार इस अनुच्छेद का उपयोग किया जा रहा है।

हर बार यह प्रयत्न किया गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो उसे किसी प्रकार सत्ता में लाया जाये और अगर विरोधी दल सत्ता में हैं, तो उन्हें किसी प्रकार सत्ता से अपदस्थ किया जाये।

प्रारम्भ हुआ राजस्थान से। राजस्थान में विधान सभा स्थगित की गई, क्योंकि कांग्रेस बहुमत बनाने की स्थिति में नहीं थी। जैसे ही कांग्रेस बहुमत बनाने की स्थिति में हो गई, विधान सभा को पुनरुज्जीवित कर दिया गया, और कांग्रेस को सत्तारूढ़ कर दिया गया।

लेकिन विधान सभा को स्थगित करने की प्रक्रिया हरियाणा में नहीं अपनाई गई। हरियाणा में गैर-कांग्रेसी मंत्रि-मंडल बहुमत में था। उसे विधान सभा में परास्त नहीं किया गया उसे शक्ति-परीक्षण तक का मौका नहीं दिया गया। उसे अपना आचरण सुधारने की चेतावनी भी नहीं दी गई और विधान सभा तोड़ दी गई तानाशाह तरीके से, गैर-कांग्रेसी सरकार अपदस्थ कर दी गई।

पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने किस तरह से आचरण किया और पश्चिमी बंगाल की सरकार किस तरह से चल रही थी, इस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता। उस विषय में मतभेद हो सकते हैं। लेकिन किसी राज्यपाल को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह जनतन्त्रीय तरीकों से किसी चुनी हुई सरकार को बिना विधान सभा में शक्ति-परीक्षा का मौका दिये बर्खास्त कर दे। पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने भी ऐसा ही आचरण किया, जो कांग्रेस को सत्ता में आने का रास्ता खोलने वाला और विरोधी दलों को शासन से वंचित करने वाला था।

ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? राज्यपाल महोदय ने जो रिपोर्ट दी है और जिस के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है, वह रिपोर्ट हास्यास्पद है। वह रिपोर्ट 10 अप्रैल को दी गई थी। 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? संयुक्त विधायक दल में शामिल सभी दलों ने श्री हरिश्चन्द्र सिंह को अपना नेता माना था।

एक माननीय सदस्य : गलत।

एक माननीय सदस्य : सभी दलों ने नहीं माना।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : संयुक्त समाजवादी दल का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को मिला था और उस ने उन से कहा था कि वह श्री हरिश्चन्द्र सिंह को सरकार बनाने

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

के लिए बुलायें; हम उन के साथ हैं। भारतीय क्रान्ति दल इस निर्णय में शामिल था। नौ विरोधी दलों का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल को मिला था। अगर राज्यपाल को यह सन्देह था कि संयुक्त विधायक दल को बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वह कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते थे।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : करना चाहिये था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : निमन्त्रित क्यों नहीं किया ? संयुक्त विधायक दल के नेताओं ने यह मांग की थी कि जो कांग्रेस अल्पमत में थी, चूंकि वह इस बात का दावा कर रही है कि संयुक्त विधायक दल के कुछ विधायक कांग्रेस में चले गए हैं, और अब वह बहुमत में हो गई है, इस लिए उन दल बदलने वाले विधायकों के नाम घोषित कर दिये जायें। कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को नहीं माना। इस को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के विधायक सचमुच में अस्तित्व में थे ही नहीं। ज़ोर-ज़बर्दस्ती से, लोभ या लालच से उन के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिये गये थे। अगर उन के नाम प्रकट कर दिये जाते, तो वे लोग लोक-लाज के सामने टिक नहीं सकते थे।

क्या दल बदलने की प्रक्रिया राजभवन से चलेगी ? अध्यक्ष महोदय, आप कल्पना कीजिए। संसद् की बैठक नहीं चल रही है और विरोधी दल के कुछ सदस्य जा कर राष्ट्रपति से मांग करें कि इन्दिरा गांधी सरकार का बहुमत खत्म हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के 20, 22 या 30, सदस्यों ने हम को लिख कर दे दिया है कि वे हमारे साथ शामिल होने को तैयार हैं,.....

एक माननीय सदस्य : यह मौका इन को कभी नहीं मिलेगा।

श्री हुकमचन्द कछवाय (उज्जैन) : जल्दी आयेगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :...तो क्या स्थिति होगी ? (**व्यवधान**) मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। (**व्यवधान**) क्या ऐसे अवसर पर राष्ट्रपति को या किसी प्रदेश में किसी राज्यपाल को यह अधिकार होगा कि उन नामों को बिना घोषित किये, केवल उन लोगों के कहने के आधार पर इस बात का निर्धारण करें कि किस का बहुमत है और किस का नहीं ? यह एक बड़ी खतरनाक नीति अपनाई जा रही है। इस के भयंकर परिणाम हो सकते हैं।

अगर किसी को दल बदलना है, तो उसे जनता की नज़र के सामने दल बदलना चाहिए। उस में जनता का सामना करने का साहस होना चाहिए। हमारे लोकतन्त्र को तभी शक्ति मिलेगी, जब हम दल बदलने वालों को जनता का सामना करने का साहस जुटाने की सलाह देंगे।

एक माननीय सदस्य : मध्य प्रदेश में क्या हुआ ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने यह नहीं किया। राज्यपाल महोदय यह दावा करते हैं कि मैं ने एक स्थायी सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वह सरकार नहीं बनी। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह स्थायी सरकार का मतलब क्या है ? अगर किसी दल में 51 सदस्य हैं और विरोधी दल में 49 सदस्य हैं, तो राज्यपाल किस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे ? बहुमत चाहे एक का ही हो वह बहुमत है और किसी भी राज्यपाल को या राष्ट्रपति को बहुमत के आधार पर जाना होगा। स्थायित्व भविष्य का विषय है। राज्यपाल को निर्णय वर्तमान में करना है। कोई सरकार टिकेगी या नहीं, यह तो भविष्य ही बता सकता है। मगर भविष्य का अनुमान लगा कर, जो ग़लत भी हो सकता है, जो किसी के साथ अन्याय भी कर सकता है, कोई राज्यपाल, आज जिस का बहुमत है,

उस को सरकार बनाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है ।

इस बात का भी निर्णय होना चाहिए कि सरकारों की तक़दीर का फैसला राजभवन में होगा या विधान सभाओं में होगा । गृह मंत्री कहेंगे कि जब राज्यपाल ने विधान सभा स्थगित कर दी तो परिस्थिति बदल गई, उन्हें तय करना था कि कौन सा दल सरकार बना सकता हैं या नहीं बना सकता है ।

यह बात तो राज्यपाल भी मानते हैं कि संयुक्त विधायक दल का बहुमत था । चौधरी चरण सिंह ने संयुक्त विधायक दल में मतभेद के कारण इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उस से संयुक्त विधायक दल का बहुमत ख़त्म नहीं हुआ । संयुक्त विधायक दल ने दूसरा नेता चुना श्री रामचन्द्र विकल के रूप में ।

एक माननीय सदस्य : कितने दिनों के बाद ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तीन दिन के बाद ।

राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया ? 17 तारीख को चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफ़ा दिया और 21 तारीख को श्री रामचन्द्र विकल चुने गए । राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने के लिए बुला सकते थे । लेकिन राज्यपाल ने एक बड़ी विचित्र बात कही । मैं राज्यपाल के 22 फरवरी के कथन का एक अंश उद्धृत कर रहा हूँ :

> "Given a reasonable time, a reorientation of political affiliations may emerge in the State Assembly, which right enable the formation of a stable Government without the necessity of another general election."

राज्यपाल मध्यावधि चुनाव टालना चाहते थे । उन्होंने स्वीकार किया था कि मध्यावधि चुनाव मंहगे हैं; राज्य की जनता को इस कष्ट-साध्य प्रक्रिया में नहीं डालना चाहिए । इस लिए उन्होंने विधान सभा स्थगित की । वह दलों को मौका देना चाहते थे कि वे अपनी शक्ति का संयोजन इस तरह से करें कि राज्य में एक लोकप्रिय सरकार चल सके । मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 अप्रैल को ऐसी क्या बात हो गई । असलियत यह है कि जो दल परस्पर थोड़े दूर चले गये थे, वे 10 अप्रैल को निकट आ गये थे । संयुक्त विधायक दल एकमत हो कर खड़ा था ।श्री हरिशचन्द्र सिंह के नाम पर सब का मतैक्य था ।

श्री नरदेव स्नातक : (हाथरस) आप भी एकमत नहीं हैं । .....(**व्यवधान**).....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : राज्यपाल को उन्हें सरकार बनाने के लिये...(**व्यवधान**)... अध्यक्ष महोदय, यह समय मेरे समय में से न लिया जाय । आप टोका-टाकी करिये, दिल में जोर बैठा है, वह बोलेगा, पाप अपना मुंह खोलेगा ।

MR. SPEAKER : The hon. Member may kindly resume his seat. Perhaps he will take another five or ten minutes. He may continue after lunch. We may now adjourn for lunch and meet again at 14.00 hours.

13.00 hrs.

The Lok Sabha adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock).

[Mr Deputy-Speaker *in the Chair]*

MOTION RE : REPORT OF U.P. GOVERNOR TO PRESIDENT ON ISSUE OF PROCLAMATION AND RESOLUTION RE : PROCLAMATION BY PRESIDENT IN RELATION TO UTTAR PRADESH—*Contd.*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विरुद्ध मेरा

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अभियोग हैं कि उन्होंने राज्यपाल का पद ग्रहण करते समय जो शपथ ली थी उसका उल्लंघन किया है। शपथ के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल को अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करना होता है और जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहने का संकल्प लेना होता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल इस शपथ का उल्लंघन करने के दोषी हैं। उन्होंने राज्य के सवैधानिक प्रमुख के नाते आचरण करने के बजाय दलबन्दी की दलदल में फंसना अधिक उपयुक्त समझा है, निष्पक्ष आचरण करने के बजाय पक्षपात से काम लिया है। क्या आप किसी ऐसे राज्यपाल की कल्पना कर सकते हैं जो मुख्य मंत्री बनाने के संबंध में निर्णय करने से पहले विरोधी दल के नेता को यह पत्र लिखे कि क्या "विरोधी दल" के नेता चौथी पंचवर्षीय योजना में विश्वास करते हैं, क्या वे योजना के लिये साधन जुटाने को तैयार हैं, क्या वे नीतियों की निरन्तरता को बनाये रखना चाहते हैं। राज्यपाल ने श्री हरिश्चन्द्र सिंह को जिस प्रकार का पत्र लिखा है वह बड़ी गम्भीर बात है। किसी भी राज्यपाल को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह मुख्य मंत्री के पद ग्रहण करने से पहले उनके ऊपर शर्तें लगाये, या उन्हें किन्हीं नीतियों के लिये बाँधे। यह लोकतन्त्र की प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। यह लोकतन्त्र पर आघात करना है लेकिन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने श्री हरीश्चन्द्र सिंह को पत्र लिखकर इस प्रकार की शर्तें लगाने की कोशिश की। और आश्चर्य की बात यह है कि जब उन्हें राज्यपाल ने श्री चन्द्रभानु गुप्त को पत्र लिखा तो उसमें चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये साधन जुटाने और नीतियों में निरन्तरता कायम रखने के ऊपर बल नहीं दिया।

मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वह किसी राज्यपाल के द्वारा इस तरह का पत्र लिखने का समर्थन करते है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे कांड में केवल राज्यपाल ही दोषी नहीं हैं केन्द्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार भी दोषी है। राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत सिफारिश की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी संविधान राज्यपाल को संविधान को भंग करने का अधिकार नहीं देता। राज्यपाल केवल राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। केन्द्रीय सरकार के लिये यह मार्ग खुला था कि वह राज्यपाल की रिपोर्ट उनके पुनर्विचार के लिये वापिस कर देती। केन्द्रीय सरकार के लिये यह भी मार्ग खुला हुआ था कि वह राज्यपाल की रिपोर्ट से सहमत होने से इन्कार कर देती। केन्द्रीय सरकार इतना कठोर कदम उठाने से पहले, जिसे न तो कांग्रेस ही उत्तर प्रदेश में चाहती थी और न विरोधी दल ही चाहते थे उत्तर प्रदेश के सभी दलों को चेतावनी दे सकती थी कि अगर लोकतान्त्रिक ढंग से उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी तो केन्दीय सरकार को कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इसकी आवश्यकता नहीं समझी। संविद के नेता दिल्ली आये, राष्ट्रपति भवन में गये, उन्होंने प्रधान मन्त्री से भी चर्चा की। वे अपने पक्ष में 229 सदस्यों का बहुमत सिद्ध करने के लिये तैयार थे वे तैयार थे कि उनके सदस्यों की संख्या गिन ली जाये। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इस बात का मौका नहीं दिया।

आश्चर्य की बात तो यह है कि राज्यपाल ने सिफारिश की कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा के स्पीकर बरकरार रहें और केन्द्रीय सरकार ने उस सिफारिश को मान लिया। विधान सभा भंग कर दी गई विधान परिषद् के जो नये सदस्य चुने गये हैं वे शपथ नहीं ले सकेंगे, वे वेतन प्राप्त नहीं कर सकेंगे लेकिन जिस विधान सभा को भंग कर दिया गया है उसके स्पीकर अपने आसन पर बैठे रहेंगे। भला हरियाणा के स्पीकर को क्यों नहीं कायम रखा गया? क्या इसलिये कि उत्तर प्रदेश विधान

सभा का स्पीकर कांग्रेसी था और हरियाणा का स्पीकर विरोधी दल का था ? क्या केन्द्रीय सरकार के लिये राज्यपाल की इस सिफ़ारिश को मानना जरूरी था ? गृह मन्त्री जी इसका जवाब दें। लेकिन वे इसका कोई जवाब नहीं दे सकते, वे लीपा-पोती करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि यह आचरण ठीक है क्योंकि उससे न तो कांग्रेस वाले खुश हैं और न विरोधी दल वाले खुश हैं। अगर ठीक काम की यही कसौटी है कि उससे सब नाराज़ हों तब तो फिर लोकतन्त्र में लोकप्रियता का कोई माप-दंड ही नहीं रहेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसमें पक्षपात साबित नहीं होता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पक्षपात भी दिखाता हूँ।

अगर उत्तर प्रदेश में यह सिद्ध हो जाता कि कांग्रेस की सरकार बन कर टिकेगी तो फिर केन्द्रीय सरकार विधान सभा को भंग करने का कठोर कदम नहीं उठाती। मुझे दुख इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर जो गुट-बन्दी चल रही है, उसका शिकार विधान सभा को होना पड़ा है। जब चौधरी चरण सिंह ने कहा कि मध्यावधि चुनाव होने चाहिये तब राज्यपाल ने नहीं माना क्योंकि वह देखना चाहते थे कि दल बदलने वालों के समर्थन से कांग्रेस सरकार बनाने का मौका मिलता है या नहीं। जब कांग्रेस को यह मौका नहीं मिला तब उन्होंने संविद को सरकार बनाने का मौका देने के बजाय विधान सभा को ही भंग कर देना ठीक समझा।

यह केवल पक्षपात नहीं। उत्तर प्रदेश में पक्षपात से भी निकृष्ट गुट्टबंदी का एक नग्न नृत्य चल रहा है। केन्द्र में बैठे हुए कुछ कांग्रेस के नेता यह नहीं चाहते कि चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री बनें। इसलिए निष्पक्षता का यह नाटक रचा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे लोकसभा अध्यक्ष के नियन्त्रण में, नियमन में, उन की अध्यक्षता में देश की विधान सभाओं के अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये गये हैं। मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आहूत सम्मेलन के निर्णयों को स्वीकार करते हैं ? मैं डा० संजीव रेड्डी के भाषण का एक अंश उद्धृत कर रहा हूँ :

> "A Ministry which has lost its majority in the Assembly after the session is over, may continue in office, until another session is summoned, and if it fails to summon a House within a reasonable period, the remedy which I have suggested in the preceding para will apply ; that is to say that the majority of Members may force the Chief Minister to summon the Assembly on a date suggested by them."

उसी के आधार पर उस सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया जिस में कहा गया था :

> "The question whether a Chief Minister has lost majority in the Assembly or not should at all times be decided by the Assembly."

यह निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है।

SHRI Y. B. CHAVAN : How does it apply here ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : गृह मंत्री महोदय कह सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश में कैसे लागू होता है ? वह मैं आप को बतला रहा हूँ। इस बात का निर्णय करना कि कोई सरकार टिकेगी या नहीं विधान सभा में होना चाहिए अथवा यह राज्यपाल की मनमानी मर्जी के ऊपर छोड़ दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : क्या वहां कोई सरकार थी ? सरकार इस्तीफ़ा देकर हट गई थी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सरकार इस्तीफ़ा देकर नहीं हटी थी। चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफ़ा दिया था। यह बात उत्तर

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

प्रदेश पर इस अर्थ में लागू होती है कि एक मुख्य मंत्री के इस्तीफ़ा देने के बाद जिस दल का बहुमत या उस के प्रतिनिधि को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया गया विधान सभा की पीठ के पीछे किस का बहुमत है यह निर्णय करने की कोशिश की गई। अगर इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश से अलग भी कर दिया जाय तो मैं पूछता हूँ कि बंगाल में क्या हुआ था ? क्या गृह मंत्री भविष्य के लिए इस प्रकार की परम्परा डालने के लिए तैयार हैं ? अगर कांग्रेस यह समझती है कि राज्यपालों के पद का दुरुपयोग कर उन्हें कठपुतली बना कर वह अपनी खोई हुई लोकप्रियता वापिस प्राप्त कर लेगी तो कांग्रेस को बड़ी निराशा हाथ लगने वाली है।

हैदराबाद के अधिवेशन में गैर कांग्रेसी सरकारों का खात्मा करने का निश्चय किया गया था। उसी षड़यन्त्र के अनुसार एक, एक करके गैर कांग्रेसी सरकारें तोड़ी जा रही हैं। लेकिन इस से कांग्रेस फिर से जनता के हृदय में अपनी जगह नहीं बना सकती। लोकसभा के तीन उपचुनाव हो चुके हैं। इन तीनों उप-चुनावों में कांग्रेस हारी है। कांग्रेस पार्टी को दीवार पर लिखे हुए को पढ़ना चाहिए। देश के भीतर धरती के अन्दर से उठने वाले भूकम्प की गड़गड़ाहट को उसे सुनना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मध्यावधि चुनाव एक बड़ी खर्चीली चीज़ है। क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में भी विचार किया है कि एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश को इस खर्चीली प्रक्रिया में डालना लोकतन्त्र को मजबूत करेगा या वह लोकतन्त्र को पूंजी का गुलाम बना देगा ? जो दल जनता के बल पर शक्ति ग्रहण करते हैं जो विदेशों से पैसा लेना देशद्रोह समझते हैं, उन दलों के सामने आज बड़ा संकट खड़ा है। वह कहां से चुनाव लड़ने के लिए पैसा लायें ? एक ओर तो समाजवाद को लाने की चर्चा हो रही है, दस सूत्री कार्यक्रम की घोषणाएं की जाती हैं मगर दूसरी नीतियां ऐसी अपनाई जा रही हैं कि जिनसे राजनीति पर पूंजी का प्रभाव बढ़ेगा। इस दृष्टि से भी विधान सभा को तोड़ने का और मध्यावधि चुनाव के आदेश देने का निर्णय ग़लत है। इस का अर्थ यह नहीं कि हम चुनाव से घबराते हैं। हम उस के लिए तैयार हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर चुनाव हुए तो कांग्रेस की जितनी सीटें आज हैं उन से कम सीटें उस के पास आने वाली हैं। लेकिन प्रश्न यह है क्या हम अपने देश में, लोकतन्त्र पर आधारित संघात्मक संविधान को सफल बनाना चाहते हैं या नहीं। इस सदन को इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। मैं सदन से अपील करूंगा कि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार करे और गृह मंत्री पर अंकुश लगाये जिससे भविष्य में और अन्य किसी प्रदेश में लोकतन्त्र पर आघात करने का उन का साहस न हो।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That this House regrets that the Government of India did not reject the report dated the 10th April, 1968 of the Governor of Uttar Pradesh to the President recommending the issue of Proclamation, laid on the Table of the House on the 16th April, 1968, seeking dissolution of the State Assembly and mid-term poll in the State, inasmuch as the S. V. D. in the State Assembly enjoyed majority in the Assembly and its leader ought to have been invited to form the Ministry."

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I beg to move :

> "That this House approves the Proclamation issued by the President on the 15th April 1968, under articles 356 of the Constitution in relation to the State of Uttar Pradesh, varying the earlier Proclamation issued on the 25th February, 1968."

I do not want to take the time of this hon. House at this stage because I am expected to reply again to the points that

would be made by the hon. members. But I would certainly state certain basic facts.

We have to take into consideration the whole history of the matter. As we know, two months before—it is now roughly two months—the then leader of the S. V. D. and the Chief Minister of U. P. offered to resign, not only offered to resign but also gave alternativie advice to the Governor ; one was that he should invite the other leader of the S. V. D. to form a Government or, in the alternative, to order a mid-term election, so that the people of U. P. may be in a position to say who are going to be in the stable majority. I am mentioning this fact because the question of mid-term election, which the hon. Member while moving his motion has condemned so much, was also contemplated by the leader of the S. V. D. himself when he resigned. I am merely mentioning the facts without any comments of mine...

AN HON. MEMBER : Facts do not mean anything to them.

SHRI Y. B. CHAVAN : Sometimes they are so eloquent.

So, this is one fact. Again—it is an interesting fact—at that time he said that he had raised eight or ten points. There was this tussle in the SVD; I am not interested in this tussle but I am interested in a stable Government. When more than one party decide to form a Government with a promise and assurance to the people that they will form a Government, their agreements about programmes do become a relevant matter. Not that the Governor had taken the initiative in the matter. Publicly the then Chief Minister of U. P. and the leader of the SVD himself asked some questions of the other parties whether they agreed to such programmes or not. This sort of thing continued. This instability continued. This is one fact.

The other fact is that the Governor was, in a way, forced to accept the resignation and recommend suspension of the Legislature and taking over by the President to which we agreed and came before this hon. House and the hon. House approved of it. Now, there is a qualitative change in the situation.

The hon. Member again referred to the recommendation or resolution of the Speaker's Conference. I think, the Speaker's Resolution is a very important one; we have all respect for this Resolution and certainly we have to consider that; with all the respect and care, we have to bestow our consideration on that matter, But the situation that the Speaker's Conference has contemplated does not apply to the U. P. situation at all. It, really speaking, speaks about the Governor's right of dismissal and, I think, they have the situation of Bengal in their mind. When a chief Minister has lost the majority or if there is a claim like that, under those circumstances what procedure should be adopted, is. really speaking, the matter which the Speaker's Conference has raised. I do not want to offer any comment on that because that is a separate matter; we have discussed this matter and possibly we will discuss it again.

In this matter, the fact is very obvious. There was no Chief Minister and there was no Government, and the Governor had to apply his mind afresh to making an assessment of the situation whereby he could find out who was in a position to provide a stable government to the people of U. P.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj) : And several leaders were chosen.

SHRI Y. B. CHAVAN : At this stage he is certainly entitled on proper consideration to come to a conclusion as to whether A is in a majority or is not in a majority. In this particular situation, both the parties had taken up the position that only if there was a stable government should its leader be called upon to take the responsibility. Here again, there is another very peculiar situation, where both the parties, the Congress and the SVD claim a majority. This is also a fact. I would not be surprised if I hear speeches from the Congress side also on this line. It only means that there is an element of membership of both the parties which is seemingly giving the impression to both the leaders that those members are on their side.

AN HON. MEMBER : Floating population.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Probably they will be on the side of the government.

SHRI Y. B. CHAVAN : If it were a position like in Rajsthan where immediately after the elections a government were to be formed, then certainly those processes could as well have been adopted or should have been adopted, but here both the parties were given a trial. First of all, the Congress Party was called upon to form a Government and they formed a government; later on, they lost the majority in the Assembly and they resigned and resigned with great dignity and went out. There after, the SVD was asked to form a government and all co-operation was given to the SVD Government by the Governor and by the Central Government also.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The SVD was never defeated.

SHRI Y. B. CHAVAN : The only party from which the Chief Minister of U. P. did not get co-operation, was not this Government or the Governor but it was his own party. This is also a fact. This is not a comment. This is absolutely a fact of life.

SHRI D. N. TIWARY : He was not defeated but went out.

SHRI Y. B. CHAVAN : If they want a scape-goat for their failures and if they want the poor Home Minister to be made a scape-goat, then I am willing to oblige them for that. Who did not want them to succeed ? They should have carried on the Government. The rest of the five-year-period was at their disposal. Can they say that we did not give them any co-operation in this matter ? I would like to deal with this point because this is very important and political motive has been attributed in this matter, and it has been stated that it is only for some political motives and because we wanted to bring in a Congress Government there that this has happened. Which Congressman opposed Shri Charan Singh ? May I ask my hon. friend ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : How could the Congressmen have opposed ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I know it from the evidence that I have; I know that some of the leaders met me and said that I was not showing any appreciation of the work that Shri Charan Singh did. Not at all. We have all appreciation for the work that Shri Charan Singh may have done. But the tragic fact remains that the only people who did not appreciate the work that was done by Shri Charan Singh was the SVD members themselves.

The Governor was in a very difficult position. Here is a Governor who has been very keen to avoid a mid-term election. He could have very well asked in the very first instance, if he was so keen, for mid-term elections; in the very first instance he could have made such a recommendation, and I am sure that in the circumstances prevailing then this House would very easily have accepted that. He had said it in so many words that he wanted to avoid mid-term elections, and he has given his reasons, administrative reasons and political reasons, and he had been reluctant to have President's rule. But even such a man ultimately was forced reluctantly to to come to the conclusion that mid-term election was the only solution.

Again, I would like to point out that in his second report he has said that he started with that hope but unfortunately that his hopes had been belied.

I would certainly like to keep something for reply, but there are some points which possibly might be made on the other side again, and which I would like to mention.

I would like to mention one point which Shri A. B. VAJPAYEE has mentioned. He has referred to the proceedings of the Constituent Assembly, and he had quoted from Dr. Kunzru's speech and also the reply by Dr. Ambedkar. I can tell him that I have read that debate very carefully, not once but many times because that gives us the mind of the Constituent Assemby which drafted the Constitution. As regards what Dr. Ambedkar said, I entirely agree with him. The idea was that no government was to be taken over under this particular article either for misrule or for good government. That was not the position here.

Here there was no people's Government unfortunately. This taking over process is not for misrule or good rule ; it is a process for no rule at all. There was no possibility of providing a people's government there, a government which is based

on the fundamental principle of stable majority in the House. What is the use of quoting from here and there ? What is, really speaking, the situation contemplated under the Constitution ? What the exact purpose is for which these articles are intended has to be gone into.

I have no doubt that the Governor acted correctly, he was actuated by patriotic feelings of providing a stable government to UP.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Question.

SHRI Y. B. CHAVAN : And what has he done ? He has not asked the Congress Party to form a government.

AN HON. MEMBER : They could not.

SHRI Y. B. CHAVAN : Many times I have seen hon. Members opposite staning and throwing challenges to us, when it was a question of Bengal, when it was a question of Punjab. They asked "why not go to the people and take their verdict? We are ready for it." I hope when they threw these challenges, they were confident of the people's support in advance.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : That does not give you a right to murder democracy.

SHRI Y. B. CHAVAN : Your idea of democracy is rather a strange idea. When it is run according to your ideas, it is democracy ; when it is done according to the Constitutiou, it is murder of democracy ? This is unfortunate.

The point is very clear. The situation was so uncertain that I think it is a very good thing that we go back to the people. We have reached a stage now when all of us have learnt in the course of the history of the last one year that is the only solution. There were coalitions before the elections ; there were coalitions after the elections. We have seen how coalitions have functioned. Then came the phenomenon of minority governments Now we have reached the stage of mid-term elections.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Punjab.

SHRI Y. B. CHAVAN : That seems to be the effective answer to all these troubles. I personally feel that possibly what is happening in UP would provide a solution not only for UP but perhaps to all the constitutional elements and troubles outside it also.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Resolution moved :

> "That this House approves the Proclamation issued by the President on the 15th April 1968, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Uttar Pradesh, varying the earlier Proclamation issued on the 25th February 1968".

Now both the Motion as well as the Resolution are before the House.

SHRI SEZHIYAN (Kumbakoniam) ; I rise to support the Motion moved by Shri Vajpayee and oppose the Resolution moved by the Home Minister.

At the outset, I want to erase a wrong impression created in the press and among the public outside regarding the attitude of the DMK in regard to the walk-out staged by Shri Vajpayee and the others the other day when Proclamation was laid on the Table. Actually we of the DMK participated in that walk-out. But one of our Members had to speak on the Demands which were coming up immediatly. The walk-out happened at 12.33 and the discussion stated at 12.34. So after walking out, he came back immediately to speak. This was interpreted as our not participating in the walk-out. This is a wrong impression. Therefore, before I proceed I want to correct that impression.

I want to discuss the more basic issues before the country, and not only before the government in regard to democratic procedure and parliamentary processes in the country. Again and again, this question has come before the public and before Parliament : the role and the functions of the Governor, how for he can and should take decisions to dismiss a Ministry or to dissolve an Assembly or to recommend mid-term elections. I think this cannot be

[Shri Sezhiyan]

done according to the whims and fancies of the Governor, whatever may be the special provisions in the Constitution.

This question on the power of the Governor has been posed from time to time, from the time when after general elections in 1965 in Kerala, the Assembly was not at all allowed to meet and the elected representatives were not allowed to take a decision.

You, Sir, sitting in the Chair are an impersonal person. But here I would quite no less a person than Shri R. D. Khadilkar when he spoke on March 24, 1965, when the question of Kerala was discussed here. He raised a very pertinent question to which not only this Minister but even his predecessors have not yet given a reply.

SHRI D. C. SHARMA (Gurdaspur) : He has changed his views.

SHRI SEZHIYAN : He has defeated ? I do not think so.

I shall now quote what Shri Khadilkar had said on that occasion. He said :

> "There is another point of propriety to which I have given deep thought. I want to ask constitutional lawyers one question : whose judgement is to be final in this matter . the judgement of the Governor or that of the representatives of the people ? That is the conflict. Let the elected representatives meet and decide. To take a decision on the basis of personal conversations is against the grain, against the spirit of our Constitution as I have understood."

This is what Shri Khadilkar had said on that occasion. I want to invite your attention to what he had said then.

Therefore, the basic question is, who is to decide ; whether the Ministry has got the majority or not, whether the Ministry is going to be stable or not, whether the Ministry should function or not has to be decided by the House. The decision is to be given not by the speaker, nor by the Governor in his private chambers, not in the Raj Bhavan, not by having private or personal converstations, not by evesdropping, not by going incognito as King Vikramaditya did in the olden days. We are functioning in a democracy under a constitution. Therefore, when they take a decision, a decision about the strength of a Ministry, it should be tested in the House.

I have read very carefully the two reports given by the Governor, and I find that they bristle with contradictions, inaccuracies and vagaries. Just now the Home Minister quoted both the leaders—the Congress leader as well as Mr. Charan Singh,—in respect of the mid-term poll. It has been given at page 3 of the Governor's report dated 10th April.

The Governor has quoted Mr. Charan Singh as : "that while recommending dissolution of the Assembly, that a mid-term election, should be held in order to ascertain the wishes of the people in regard to the political party or parties which they would, in the circumstances like to run a stable Government for them".

I went through the earlier report and find that certain other things said by Mr. Charan Singh have been conveniently omitted. The Governor has also conceded it in the first report, but he has not put it in the second reports. Probably it was convenient then and inconvenient now. The Governor has said in his letter dated 22nd February, 1968 :

> "After turning the matter over very carefully in my mind, I have come to the conclusion that such a qualified conditional and secondary recommendation cannot be treated as a recommendation for dissolution under article 174(2)(b).'i

What had Mr. Charan Singh said ? He had said :

> "It is obvious that it will be necessary to have another Chief Minister and a Council of Ministers. In as much as the Samyuk Vidhayak Dal enjoys a majority in the Legislative Assembly, you might, perhaps, like to send for its new leader with a view to forming the Government."

How for this has been fulfilled, I want to raise this question.

Now, in regard to majority, it has always been that the party or group of parties which have the majority should be

called to form the Ministry. But now, new definitions, new adjectives, are being brought in for the word 'majority'. In his letter the Governor has introduced a new phenomenon, "stable majority" ; not only a majority but a stable majority. There seem to be different kinds of majorities. In the letter dated 10th April, in two places, the word 'stable' has been underlined to give it a new meaning and a new impression. I want to know what they mean by a 'stable' majority. Is it an absolute term or has it got any proportions, whether five or 10 per cent more should be required to qualify for a 'stable' majority ? He has not given anything. But in the earlier letter, dated the 22nd February, he went into the meaning of the words "stable majority", and said :

> "But in order to give stable Government to the State, it is necessary that the majority should be fairly substantial so that a small movement of members from one side to the other...may not deprive the Government of its majority in the Legislative Assembly."

Therefore, this stability or the stable majority has not been defined here clearly. Only thing indicated was that the majority should be substantial. I want to apply this test of stable majority where the Congress Governments have been ushered in and see whether they have scrupulously followed it. In Rajasthan. what has happened ? After the election, out of 183 members, 93 members were in the opposition brought to Delhi and presented before the president. Was that accepted ? No, because out of them the Inpependent members were not taken into account. All right. There the Assembly was not dissolved. It was simply kept suspended till Mr. Sukhadia was able to form a ministry. After that how many members did he have ? He had only 92 or 93 members out of 183, if the Congress has 93 and the opposition 90, is it a stable or comfortable majority ? Why was this rule of 'stable majority' not applied in Rajasthan ? It was not applied because it was in the way to have a Congress ministry.

Even in this House, what is the majority of the Congress ? Out of 523 members, they have got 282. If 21 members. i.e. just 4 per cent, defect from that side, the ministry will fall. Is it a comfortable or substantial majority ? Will the ministry here go back to the people and ask them to give their verdict ? Even taking a broader view, they got only 42 per cent of the votes of the people. It is not at all a majority. Therefore, this definitition of "stable majority" is only for the convenience of the occasion and there is no basic factor in it.

Then it is said that it should be a majority not only now but in future also ! Only an astrologer can say what is going to happen later. In Rajasthan, out of 93 members, if 3 had defeated from the Congress, the ministry would have fallen. Even an ordinary man could tell that and no astrologer is required for that. I do not know whether Mr. Chavan has got a royal astrologer as so many other ministers have. Now Governors themselves have become astrologers predicting whether it will be a stable majority or not. Therefore, the new measure of stable majority should not be the criterion for making a personal assessment by the Governor.

Now, he has introduced another peculier thing. The Governor has said, the majority in U.P. is not united. It is a new phenomenon which has entered into our politics. He says :

> "The uncertainties in the SVD functioning as a united body are too glaring to be ignored....The Samyukta Socialist Party and the Communist Party, though they are constituent of the Samyukta Vidhayak Dal, are not prepared to shoulder the burden of running the administration."

Let us apply this test of "united majority" to the Congress Governments. They say, SSP and Communist Party are not prepared to shoulder the burden. In West Bengal, after Mr. Ajoy Mukherjee's Government was unceremoniously dismissed, when Dr. P. C, Ghosh was installed as Chief Minister, did the Congress members shoulder the responsibility ? 130 members were in the Congress and 17 members in the P. C. Ghosh group. But still 17 member-group was asked to shoulder the responsibility and the Congress remained outside. The Congress only promised support, but refused to shoulder responsibility. Mr. Ramamurti and others were saying then that it is a Shikandi

[Shri Sezhiyan]

ministry and not a full-fledged minstry. Still, it was allowed to function. In Punjab after the fall of the Government, the Dal and Janta party, which had only 17 members, were asked to form the Government, whereas Congress with 44 members did not take part in the Government. Even the Jan Sangh did not take part in the formotion of the Government in Haryana. Therefore, parties not shouldering responsibility is not a new feature which has crept in U.P. alone. In 1965, when a Congress woman and a Congress man contested for Prime Ministership, out of 524 Congress members in both Houses, Mrs Gandhi got 355 votes and Mr Desai got 169 This too is not a unamimous majority, because 169 members inside the party opposed her.

If you take the view that it is not a united one, then the Congress Government should not have been allowed to function. Therefore, the "united" nature does not fit in neither for the Congress Government there nor for the Government at the Centre. There may be difference of views insiude the party or the roling group. One leader may go and another leader may be elected. If you go into the question of arrangement inside the party then many Congress Governments should have been sent home long long ago. The same thing happened in Madras and Kerala several times. In Madras it has happened under the aegis of Shri Kamaraj. Mr. Prakasan was unseated from the Chief Ministership and Mr. Omandeer Ramaswami Reddier was enthrned; then Shri Ramaswami Reddiar was sent home and Mr. Kumaraswami Raja brought in the same way Shri Rajagopalachari was sent home. That has not prevented the party from functioning. Shri Vajpayee said that the Chief Minister resigned but the party did not resign, the party was functioning there.

As I said, firstly, a new definition has been given to majority. They want a stable majority. Secondly, they want the majority to be united. Thirdly, they say that the majority must be unanimous. In the report dated 22nd February the Governor has said :

> "I find that Shri Charan Singh had been elected unanimously but it is not stated that the second leader has been elected unanimously. All that was said was that he had been elected without opposition."

He makes a subtle difference between 'unanimity' and 'without opposition'. He says that unless a leader is elected unanimously by his party he cannot function effectively. 'Unanimity' is a very dangerous thing because even in the Congress there has not been unanimity. I would like again to go back to 1965 and refer to the Prime Minister's election when two persons contested for it. It took place on 19th January. On 18th January an appeal was sent by Shri Morarji Desai to all the Congress Members of Parliament and therein he discussed the propriety of unanimity in elections. He says there :

> "Those who by virtue of their positions had a special responsibility to be above personal prejudices and animus seem to have decided that the search for unanimity should mean the elimination of all those whom they do not like. I have been greatly distressed to see how all kineds of unhealthy precedents are being set up in the effort to claim unanimous support for the choice of a few people who are in positions of authority."

Therefore, this word 'unanimity', 'unanimous' and others have been condemened by no less a person than the present Deputy Prime Minister.

SHRI Y. B. CHAVAN : Nobody had propounded this theory of unanimity in the past.

SHRI SHEO NARAIN : What does the hon. Member mean by 'unanimity' ?

SHRI SEZHIYAN : I would not have taken this question of unanimity. But the Governor in his report of 22nd February on page 4 has said that Shri Charan Singh was elected unanimously—he has underlined the word 'unanimously'—and the second leader was only elected without opposition—he has underlined the words 'without opposition.' He wanted to give some significance to these words. If the Home Minister had-not taken cognizance of it I would not have worried. But the proclamation has been done after receipt and study of this report.

When Shri Vajpayee opened his speech by saying that it is a murder of democracy it was resented by many hon. Members on the other side by asking how it could be called murder of democracy. I want to point out that Shri Morarji Desai used the same term in the last year's debate. At that time West Bengal was being discussed and the Deputy Prime Minister was presenting the Government's position when he said ;

> "He, therefore, only suggested to the Chief Minister that he has evidence to show that he has lost majority support and, therefore, it is better that he calls the Assembly in order to prove that he has the majority.....He, therefore, wanted to be sure about it and he suggested to the Chief Minister that a meeting of the Assembly should be called within seven days."

Then there was an interruption by Shri S. M. Banerjee and the Deputy Prime Minister stated :

> "The Chief Minister proposes to call a meeting on the 18th December, more than a month and a half after the suggestion is made to him.....For a month and a half how can the Governor keep the Chief Minister in in office? The Governor would not have been fit to remain in office if he had allowed such a murder of the Constitution at the hands of the Chief Minister."

The Chief Minister refused to convene the Assembly and the Deputy Prime Minister said that a murder of the Constitution has taken place. Now the reverse is happening. The Members want the Assembly to be convened but the Governor says that he is not going to allow it. Therefore, it is murder of democracy. At that time he justified the dismissal of the Chief Minister on the ground that he refused to have the Assembly convened within seven days. Here the Governor is refusing to arrange for the Assembly to function. So, applying the same formula, the Governor should have been dismissed, which the Government have not done.

I have said during the course of an earlier discussion that standards vary from State to State. In Rajasthan the Assembly was simply suspended tile the Congress Government was able to be formed. In Pondicherry the Assembly was suspended. In Haryana the Assembly was dissolved. In Punjab and West Bengal they adopted other methods. Therefore, I said at that time that different standards have been evolved for different States, dual standards. Now I have changed that view, because there has heen no standard at all. Only one standard has been set, whether the Congress Government can come to power or not. If the Congress cannot come in they say : Let us go to the people.

This raises a very serious question. I am not worried wheteer SVD eomes to power or the Congress comes to power ; it is immaterial. I am concerned with the question what should be the standard, what should be the criterion by which the Assembly can be dissolved and the elected representatives sent home. Should it be left to the whims and funcies of the Governor ? Or, as you have said, 'Sir,—I am sorry, as Shri Khadilkar has said—at that time, the Governor by a private conversation cannot alter the fate of the Government and the majority of the Ministry has to be tested in the Assembly. That is the crucial issue which they themselves may have to face, probably after the next general elections. Therefore, for the sake of the future of democracy, I think this question should be tackled to its full and logical end.

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ध्यान से माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी, का भाषण सुन रही थी, खासकर इस लिए कि अभी तक उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी—मेजर पार्टी उन्हीं की थी और साथ और छोटे भाई थे, जो मिलकर वहां पर सरकार चला रहे थे ।

उन्होंने बहुत सी बातें कहीं हैं, जिन में से दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस की मदद करने के लिए, एक पार्टिसन तरीके से, एसेम्बली डिज़ाल्व की गई है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सदस्यों को अपनी राय ज़ाहिर करने का मौका देने के लिए एसेम्बली की मीटिंग होनी चाहिए थी। जहां तक मैं समझ सकी हूं, इस काम से कांग्रेस

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

के साथ सरासर ज्यादती हुई है। कांग्रेस को इस समय राज्य चलाने का मौका मिलना चाहिए था। दस महीने से उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही थी उससे प्रान्त की हालत कैसी हुई? बड़ा भारी प्रान्त, 8 करोड़ की आबादी, सरकार बनी रंग-बिरंगी, रंगीली सरकार थी, सब की अलग-अलग पालिसी किसी की कुछ पालिसी और किसी की कुछ पालिसी जो कामन पालिसी बनाई गई, उस पर भी सब झगड़ते थे। एस० एस० पी० यह सवाल बार-बार उठा रही थी कि उस पर पाबन्दी होनी चाहिए। 10 महीने तक कैसे उत्तर प्रदेश में सरकार चली, मैं उस पर ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन इन झगड़ों का जो दृश्य सामने आया वह आपके सामने है वहां पर ला एण्ड अन्डर सिचएशन की आज क्या हालत है, उसे आप जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हालत है? एक-एक कागज एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने में कितनी दिक्कत आती है। वहां पर आम लोगों से पूछिये कि उन के सामने कितनी कठिनाइयां आयी हैं। सरकार का काम चौपट है।

लेकिन इन दस महीनों में कांग्रेस पार्टी चुपचाप बैठी रही। यह बात याद रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी करीब-करीब आधी पार्टी होते हुए भी वह वहां चुपचाप बैठी रही। उसने कोई परेशानी नहीं दिखाई, कोई अधीरपना नहीं दिखाया। और गड़बड़ी कहां से शुरू हुई चरण सिंह को उतारने के लिए कांग्रेस ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन आपस की फूट इतनी बढ़ती गई.....

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा): जिस ढंग से आप तथ्य रख रही हैं, वह उचित नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी: ऐसी बात न कहिए, आप लोग खुद ही नहीं चला पाये। मैं यह समझती हूं कि कुछ पार्टियां ऐसा सोचने भी लगीं कि अब चुनाव आने वाला है, इस लिए इस वक्त हम लोग खिसक जायें। क्योंकि यह बात सबके सामने जाहिर हो गई थी कि जो सरकार वहां पर बनी उस की गवर्नमेंट चलाने में दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी इस बात में थी कि हम अगले चुनाव की तैयारी कर लें। इनके मन में यह आया हुआ था कि मिड-टर्म इलेक्शन होने वाले हैं, उसकी तैयारी कर लें। गवर्नमेंट चलाने में इनकी बहुत लापरवाही रही और पार्टी को मजबूत करने के लिए जुटे रहे हैं।

आज आप लखनऊ शहर की सड़कों पर चले जाइये मैं अभी तीन-चार दिन पहले लखनऊ गई थी, सड़क पर चलते हुए जब मैं एक दुकान में घुसी तो जो बातें उन लोगों ने मुझसे कहीं, उन को सुन कर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उन लोगों में नहीं हूं, अपोजीशन पार्टी की गवर्नमेंट आने से अफसोस होता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कभी कोई पार्टी आती है और कभी कोई जाती है। कांग्रेस से 20 साल तक सरकारों को चलाया और अब बहुत से स्थानों पर अपोजीसन पार्टियों की सरकारें हैं, जहां-जहां गवर्नमेंटें बनीं, उन्होंने हमेशा सैन्ट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ़ शिकायत की कि हम से सौतेला व्यवहार किया गया है, पूरी मदद नहीं की गई है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने कहीं भी अपोजीशन पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की, बशर्ते कि वह गवर्नमेंट ठीक ढंग से चल रही हो। लेकिन जहां कोई गवर्नमेंट ही न चल रही हो आखिर सरकारें क्यों बनती हैं? वहां पर राज चलाने के लिए, अगर राज्य ही न चल रहा हो, जो मैन आब्जेक्ट है वह फुलफिल न हो रहा हो, तब क्या स्थिति हो? हम ने यू० पी० गवर्नमेंट को नहीं गिराया, वहां पर आपसी झगड़े की वजह से हालत ऐसी हो गई थी कि चरण सिंह, जो कि सख्त आदमी माने जाते थे, जो बड़े उत्साह से अपोजीशन में गये थे बड़े पुराने कांग्रेसी थे, जो सन 1937 से

लेकर अब तक हर कांग्रेस गवर्नमेंट में शामिल रहे हैं—पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से लेकर मिनिस्टर तक की हैसियत से—वह जब लपक कर, जोश से अपोज़ीशन में गये थे, वह भी हैरान हो गए और बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया।

उसके बाद अभी यहां पर यूनेनिमिटी का सवाल एक भाई ने उठाया वहां पर क्या नज़ारा देखा, जितनी मीटिंग्स हुई फार्मली या इनफार्मली कोई फैसला नहीं हुआ और आखिर में विकल जी को लीडर बनाया गया, लेकिन उसके दो ही घन्टे बाद एक और मीटिंग हो गई और गवर्नर के सामने दो नाम पेश हो गये, गवर्नर बेचारा हक्का-बक्का रह गया, किस को बुलाये, कोई कहता है कि यह लीडर है, कोई कहता है दूसरा लीडर है यूनेनिमिटी का सवाल कहां रहा, कौन लीडर हैं कुछ पता नहीं चलता। ऐसी हालत में उस ने कहा कि असेम्बली को सस्पेण्ड कर दो, इसमें उन्होंने कोई बेजा बात नहीं कही थी, ऐसी हालत में भी वह चाह रहे थे कि असेम्बली को खत्म न किया जाय, फिलहाल सस्पेण्ड रखा जाय ताकि थोड़े दिनों के बाद इनमें कुछ अक्ल आ जाय और सब ठीक-ठाक हो जाय और फिर गवर्नमेंट ठीक से चले। लेकिन फिर क्या हुआ? मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहती, मैं आज ही दौरे से वापिस आई हूँ, अगर मेरे पास थोड़ा समय होता तो मैं तारीखें दे सकती थी, 8 को उनकी मीटिंग हुई, 9 को मीटिंग हुई, 12 को हुई, 13 को हुई बीसियों दफा उनकी मीटिंग बुलाई गई, लेकिन पोस्टपोन होती रही आखिर में जाकर हरिश्चन्द्र सिंह को, जिनको हम तो सात साल यू० पी० में रह कर आये हैं, उनका परिचय नहीं रखते हैं, इतने प्रौमिनेन्ट आदमी वह हैं, उनको नेता बनाया गया। उसके बाद दोनों पार्टियां क्लेम करने लगीं कि हमारे पास मेजोरिटी है। वह कहते हैं कि हमारे पास 229 सदस्य हैं और गुप्ताजी कहते हैं कि हमारे पास 225 सदस्य हैं 29 और 25 का फर्क है—इसका मतलब है कि ज़रूर कुछ मेम्बरों का नाम दोनों की लिस्टों में है और इस तरह से वहां पर कोई क्लीयर पोज़ीशन नहीं बन सकी।

एक दूसरी बात जिस पर गौर करना चाहिये वह यह है कि आज कांग्रेस पार्टी वहां पर एक है, उस के सब मेम्बर एक साथ हैं, वहां पर एस० बी० डी० जैसा आज चरण सिंह नेता हैं या हरिश्चन्द्र सिंह नेता हैं ऐसा सवाल नहीं है, गुप्ता जी उनके लीडर हैं, सर्व सम्पति से नेता हैं।

श्री अर्जुन सिंह भदोरिया : फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं पार्लियामेंट में चुनकर आई हूँ, इस लिए आपका सवाल गलत है।

अब जब वहां पर हरिश्चन्द्र सिंह को चुना गया तो अलग-अलग पार्टियों ने क्या-क्या कहा, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। एस० एस० पी० सेन्ट्रल पार्टी ने जब कहा कि तुम इस में मत रहो, तो उन के आधे मेम्बर कहते हैं कि हम रहेंगे। और आधे कहते हैं नहीं रहेंगे। जो नज़ारा एस० एस० पी० का सामने आया वह आपको मालूम है। वह पार्टी अगर आज सपोर्ट करेगी तो कल अपनी सपोर्ट को हटा लेगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। पी० एस० पी० की हालत क्या है वह भी आपको मालूम है। उन की अन्दरूनी हालत यह है कि त्रिलोकी सिंह जैसे पुराने आदमी उसमें से निकल आये हैं और निकल कर अभी वह फिलहाल एक मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें बाकी पी० एस० पी० वालों को दावत देने वाले हैं कि आप सब भी हमारे साथ आयें, क्योंकि हमारे साथ आकर शायद कुछ अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ने जिसके वहां पर शायद 5 मेम्बर हैं, एलान किया कि जहां जनसंघ गवर्नमेंट फौर्म करता है, हम उनके साथ गवर्नमेंट फौर्म नहीं करेंगे। एक और नई पार्टी वहां बनी – कृषक विधायक दल, उस ने भी पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि हमें नहीं

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

मालूम कि एस० वी० डी० वहां कोई स्टेबिल गवर्नमेंट फौर्म कर सकेगी। स्वतंत्र पार्टी की भी इसी तरह की हालत है। ऐसी हालत में कौन कह सकता है कि गवर्नर के सामने कोई क्लियर पोजीशन थी कि फलानी पार्टी मेजोरिटी में है, उनको बुलाया जाय। हां यह बात सही है कि अगर किसी को गवर्नमेंट बनाने के लिए बुलाना चाहिये था, तो गुप्ता जी को बुलाना चाहिये था, कांग्रेस पार्टी को बुलाना चाहिये था, क्योंकि पिछले 10 महीनों में यह पार्टी एक साथ जम कर बैठी रही, उस का एक भी आदमी बाहर नहीं निकला। जैसे एक टोकरी में जिन्दा मछलियों को रख दिया जाये तो वे फुदकती रहती हैं, वह हालत कांग्रेस पार्टी की नहीं थी।

मैं यह समझती हूं कि गवर्नर ने कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है जो उस ने कांग्रेस पार्टी को मिनिस्ट्री फौर्म करने के लिए नहीं बुलाया। मैं आपके सामने इसके संबंध में एक कांस्टीचूशनल रेफ़ेन्स दे रही हूं मैं जैनिग्ज़ से आपको कोट कर रही हूं अगर कोई गवर्नमेंट अन्दरूनी बिकरिंग या झगड़े के कारण गवर्नमेंट नहीं चला सकती है तो अपोजीशन लीडर को बुलाना चाहिये। अगर इस कानून को हम मानें, तो आज आप को गुप्ता जी को बुलाना चाहिये था, उनको सरकार बनाने का मौका देना चाहिए था। उसके बाद वह हाउस में आते और अगर हाउस में उनकी मेजोरिटी नहीं थी तो उसका फैसला हो जाता और फिर पब्लिक को मौका मिलता चुनाव के जरिये से अपनी राय देने का।

वाजपेयी जी ने कहा कि पब्लिक को मौका देना चाहिये था अगर पब्लिक को ही मौका देने का सवाल है, तो फिर आप एतराज क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है, उसमें पब्लिक को राय जाहिर करने का ही मौका दिया गया है। इससे बड़ा राय जाहिर करने का तरीका और क्या हो सकता है, असेम्बली के फ्लोर पर राय जाहिर करने के बजाय, इलेक्टोरेट अपनी राय दें? इलेक्टोरेट्स जो फैसला करेंगे, उसके बाद जिसकी किस्मत में बहुमत होगा, वह राज्य को चलाएगा।

मैं समझती हूं कि इन परिस्थितियों में गवर्नर ने गलती जरूर की है। उसकी गलती यह है कि उस ने अपोजीशन के साथ बड़ा भारी पक्षपात किया है। हमारी राय में इस वक्त कांग्रेस का हक था— कांस्टीचुशनली, फैक्चूअली और अदरवाइज उनको गवर्नमेंट चलाने का मौका देना चाहिये था, अगर उनसे नहीं चलती तो फिर मिडटर्म इलेक्शन होता।

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : पब्लिक तो पहले ही फैसला कर चुकी है। तुमको 40 फीसदी वोट मिले हैं, पब्लिक कहां तुम्हारे साथ है? आप पब्लिक की बात को कहां मानते हैं?

15.00 hrs.

SHRI S. A. DANGE (Bombay Central South): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I want to begin my understanding of the question with the same words with which the Home Minister began. That is, he says, let us look at the history of the question. Let us look at the history of the question. What is the question? The question that was formulated, after saying so, was formulated by him in a very narrow way, because he immediately went into the details only of the U. P. question. Only later on, as the Home Minister has also a general outlook of philosophy, he went into dialectics and said, 'There is now a qualitative change in the situation.' But then the question is: which situation? There again he limited himself to U.P. But then he, like a true philosopher that he is in his seat, or claims to be at least one—I do not want to contest the claim—at the end of it said, "We have gone through several experiments and we have now come to this conclusion." What are those experiments? He said, Bengal experiment, Haryana experiment and so many experiments. Now, he says, having tried all these things, they

have come to the conclusion that election is the best. Have I a quarrel with mid-term election ? No, Sir. I do not challenge his conclusions or his actions, simply on the basis of the question as to why he has ordered a mid-term election. No. Public opinion has to be tested by elections and if an Assembly does not serve the purpose for which it is elected, then its existence has also to be tested by elections. We have no objection to that proposition. That is why, in Bengal, we did stand for mid-term elections. When, in principle, you have to put to me the question, 'Am I against mid-term elections ?', I would say, 'No, I am not'. But the question is : how do you arrive at the conclusion that the mid-term election is necessary ? That is my point. My proposition is that, in arriving at such a conclusion, the ruling Party does not apply common norms of democracy. Therefore, what is the history of the question ? The history of the question is the history of the application of understanding of democracy to the situation in India by the ruling Party. What is the history of the question? The history of the question is: how do they wish parliamentary democracy to function after the year 1966. Why do I put it that why ? It is because they enjoyed power continuously unchallenged till 1966. Then the norms of democracy, as interpreted by the Constitution, were not, more or less, in question except on questions of Fundamental Rights and Directive Principles and so on. But the functioning of Assemblies, formation of Ministries, formation of Governments and the question of powers of Governors were not so solidly questioned before 1966 as they began to be questioned after 1966. Therefore, all this confusion has arisen.

What I want to state here is this that it is a common problem for all of us. Just now I am not speaking from any partisan position. For, it is a common problem before all of us—how we apply the norms of democracy in elections, in functioning of Assemblies, in formation of Governments, in the dismissal of Governments and in going back again to the test of democracy by a mid-term vote. This is the question. If you look at that question and if the ruling Party or their spokesman, the Home Minister, has at least come to some norms of understanding, then we shall be very glad. But my doubt is that they have not. Maybe, they have come, by some other motives, to that conclusion. I am not going into the motives.

Now, let us see what the situation is, taking history as it is. After the last general elections, the Congress lost the monopoly of power in several States. What should have been the natural reaction in terms of democracy ? The natural reaction should be that those who have been elected by a majority or could come together to form a majority should be allowed to form the government, because coalition is not against democracy. The formation of democratic coalition governments fits in with the process of democracy everywhere in the world and as this Constitution is based upon precedents in many other countries, we shall have no quarrel with it, and we need not quarrel about it.

A single party having a majority came into power in Madras. But except for that State, in the other States, a programme was evolved on which several parties agreed and a democratic coalition was formed, and the programme and the Government came into existence. That programme was different from the Congress programme. That programme was a programme which was against landlordism basically. That programme was a programme which basically wanted to challenge the right of monopoly. That programme wanted basically to curtail the development of capitalism, which, though in principle or in words may have been accepted by the Congress, was not being given effect to. Therefore, there was a feeling of unrest, the highest unrest being in Kerala, in Bengal and even in Bihar and so on. So, the unrest, the confusion or the instability in the minds of the ruling party at the Centre came into existence not because there were coalitions or not because their party alone lost the government but because a new programme with a new government challenging the established rights and privileges of the ruling class which had failed to develop this country forward socially was emerging. That was the picture after the elections of 1967.

The SVD Government may have had their own quarrels. They may have had their own differences. They may have had their own factions or shortcomings. Let

[Shri S. A. Dange]

us not start comparing the shortcomings of the SVD with those of the Congress. The hon. ex-Chief Minister of UP who spoke should have been the last person to discuss our quarrels, when in her own party two factions were tearing her to pieces. She has got the courage to describe.....

SHRI SHEO NARAIN : We are united here. I shall reply to him afterwards. (*Interruptions*)

SHRI S. A. DANGE : Let him have a sense of humour. Some people do not understand having a little bit of humour in between.

I was very glad that she was very humorous and compared SVD to the case of fish when being friend in the pan, jumping into the fire. But in her own government there were only three fishes, and even they could not be fried properly and eaten ; one fish belonged to one faction, another fish belonged to another faction and the centre fish was jumping all alone. So, let us not please discuss this cookery business, though she may be a good cook ; I do not know ; of course, that is subject to the opinion of Shri J. B. Kripalani.

Now, the point is this. This programme came into existence and that really was the source of questioning the stability of governments. The stability was not of a majority of votes ; the stability was not of the given Ministry ; the "stability" that was built up for the last fifteen years against the people was in question. That is the history of the question. We challenged that stability in Bengal. We are proud of that ; in spite of our quarrels, in spite of our mistakes, one thing we did was to challenge the power of the employers and the landlords ; we may have suffered for it ; we have paid the price, and we are going to pay it again.

What is the stable government that they are after ? That is the history of the question. Is the government stable when the President rules with Communal riots breaking out in Allahabad ? Is the government stable when the Governor rules with all sorts of things breaking out ? What is the concept of stability on which the Home Minister is testing all these things ? There is, perhaps, no such term as 'stable government' in the Constitution ; I do not know because I am not an expert. There is no such term as 'stable majority' in the Constitution ; again, I do not know because I am not an expert. The only phrase which occurs is 'Government according to the provisions of the Constitution'.

The provisions of the Constitution are sufficiently democratic, if there were a democratic party in power to put them into practice. Fundamental rights are democratic. Directive principles of state policy are democratic. Economic power shall not concentrate in the hands of a few monopoly houses—this is a fundamental element in the directive principles of state policy.

SHRI R. D. BHARDARE (Bombay Central) : That is his dialect.

SHRI S. A. DANGE : Not mine, it is provided there. Let me remind my friend who is a constitutional lawyer also.

Concentration of economic power to the detriment of the community is not permitted. Has it not concentrated ? They have admitted it. They were good enough to appoint a Commission to probe into it.

We started with challenging that with our new programmes. We are inexperienced, no doubt, in the art of government. May be we formed coalitions in which all of them may not be very firm on that. But at least one credit they have to give us—that we were absolutely insistent on translating the democratic rights given in the Constitution into practice and developing the economy in a direction in which, I am sorry to say, the other side and failed to develop. I do not say that they have not developed the economy. I am saying, in the direction envisaged by the democratic content of the Constitution. That they have not done. Hence started the cry of instability.

Otherwise in these States or even here, which is the most stable thing in the Government ? Is it the members on the Congress Benches opposite ? No. They are not the most stable part in the Government. So if their inner questions were to become the standard for judging our stability, then all those signatures which some Congress MPs send to their leader-

ship challenging why the 10-point programme wa not being followed—can that be used by the President to question whether they have a majority and say that they have lost it ? So if the SVD parties among themselves declare that such and such group had not agreed to the programme, or such and such group had not agreed to do a certain thing, that cannot be a matter of which cognisance can be taken by the Governor—just as the signatures of Congress MPs cannot be a matter which can be taken cognisance of by the President to challenge their majority.

So they are applying double standards. Therefore, what is stability ? They are not stable ? Stability, in the present bourgeois system rests on the invisible, irremovable, permanent bureaucracy. That is the stable element in the system. Chief Ministers come and go. Even Prime Ministers come and go. Between elections, there is a vacuum. Even the Governor does not know what is what. It is the one immutable element in the system which lays down policies, gets signatures and executes them. Sometimes Ministers do not know what they have signed.

AN HON. MEMBER : Governors do not know.

SHRI S. A. DANGE : That is the stable thing. So what is the use of asking us : 'Can you provide a stable government ?' I will say, 'Oh, yes, we will provide a stable government. Why do you ask us ? Did you not try to provide a most stable government on the basis of 18 votes in Bihar of the Mandal Ministry ?'

And what a wonderful programme that gentleman gave to his party and Bihar ? 'Anybody who joins my party will be made a Minister'. A simple programme of economic development of the person concerned ! And he gathered 39 Ministers. At that time, where were these standards of stability morality, provisions of the Constitution and those principles which they are hurling at us and also checking up whether Shri Charan Singh was supported by somebody or not ?

So I will be very glad if they, henceforward, agree that they will not support minority governments. Then let them dismiss the Punjab Ministry first before challenging us over our internal differences. At least our elected leader went to the Governor and said 'I have 229 votes with me'. The Governor asked Shri C. B. Gupta whether he could produce something more. According to the Governor, our 229 was unstable. The Congress is 198.

18 are doubtful. Then the largest single party nearest to the majority party should have been called. I am for that. I have no objection to the Governor calling the Congress party; with 198, when we have failed, you are the largest party nearest to majority, not just like Mandal. Please remember that. And then let him try and then attract those 18 who said "We are with those who form the Governmcnt." So, there were 198 on your side and neutrals on the other, and you could have done it. Why at that stage did you desert the principle of formation of the Government with a majority support and providing a stable government ? Because at that stage you were confronted with your own inner quarrels in regard to C. B. Gupta and Tripathi—I do not know those names, and the leader of my party there is not here. (*Interruption*) Indrajit Gupta is not yet on your side. Why did they not do it ? Why suddenly take up the principle of sovereignty of the people, poll and taking votes and so on ? Because those two Congress factions were not useful to certain people ; their leadership was not useful. Therefore, again here, you are taking resources to election, not because you believe in the people's vote, not because you believe in the fundamental norms of democracy but because you could not resolve the position because of your own quarrels.

Therefore, I challenge your resolution. I am not going into the niceties of the things. But have you followed the fundamental principle ? My suggestion, therefore, would be, please make a declaration that you shall never support a minority government and not allow a minority government to function. How is a minority government a reflection of popular opinion ? May I know ? And you are doing it : Why do you do it ? Just because that minority group serves your policy you allow it. And where our minority group does not serve your policy, you disallow it. This was the point, and I have every right to say that the SVD even with a

[Shri S. A. Dange]

minority could and should have beed allowed to form the government in Uttar Pradesh. My programme clashes against your programme, because you want to have stability on the basis of a reactionary programme, that is why your definition of stability is not a democratic definition. It is not a definition in terms of the Constitution.

Now, to come to the conclusion, if you really want to evolve democratic norms in the country, agree that minority governments will not be supported and will not be allowed to function. Secondly, the test of a majority and a minority is not in the house of the Governor but on the floor of the Assembly or Parliament. It is a fundamental principle. You must not to go by the subjective opinion of the Governor, because, here, he has said, "I do not know if he has a majority". How can he know by just calling Shri C. B. Gupta, this man and that man ; he called this splinter group and that splinter group and then came to the conclusion. I do not know. We do not know whether he based his knowledge on the philosophy of Sankaracharya and his dialectics. He said there is no party, no government, no parabrahma; everything is zero, *shunyam*. Therefore, in a *shunyam*, who should step in ? The Home Minister. In that *shunyam*, who should step in ? The President. What comes out of it is some incomprehensible stability run by a bureaucracy which cannot prevent even communal riots in Allahabad. When we were in West Bengal, our Ministers and leaders went out in the streets and stopped the communal riots. (*Interruption*). You should do it. Please do it. You cannot stop the murder of a Harijan boy after 20 years of swearing by Gandhiji's untouchability. Do not talk about our party and our principles and all that.

So, Sir, what I am saying is, let us come to some norms of democracy. I am only anxious about that. No minority government, and no minority support should be there. Thirdly, no mincompoop, why is not a member of the Assembly, should be chosen and be allowed to remain for six months as Chief Minister. What is this kind of democracy, may I know, where a man who has not been elected, not even tested according to public opinion, can sit in the Assembly ? He may be in Parliament, I do not know.

SHRI Y. B. CHAVAN : He was an SVD Minister first.

SHRI S. A. DANGE : If he was in the SVD first, did you ask for a vote to test its support ? If you agree that you will be in difficulty.

SHRI Y. B. CHAVAN : I am not agreeing. You said, we made him minister. We did not make him minister. It was SVD who kept him as minister for 6 months.

SHRI S. A. DANGE : If the SVD does it, it is wrong. I am not concerned with who does it. I am trying to establish certain norms of democracy. If we have violated them, please censure us. Let him who is innocent and not a sinner cast the first stone, as somebody said. Nobody who is not an elected member of Lok Sabha should be allowed to become Prime Minister and nobody who is not an elected member of the Assembly should be allowed to become Chief Minister. You are already discussing the problem of defections. What is the value and plade of people who change their places, desert their parties and join other parties ? That is a problem which should be discussed. I am only concerned with these questions of democracy being raised and solved. Judged from all these angles, your action in UP is not justified. The majority should have been ascertained by the Governor by calling the leader who was elected and who claimed he had a majority. Call the Assembly and if he has no majority, topple that Government. But your toppling from outside is not a democratic behaviour and I am opposed to this kind of behaviour or functioning which you have accepted.

I do not accept verification of majoriyt by a parade of the members whether before the President or before the Governor. It is below the dignity of an elected member to go before the Governor or President and say, "Please, Sir, record me as belonging to this or that party". It militates against my conception of democracy. Who is the Governor who is to verify me ? "मामेव

वृणीत, मामेव वृणीत" as all those gods paraded before that mythological figure and she could not decide what it was. Now, after parading before the Governor, what is the guarantee that I will not desert that party and on my way back join some other party ? Therefore, I say that the test should be on the floor of the Assembly.

If you want to lay down norms of democracy, let us all sit down—the Congress and all the opposition parties—and let us evolve those norms and follow them. But when it suits you in one way, you observe one norm. When it suits you in another way, you observe another norm. Should it not be called dishonest tactics and wangling things to get your programme through and not the SVD's ? You may say, we quarrel among ourselves. Everybody knows that we and the Jan Sangh or we and the Swatantra quarrel. But that is not to be taken note of by the Governor. Whether they do or do not quarrel on the Assembly, floor, that is the only test.

In conclusion, I say that the Congress party has not behaved according to norms of democracy. In the last one year, after it was jolted out of power, it has lost its balance and deserted every principle of democracy with the only aim of putting itself in power, only to save the classes outside—the monopolists and landlords—whom we challenge. That is my accusation. You have deserted the provisions of the Constitution. You are blinded by the idea that you must somehow or other preserve the power of the monopolists and landlords when we challenge and preserve the power of bureaucracy, even if they hit at you. If you say you are the guardian of democracy, please sit down, enunciate the norms and observe them. Even if there something is not in the Constitution, nothing is barred.

If it is necessary the Constitution can be amended by mutual consent. So again I say, we have not murdered democracy. I do not say whether you have murdered democracy or not. I do not know, because you are applying different standards. So I am not going into the murder question at all. History will judge who was the murderer of whom, but at present my submission is that your behaviour in U. P. was wrong, your behaviour in Punjab was wrong, your behaviour in Haryana was wrong and your behaviour with regard to the remaining governments also is going to be wrong unless you change over to fundamental principles of democracy.

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस महत्वपूर्ण विषय की इस वक्त समीक्षा करना है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस को दो अंशों में विभाजित कर दिया जाये । सब से पहले तो यह निर्णय करना है कि वास्तव में क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी परिस्थिति थी कि विधान सभा भंग की जाय और राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाये तथा साथ ही साथ मध्यावधि चुनाव के भी आदेश दिये जायें, दूसरी बात यह कि यह जिम्मेदारी किस पार्टी की है । अभी श्री वाजपेयी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति वहां पैदा नहीं हुई थी और जो कुछ वहां पर हुआ है उस की सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी पर है । मेरा तर्क उन के बिल्कुल उल्टे है, उन से विपरीत है ।

अगर हम आज इस पृष्ठभूमि में देखेंगे तो उस से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है उस में न तो बहुमत कांग्रेस का है और न बहुमत संविद सरकार का है । ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल महोदय क्या कर सकते थे ?

एक माननीय सदस्य : यह कैसे कहा जा सकता है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : माननीय सदस्य को समय मिलेगा और वह अपना बहुमत वहां अवश्य दिखायें । मैं ने तो पहले ही कहा कि कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिस में किसी का स्पष्ट बहुमत नहीं है । तब राज्यपाल के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवा इस के कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाय और मध्यावधि चुनाव कराये जायें ।

मैं श्री वाजपेयी से कहना चाहती हूं कि एक वर्ष पहले चुनाव के बाद जब वहां पर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग हुई तब मैं उस में

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

मौजूद थी और उस में चौ० चरण सिंह ने श्री चन्द्रभानु गुप्त का समर्थन किया था और उन को अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया था। मैं पूछना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि दस दिन बाद उन्होंने अपनी राय बदल दी, जो उन के अपने थे वे पराये हो गये ? जिस कांग्रेस की सहायता से मंत्रि पद पर रह कर, जिस कांग्रेस की प्रतिष्ठा के नीचे रह कर, उन्होंने जनता से वोट मांगे, वही कांग्रेस की सरकार उन की पराई हो गई ? उस के बाद देखिये कि जिसने अपनी पार्टी को छोड़ा और दूसरी पार्टी बनाई वही जब चीफ मिनिस्टर की हैसियत में आता है तब जन संघ ने और दूसरी सात पार्टियों ने उसे अपना नेता बनाया, एक आदर्श बनाया और बड़े-बड़े वादे किये कि वह उस संविद सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करेंगे। क्या किया उस संविद सरकार ने ? उस ने साल भर में 31 दिन के लिये ही विधान सभा बुलाई। अगर उस को अपने लोगों पर विश्वास था, तो केवल एक महीने के लिये असेम्बली की बैठकें करने की क्या बात थी ? अगर उन को आपस में विश्वास था, अगर आपस में उन का कोई टकराव नहीं था, अगर उन के आपस में मतभेद नहीं थे, आपस में रुकावट नहीं थी, उन को एक दूसरे का डर नहीं था कि समय पर वह काम नहीं आयेंगे, तो क्या बात है कि साल भर तक सरकार रहती है और उस साल भर के अन्दर केवल एक महीने के लिए विधान सभा बुलाई जाए ?

बीच में जब वह लड़ते रहे, एक दूसरे पर लांछन लगाते रहे तब तीन दफे डरा कर, धमका कर, पुचकार कर के, श्री चरण सिंह ने अपना इस्तीफा दिया। तीन दफे तो दे दिया लेकिन चौथी दफे देने के पहले ही उन्होंने अपनी राय बदलने की चेष्टा की। कहां थी वह संविद सरकार ? एक कामन ऐग्रीड प्रोग्राम बना, लेकिन वह क्या था ? एस० एस० पी० उन से अलग हो गई, सारी पार्टीज उन से अलग हो गईं, पी० एस० पी० अलग हो गई। कहां गई वह संविद सरकार ? ऐसी स्थिति में जबकि वहां पर किसी का स्पष्ट बहुमत नहीं था जैसा कि राज्यपाल ने कहा, इसके सिवा क्या चारा था कि राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाए। स्टेबल गवर्नमेंट किस तरह से बन सकती है, उसका क्या आधार हो सकता है ? यही आधार हो सकता है कि उसका एक नेता हो, एक उसकी नीति हो, उस में एकता हो, उस में क्षमता हो, उसमें शक्ति हो, उस में सामर्थ्य हो। तभी वह सरकार चल सकती है। लेकिन संविद में नेता ही कहां था ? विकल जी को नेता बनाया गया लेकिन तीन घण्टे के बाद ही पांच पार्टियां कहने लगीं कि हम उसको नेता नहीं मानते हैं। तब हरिश्चन्द्र जी को नेता बनाया गया। इस पर रिपब्लिकन पार्टी और स्वतंत्र पार्टी के लोग अलग हो गए और कहने लगे कि वह हमारे नेता नहीं हैं।

संविद की एक ही नीति रही है 'कीप दी कांग्रेस आउट एट एनी कास्ट'। यही पालिसी रही है और वह भी विघटनकारी रही है। कोई कंस्ट्रक्टिव काम वह एक साल में नहीं कर सकी है। एक ही उसका ध्येय रहा है कि किसी भी तरह से गद्दी पर बनी रहे। अगर नेता नहीं, नीति नहीं, अगर शक्ति नहीं तो किस तरह से वह असैम्बली को फेस कर सकती थी। चैलेंज होने के बावजूद भी साल भर में केवल एक महीने के लिये असैम्बली की बैठकें हुईं। क्यों नहीं मांग होने पर असैम्बली की बैठक की गई और उस में बहुमत सिद्ध किया गया ? क्यों नहीं जब कभी चैलेंज दिया गया, उसको स्वीकार किया गया ?

आप देखें कि चौथी योजना लागू होने वाली है। वह बन रही हैं। लेकिन ऐसी सरकार, जो नेता विहीन हो, जो नीति विहीन हो, जो शक्ति विहीन हो क्या उस सरकार के पास सामर्थ्य हो सकती है कि वह उपलब्ध साधनों का

सदुपयोग कर सके या नए कर योजना को कार्यान्वित करने के लिये लगा सके ? क्या ऐसी सरकार जनता की सेवा कर सकती है ?

संविद सरकार का क्या हाल था ? यह तो एक खिचड़ी सरकार थी। एक खिचड़ी उसने पकाई, कोई जीरा ले गया, कोई नमक ले गया, कोई मिर्च ले गया। किसी ने भैरवी बजाई किसी ने केदारा बजाया, किसी ने दरबारी और किसी ने शंकरा बजाई। अलग-अलग दल, अलग-अलग राग। ताल भी एक नहीं था। किसी प्रकार से वे वहां पर एक हो कर सरकार में बैठ गये थे.....

एक माननीय सदस्य : बहुत बेचैन हो।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : एक तरफ तो यह हालत थी और दूसरी तरफ कांग्रेस की जो स्थिति थी वह भी कोई बहुत स्पष्ट नहीं थी। कांग्रेस एक मर्यादा के अन्दर रह कर, प्रतिष्ठा के आधार पर, ऊंचे लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर, कनवैंशंज के आधार पर कार्य करना चाहती थी और इन्हीं ऊंचे आदर्शों को सामने रख कर उस ने पद त्याग किया था। यह उस ने श्री चन्द्र भान गुप्त के नेतृत्व में, श्री कमला पति त्रिपाठी के नेतृत्व में किया था। जिस प्रकार से गुप्त जी ने उत्तर प्रदेश में आचरण किया है, वह एक अनुकरणीय मिसाल है और इस को स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

अभी जो स्थिति थी उसको आप देखें। कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत न होने के कारण और साथ ही साथ संविद का भी स्पष्ट बहुमत न होने के कारण राज्य पाल के पास और कोई चारा नहीं रह गया था और इसी लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा :

> "I want to satisfy myself about the respective case. I shall not favour anybody. I shall not do anything which would not satisfy the people."

अगर उन्होंने इस बात को लिखा तो इस के लिए उनकी तारीफ ही की जानी चाहिये। उन्होंने निष्पक्ष रूप से अपनी राय दी है। जैनिंग्ज़ के कथनानुसार वह चल चल सकते थे। जैनिंग्ज़ ने लिखा है :

> "In a situation where a Government resigns due to its internal dissension, the Crown consults the Leader of the Opposition first and only when he expresses his inability to form a Government does he consult others."

वहां पर यह परिस्थिति भी वह उत्पन्न कर सकते थे और कांग्रेस के नेता को बुला कर उन को गवर्नमेंट बनाने के लिए कह सकते थे। लेकिन उन्होंने सब बातों पर विचार कर के यही निष्कर्ष निकाला कि वहां ऐसी स्थिति नहीं है कि जिस में कांग्रेस का स्पष्ट बहुमत हो।

इस बात के लिए उन की और सराहना करनी होगी। उन्होंने कोशिश इस बात की की है कि डिफैकशंज़ की जो प्रथा चली है उस को एनकरेजमेंट न मिले। मुझे पता चला है कि अभी राज्य सभा का जो चुनाव हुआ था उस में 31 आदमियों को चार लाख रुपया खर्च कर के संविद से तोड़ कर राज्य सभा की सीट जीती गई है। रुपये के बल पर, चांदी के टुकड़ों के बल पर, जनता के चुने हुए लोग चाहे इधर के हों या उधर के हों, उन का अगर इस तरह से समर्थन लिया जाता है और राज्यपाल इस तरह के डिफैकशंज़ को रोकना चाहते हैं तो इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूं। मैं यह भी समझती हूं कि अगर असैम्बली में किसी दल को बहुमत सिद्ध करने का मौका दिया जाता तो इस में कोई दो राय नहीं हैं कि कुछ लोग इधर के इधर आ जाते और कांग्रेस का समर्थन करते। कांग्रेस ने हर तरह दिखा दिया है कि जो गलती आपसी झगड़े के उसने पिछली बार की है उस का पश्चाताप वह कर चुकी है। कांग्रेस दल अपनी शक्ति और ताकत का परिचय दे चुका है। जिस निर्भीकता और ईमानदारी से और अटल हो कर आज कांग्रेस दल

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

कार्य कर रहा है उस को देखते हुए कांग्रेस के डरने का कोई सवाल नहीं है।

मैं समझती हूँ कि केन्द्रीय सरकार की भी हमें तारीफ करनी होगी कि उस में राज्यपाल महोदय ने जो निष्पक्ष कार्य किया है उस में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया है और हस्तक्षेप न कर के उसने राज्यपाल को पूरी तरह से ईमानदारी से काम करने का मौका दिया है। मैं इस के साथ-साथ वाजपेयी जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जो स्थिति वहां आज बनी है उस स्थिति को लाने के लिए क्या कांग्रेस जिम्मेदार है। एक बड़े ही विवेकशील आदमी ने जो लिखा था उस में से केवल एक लाइन ही मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिस से स्पष्ट हो जाएगा कि जब ऐसी परिस्थिति होती है तो क्या करना चाहिये :

> "On such brittle ground of shifting sands even the angles would not dare to tread."

न इधर और न ही उधर, जब ऐसी परिस्थिति आए तो जनता जनार्दन के पास हमें जाना चाहिये जिस से हमें सारी ताकत आती है। जनता जनार्दन के पास जाकर हमें उस का वर्डिक्ट प्राप्त करना चाहिये। कौन बहुमत में आता है, किस को जनता बहुमत में भेजती है, इस को देखना चाहिये। मैं एक प्रश्न वाजपेयी जी से पूछने जा रही थी। डांगे साहब जा रहे हैं। उन से भी मैं एक निवेदन करना चाहूँगी। उन्होंने कुछ मौलिक प्रश्न उठाये हैं और उन से भी मैं प्रार्थना करूंगी कि वह मेरे प्रश्न का उत्तर दें। वाजपेयी जी ने जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ है उसके लिए कांग्रेस पर जिम्मेदारी थोपी है। मैं उन से पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में संविद की सरकार बनाने की जिम्मेदारी किस की रही है ? चरण सिंह जी को, जो कि एक डिफैक्टर थे, किस ने नेतृत्व प्रदान किया ? उनको नेतृत्व देने की जिम्मेदारी किस की रही है ? संविद सरकार की ही तो रही है। संविद सरकार में सब से बड़ा घटक, सब से बड़ा यूनिट कौन सा था ? जनसंघ ही तो था। संविद में जनसंघ का बहुमत होते हुए भी उस में यह सामर्थ्य नहीं थी, इतना साहस नहीं था, हिम्मत नहीं थी, क्षमता नहीं थी कि संविद का नेतृत्व यह सम्भालता, जन संघ अपना नेता संविद का बनाता। लेकिन एक डिफैक्टर को उन्होंने अपना नेता बनाया, उसके नेतृत्व के अधीन उन्होंने कार्य किया। उन्होंने ही आज कहा है कि हर एक यूनिट ने अवांछनीय कार्य किया था। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि जितने यूनिट थे उन में से कुछ तो देशद्रोही हैं। इन शब्दों का प्रयोग अगर किया जाता है तो कौन आदमी इन को स्वीकार कर सकता है...(इन्टरप्शंस)

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : बरेली में यह कहा है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : अगर चरण सिंह जी ने दोशद्रोही शब्द का प्रयोग नहीं किया और वह इस को कह दें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन अखबारों में यह चीज आई है और इसको मैंने स्वयं पढ़ा है। जनता के किसी भी प्रतिनिधि के लिए जब इस प्रकार का देशद्रोही शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस को कैसे स्वीकार कर सकता है ? लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आज उसी नेता, उसी लीडर की ये खुशामद करते फिर रहे हैं और कहते फिर रहे हैं कि आप ही हमारे नेता हो, आप ही हमारी नैय्या को जोकि डूब रही है, उबारें, मंझधार से बाहर निकालें।

फिर आप यह भी बतायें कि मध्यावधि चुनाव का सुझाव किस ने दिया था राज्यपाल को ? संविद सरकार के मंत्रिमंडल ने ही तो

दिया था। अब आप बताइये कि कांग्रेस उस में कहां से आती है ? अगर आप मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते हैं तो क्यों ऐसा सुझाव पहले दिया था। इस वास्ते मैं कहूँगी जो कुछ भी हुआ है उन्हीं के सुझाव पर हुआ है। मैं नहीं समझती हूँ कि अब क्रुद्ध होने की, रुष्ट होने की कोई बात है। कांग्रेस जनतन्त्र में विश्वास करती है। कांग्रेस जानती है कि जनता उस के आचरण को मानेंगी। जनता को कांग्रेस पर और कांग्रेस को जनता पर विश्वास है। कांग्रेस जानती है कि वह जो कुछ कहती है उस को करने का प्रयास करती है। यह बात अभी त्रिलोकी सिंह जी ने जो कुछ कहा है उस से भी सिद्ध हो जाती है। अठारह साल तक भटकते रहने के बाद आज इतने बड़े विवेकशील आदमी ने यह माना है कि देश में अगर कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी ही है—

श्री झारखंडे राय (घोसी) : डिफैक्टर को क्यों वैलकम किया जा रहा है ? क्या आप उन को डिफैक्टर नहीं मानती हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक डिफैकशंज का सम्बन्ध है, मैं एक बात कहना चाहती हूं। एक कमेटी बनी हुई है जो कि डिफैकशंज के मसले पर विचार कर रही है। मैं उस को एक सुझाव देना चाहती हूँ। जैसे वह सारी पार्टियों के बारे में विचार कर रही है उसको यह भी देखना होगा कि हमारे बीच में एक फ्लोटिंग एलेमेंट है जिस को आप चाहें तो इंडिपेंडेंट कह दें या कुछ भी कह दें, जो जनता के बीच में जब वोट मांगने जाता है तो स्वतन्त्र रूप से जाता है और पार्टियों के जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे होते हैं उन सब के खिलाफ वोट मांगता है और जब वे जीत कर आ जाते हैं तो कारण चाहे जो भी हों, कुछ दिन के बाद अपनी राय बदल लेते हैं और किसी न किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं और इस तरह के लोगों पर भी कुछ न कुछ अंकुश लगना चाहिये। अगर उन की आस्था बदल जाती है, अगर उन का विश्वास बदल जाता है और सिद्धान्तों के आधार पर वे किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं तो क्या उन को ऐसा करने से पहले जनता के सम्मुख जा कर फिर से दुबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहिये। पांच साल तक या तो वे स्वतन्त्र रूप से रहें या फिर इस के बारे में भी कमेटी विचार करे कि क्या किया जाना चाहिये। नहीं तो इन के कारण बैलेंस आफ पावर बदलता रहता है।

डांगे साहब से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि वह तो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। उन्होंने पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश का मिलान किया है। पश्चिमी बंगाल में तो घेरावों के कारण और जो उस से प्रतिक्रिया फैली उस के कारण प्रशासन ठप्प हुआ, सारे उद्योग धन्धे समाप्त हुए और वे चाहते हैं कि वही चीज़ हम उत्तर प्रदेश में करें। यह कहां तक लोकतन्त्र के अनुकूल है इस को वह देखें।

SHRI A. N. MULLA (Lucknow) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have a great admiration for Shri Atal Bihari Vajpayee. But I feel that the motion which he has presented today is rather misconceived.

The questions which arise in this debate can be approached from three angles. There is the human angle ; there is the constitutional angle and there is the political angle. I will not try to give any opinion as far as the political angle is concerned. I think, as I am an Independent Member of the House and I am not connected with any political party, I am not in a position to appreciate this issue from any political angle. I would, therefore, confine my observation to an approach made from the constitutional angle and the human angle.

Before doing so, I will to place some facts before the House which, as a resident of Lucknow, and as a resident of Uttar Pradesh, are within my own personal knowledge. I happened to be in Lucknow in the beginning of last month. At that time, the Assembly was already suspended. I wanted to find out the reactions of the

[Shri A. N. Mulla]

people on the suspension of the Assembly. I had my contacts. People came to me. I am not exaggerating, when I am saying that the people (it may be that the people whom I met were not the true representatives of the people) most of them, heaved a sigh of relief that the Assembly was suspended and the so-called Ministry was not functioning. It may be very sad that the suspension of the democratic process was being welcomed by the people there. But I find that even today two persons came to me from Lucknow and they wanted to ask my opinion, as a lawyer, whether anything can be done that this mid-term election should not be held but the President's Rule should continue for the whole term. Obviously, I told them that this is impossible. It is for the political parties to appraise and appreciate this position that the reaction of the people of the province is that they feel whichever party may come into power, they cannot expect a fair deal from it. A pointer to that may also be seen from the fact that only, perhaps, three or four weeks ago a certain person had willed that his heart should be transplanted into any person but that person should not be politician. Therefore, I am just pointing out all these facts for the hon'ble members of this House to realise that the politicians, as a class, have failed in the eyes of the people.

Now, in the background of these facts and in the history of the last year which has been narrated by so many speakers on this side and on that side, I feel that what the Governor did and recommended was merely the culmination of a series of a large number of earlier incidents and that it was an inevitable conclusion which had to be reached. As a matter of fact, everyone felt that sooner or later there would be the President's Rule and, from the speeches that have been made by my friends on the right side, I have inferred that their grievance is not so much against the President's Rule being imposed there but they are only challenging that the manner in which this Rule has been imposed has been a violation of the principles and the norms of democracy.

And because the Governor has voilated the norms of democracy, he has done an incorrect thing.

I will come to what is the Constitutional position, whether the Governor acted rightly within the framework of the Constitution, whether he transgressed the Constitution or whether it is difficult to say whether he did not do so.

The first thing which should be kept in mind is—at least that is my reading of the Constitution of India—that the Governor has been armed with special powers in the Indian Constitution which are perhaps not consistant with the norms of democracy. If you read certain provisions of the Indian Constitution, you will find that some extraordinary powers have been given to the Governor which seem to be a misfit in a democratic Constitution. These powers have been given to the Governor which should not have been given to him. But that is a matter for the amendment of the the Constitution or whatever it might be. We have only to see, within the framework of the Constitution, whether the Governor functioned suitably or not.

Now I have already placed before the hon. members what is the reaction of the people, and I purposely did so because, in order to analyse the conduct of the Governor, we have to see what are his duties. The duties of the Governor should be also considered in the light of the oath which the Governor is asked to take. A part of this oath is that he will devote himself to the service and well-being of the people. A duty is cast on the Governor to devote himself to the service and well-being of the people, and if the people heave a sigh of relief if he had taken a particular decision I think, reading these two things together, it can be inferred that what he did was in keeping with the oath which he had taken.

A second question arises. If he had acted in this manner and he had raised the question that a stable Ministry was not in the offing and, therefore, he had made the recommendation, the qnestion arises : was he a competent authority to decide this question whether a stable majority existed or not or whether this matter was to be disposed of on the floor of the House. As I said, so far, these thing can only be decided by laying down traditions, for, there is no clear indication

in the Constitution as to how the Governor should come to his own conclusions. On the word of the Constitution, the Governor is entitled to appoint a Chief Minister. Obviously, some of my friends on my right are contending that the party in power still existed ; only the Chief Minister had resigned but the Party remained in power. I somehow cannot accept this contention. In my opinion, after Mr. Charn Singh resigned, and after the Assembly was suspended, there was no Group that was functioning as the majority group. If any grievance had to be voiced it should have been voiced at the time when the Assembly was suspended, but after the Assembly was suspended, a vacuum had been created and the Governor had stepped in. After the Governor stepped in, it cannot be contended that a particular Party was continuing to be in Government and that it should have been tested. I feel that if the Governor had been pleased to call the S. V. D., I am sure, they would have formed a majority.

If the Governor had been pleased to call the congress leader Shri C. B. Gupta, he would also have secured the majority. It is the stuff of an appreciable section of the legislators that is responsible for this for they have one leg in this camp and one leg in the other camp. Whoever had been called to form a Ministry would have had the backing of the majority.

SHRI D. C. SHARMA : How true ! How true !

SHRI A. N. MULLA : In these circumstances, therefore, if the Governor decided that this majority was not dependable and that there must be a stable government, then he was acting within his rights, for, the people had a right to demand from their representatives that they should be governed. They cannot be happy with a vacuum, and if for whatever reasons it might be, there is a vacuum, then certainly the Governor is entitled to protect the interests of the people and say 'I shall give you a government if I can'. Obviously, a mid-term election is the only way of deciding whether the elected representatives of the people are still the representatives of the people or whether they have ceased to be the representatives of the people.

I would like to say something more, but I have heard your bell, and, therefore, I am sitting down.

श्री शिवनारायण (बस्ती) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस पक्ष को भी सुना और उस पक्ष को भी सुना । आज उत्तर प्रदेश का जो प्रश्न है, वह न बंगाल का है और न पंजाब का है और न हरियाना का है । मैं आज गवर्नर रेड्डी साहब पर चार्ज लगाना चाहता हूँ कि उन्होंने कांस्टीचूशन के होते हुए, डेमोक्रेटिक सेट-अप के होते हुए, सही एक्शन नहीं लिया । इंग्लैंड में जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो वहां की क्वीन या किंग अपोजीशन के लीडर को सरकार बनाने के लिये इन्वाइट करते हैं और वह गवर्नमेंट फौर्म करता है, ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं । आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सत्य बात कहना चाहता हूँ, न मुझे इस सरकार से कम्पन है और न उधर से कम्पन है, मैं अपना कर्तव्य पालन करना चाहता हूँ—

I am the representative of the people by the people for the people. I have come here as the elected representative of the people.

हुजूर, मैं कांस्टीचूशन पर बोलना चाहता हूँ—

"If the President on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise.....".

"अदरवाइज" लफ्ज है—

The word 'otherwise' which occures here is a very important word. Here, I am totally in agreement with Shri S. A. Dange and I support him ; he was quite correct when he said that the floor of the House was the place where the issue should have been decided.....

SHRI D. C. SHARMA : He will cross the floor now.

SHRI SHEO NARAIN : It is the floor of the Assembly where the test of democracy is done and the matter is judged. It can be judged here, not in the President's

[Shri Sheo Narain]

house or in the Governor's bungalow. I would say that the Governors of Hindustan are acting like dictators. They are marching towards dictatorship. I would inform this Government that coming events cast their shadows before. My hon. friend from the D. M. K. had referred to the words 'stable majority'. This is a very dangerous phrase the word 'stable' is a very dengrous Word. It will affect them also, and it may affect anyone.

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय,

The President who is the head of this country should have gone through the statement of the Governor.

माननीय राष्ट्रपति को राज्यपाल एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन रबरस्टैम्प की तरह से काम नहीं करना चाहिये, उनको अपनी कामन-सैन्स से काम लेना चाहिये था ।

जरा एस० वी० डी० वाले अपने कलेजे पर हाथ रख कर बैठें, आज भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 200 एम० एल० ए० हैं, जिनके नेता श्री चन्द्र भानु गुप्त जी हैं, कांग्रेस वहां की सब से बड़ी पार्टी है, लेकिन उस के बावजूद भी उन्होंने कहा है—

"We are not in a hurry to topple down the S. V. D. Government."

My hon. friend Shri Jharkande Rae who was the Food Minister in the S. V. D. Government might contradict me if what I am saying is wrong. Shri C. B. Gupta had said that in the House there. This is a clear picture of the Congress people or the Congress MLAs of U. P. They have acted very nicely. I hope that this Government will learn a lesson from U. P. The other day I told the Speaker that I represented U. P.

Madhu Limae and others do not represent U. P. I represent U. P. I know the situation there. My chief whip is here. He is a member of the working Committee. When this was going on the 13th March I was watching the situation. When I came to Delhi, I conveyed the message to him. I conveyed it to everyone in high authority here.

वह आग वहां पर लगने वाली है कि अगर बाल्टी पानी लेकर भी दौड़ेंगे तो बुझने वाली नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात की परवाह नहीं की ।

मैं चरण सिंह की निन्दा नहीं करना चाहता हूँ, मैं एस० वी० डी० की निन्दा नहीं करना चाहता हूं लेकिन यह कांस्टीट्यूशनल प्रश्न है । गवर्नर की ड्यूटी थी कि उत्तर प्रदेश में चाहे वह एस० वी० डी० के लीडर को बुलाते, चाहे अपोजीशन के श्री चन्द्र भानु गुप्त को बुलाते और गवर्नमेंट को फौर्म कराते । इस बात में हम दोनों पार्टियां यूनैनिमस थीं कि वहां पर सरकार बनाई जाती । लेकिन गवर्नर ने हमारे साथ ज्यादती की और इस तरह से हमारे प्रजातन्त्र की शान को धक्का पहुँचाया । प्रजातन्त्र को कायम रखने के लिये-यह कोई जोक नहीं है—हम इलैक्शन लड़ कर आये हैं, किस मुसीबत से यहां आये हैं और अब इस इलैक्शन पर फिर कितनी पब्लिक मनी खर्च होगी । आपने उनको गवर्नर बनाया है जो रिटायर-शुदा हैं, जो ओवर-एज हैं, जिनके पास एबिलिटी है .....(व्यवधान).....

If I had been the Governor of Bengal, I would have given a long rope to Ajoy Mukherjee until he hanged himself, I would have waited till 18 December.

मैं 18 दिसम्बर तक वेट करता । ऐसी ही भूल पंजाब में हुई । इसलिये मैं इस सरकार से और होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि जरा इस तरफ़ ध्यान दें । एस० वी० डी० की गवर्नमेंट के कारनामे 10 महीनों में खुले गये-

I will face Atal Bihari Vajpayee in the mid-term elections. But I am opposed to mid-term elections. I am demanding of this Government that this Proclamation should be returned to the President. Let us call back the elected representatives of the people, restore the constitutional position and let them decide...the issue in the

Assembly. What has been done is a great injustice to U. P.

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : हिन्दी में बोलो ।

श्री शिवनारायण : उपाध्यक्ष महोदय, ये हिन्दी के सेवक नहीं हैं, उसके शत्रु हैं, ये उसका कल्याण नहीं चाहते हैं। मैं इस ग्रोगस्ट हाउस से ईमानदारी से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के कल्याण के हित में ग्राप सब लोग सोचें, यह हमारे लिये दुनिया के ग्रन्दर बड़ी बदनामी की बात है। मैं ग्रगस्त में फ़ारन गया था, मैं वहां देख कर ग्राया हूं कि वहां पर क्या पोज़ीशन है ग्रौर हमारे यहां क्या हालत है......

श्री महाराज सिंह भारती : वहां भी कांग्रेस की बुराई सुनी होगी ।

श्री शिव नारायण : महाराज सिंह जी बोल रहे हैं, उनको बोलने की ग्रादत है, सुनने की तमन्ना नहीं है। लेकिन याद रखिये कांग्रेस वाले जिम्मेदार लोग हैं, वे रीयल बात कहते हैं, ग्रौर इसी लिये तुम फेल हुए, निकम्मो ।

The Governor should have invited C. B. Gupta to form the Government.

क्योंकि उनकी पार्टी एक रही है, ग्रपोजीशन में सबसे बड़ी पार्टी रही है। मुझे उसमें भी एतराज नहीं था कि ग्रापने विकल को बुलाया होता, हरिश्चन्द्र को बुलाया होता ग्रौर वहां पर गवर्नमेंट बनाने दी जाती ग्रौर फिर ग्रसेम्बली में फैसला हो जाता है ।

घोखा न दो, भाइयों, घोखा न दो, भाइयों,
मझधार में है नांव हमारी ।

जिनकी 40 से कम उम्र है, मैं उन को सचेत करना चाहता हूं कृपालनी जी हमारे पुराने नेता हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ, त्रिलोकी सिंह को वेलकम करता हूँ, डांगे जी को वेलकम करता हूं, राममूर्ति जी को वेलकम करता हूँ, ग्रौर हमारे जो बाप बैठे हैं हमारे सामने, इनको भी वेलकम करता हूँ। ग्राप सब कांस्टीचूशन के पंडित रहे हो, ग्राप सब विचार करें ।

16.00 hrs.

The Governor should have tested the members in the Assembly. He should have left it to the Members to decide. If he is not going to act on that principle, he is killing democracy.

I hope that this Government will appoint such persons who can act with their common sense. Is there any law and order in Uttar Pradesh. Today there is no law and order in Uttar Pradesh. I saw in Allahabad the other day; four people were killed. These people here read from the newspapers. But I was present there, Sir. Two from this side and two from that side were killed.

इसलिये मैं ग्रदब के साथ हाथ जोड़ कर इस सरकार से प्रार्थना करता हूं ग्रौर खास तौर पर होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि जो प्रेसीडेन्ट रूल वहां पर लागू किया गया है उसमें ग्रगर हमारे एक बच्चे को भी गोली मारी गई तो उसके खून की जिम्मेदारी ग्राप पर होगी। मैं डिमान्ड करता हूँ कि यह प्रोक्लेमेशन वापिस लिया जाये ।

श्री ग्रर्जुन सिंह भदौरिया (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के ग्रन्दर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उससे संविधान की हत्या की गई, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं हैं। ग्राज इस तर्क में जाने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रपति शासन सही है या गलत। ग्राज उत्तर प्रदेश का हर शिक्षित व्यक्ति ग्रौर दूसरे लोग यह स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश के ग्रन्दर जो कुछ किया गया है, जिस ढंग से किया गया है वह सब ग्रवैधानिक ढंग ग्रपनाया गया है। मैं ग्रापके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से यह ग्राग्रह करना चाहता हूँ कि रेड्डी साहब, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जिस ढंग से उत्तर प्रदेश के ग्रन्दर शासन चला रहे हैं क्या वह तरीका वैधानिक है, क्या उस

[श्री अर्जुन सिंह भदोरिया]

ढंग से उनको चलने की इजाजत दी जा सकती है। राज्यपाल राज्यपाल हैं राज्यपाल या वहां का चीफ सेक्रेटरी मुख्य मन्त्री नहीं हो सकता है। यह भारती लोकतन्त्र के लिये एक बड़ा अपमान है कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर प्रति दिन विधान भवन के अन्दर जाकर मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे। अभी तक हमने उनके विरुद्ध कोई कदम उठाना उचित नहीं समझा जबकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधान सभा को भंग कर दिया और मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी। लेकिन अब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ केन्द्रीय सरकार से और खास कर के घर मंत्री से कि अगर गवर्नर महोदय ने राज्यपाल भवन में बैठकर काम चलाया तो ठीक है, उन्हें चलाना चाहिये और हम उनका स्वागत करेंगे लेकिन अगर वे कौंसिल हाउस में प्रति दिन जाकर मुख्य मन्त्री की कुर्सी पर बैठेंगे तो आगे चल कर सबसे पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी उनका घेराव करेगी और उनको इस बात के लिये बाध्य करेगी कि वे लोकतन्त्र की हत्या अपने कामों से न होने दें। (व्यवधान)... लोकतन्त्र की हत्या की जिम्मेदारी आप पर है। और आप जब हत्या करेंगे तो उसको रोकने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है।

16.02 hrs.

[Shri C.K. Bhattacharyya *in the Chair*]

मुल्ला साहब ने निहायत संजीदगी के साथ कहा कि उनसे कुछ लोगों ने यह आकर कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन निरन्तर बना रहे तो उनको ज्यादा खुशी होगी तो मैं कहना चाहूँगा कि इसी राष्ट्रपति शासन के अन्दर आज इलाहाबाद में क्या हो रहा है? आज उत्तर प्रदेश में संविद की सरकार नहीं है, आज वहां चरण-सिंह नहीं हैं और दूसरे लोगों की सरकार नहीं है, आज वहां पर सरकार है केन्द्र की और केन्द्र संचालक हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नर और उत्तर प्रदेश के गवर्नर की देख-रेख में जो कुछ इलाहाबाद में हो रहा है वह बहुत ही शर्मनाक है इस देश के लोकतन्त्र के लिये और उनके लिये भी लज्जा की बात है जोकि हमेशा लोकतन्त्र की दुहाई देते रहते हैं। यही नहीं, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के अन्दर पीलीभीत है और वहां पर एक छोटी सी टाउन एरिया है। आज वहां के 30 मुसलमान और उस टाउन एरिया के चेयरमैन गिरफ्तार किये गये हैं महज इसलिये कि उन्होंने मोहर्रम का जुलूस निकाला और जुलूस निकालने के पहले पर्मीशन नहीं ली। मैं आपके माध्यम से घर मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जब कभी दीपावली मनाई जाती है या होली पर रंग खेला जाता है तब क्या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इजाजत ली जाती है, क्या उनसे यह पूछा जाता है कि हम रंग खेलें या नहीं? पूरनपुर की टाउन एरिया में 16 हजार की आबादी में 8 हजार मुसमान हैं, टाउन एरिया में 4 मुसलमान सदस्य हैं, उन्होंने अपना उत्सव मनाया और पुलिस की देख-रेख में अपना जुलूस निकाला, मेंहदी भी उठाई और मेंहदी निकल जाने के बाद 30 मुसलमान और टाउन एरिया के चेयरमैन श्री हर नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया ...(व्यवधान)...

गलत आप करते हैं। आप गलत करेंगे तो उसको ठीक भी किया जायेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास कोई जवाब है कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया?

एक और उदाहरण आया कि महाराष्ट्र में एक हरिजन को मारा गया। उत्तर प्रदेश में भी इटावा के अन्दर एक कपड़ा धोने वाले हरिजन धोबी को यहां तक मारा गया कि वह मर गया और उसके बाद उसको जला दिया गया, उसकी लाश भी उसके घर वालों को नहीं दी गई। तो आज उत्तर प्रदेश के अन्दर संविद की सरकार है या राज्यपाल का एक छत्र राज्य है? निरन्तर मैं देख रहा हूँ कि 20 वर्षों के अन्दर अपराधों की संख्या बढ़ी है और

उससे देश के लोकतन्त्र के लिये, देश की सुरक्षा के लिये और नागरिक जीवन के लिये एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। आज जो यह सवाल है, यह केवल बिरोधी दलों के सामने ही नहीं है बल्कि आप जो शासक दल के हैं उनके सामने भी यही सवाल है।

रूलिंग पार्टी, शासक दल के जो लोग हैं उन्होंने, हम जो गैर-कांग्रेसी दल हैं, उनके कम्पाउन्ड में यह गेंद फेंका है और कहा है कि जो गैर-कांग्रेसी दल हैं, संविद के जो विभिन्न घटक हैं, क्या उनमें एकता है ? मैं कहना चाहता हूँ कि हां, एकता है। बार-बार एस० एस० पी० का नाम लिया गया और कहा गया कि एस० एस० पी० के लोग वहां के शासन में शामिल नहीं थे। यह बात सही है कि हम सरकार में शामिल नहीं थे लेकिन वहां की सरकार को लगातार हमारा समर्थन रहा। हम हमेशा इस बात को समर्थन देते रहे कि संविद के नेता को बुलाया जाये। इस सिलसिले में 3 अप्रैल को राष्ट्रपति से मिले और 29 मार्च को वहां के गवर्नर से मिले थे और उनसे साफ-साफ कहा था कि आप संविद के नेता को बुलाइये क्योंकि वे सर्वसम्मति से चुने गये हैं। अगर वे संविद के नेता को बुलाना नहीं चाहते थे तो फिर जैसा कि यहां पर वाजपेयी जी ने कहा, उन्हें कांग्रेस के नेता को बुलाना चाहिये था। अभी तक जो तथ्य उपस्थित हुये हैं और जो कुछ हमने देखा और समझा है उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि लगातार उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने इस बात की कोशिश की कि किसी न किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बहुमत में ला दें और इतना बड़ा बहुमत ला दें जिससे स्थायित्व आ जाये। उन्होंने हमेशा अपने ब्यानों में और पत्र-व्यवहार में इस बात की धमकी दी कि अगर स्थायी सरकार नहीं बनती तो मध्यावधि चुनाव होंगे। इस मध्यावधि चुनाव की नंगी तलवार एक सूत के धागे में टांग करके उत्तर प्रवेश के विधायकों की गरदन पर खड़ी कर दी गई ताकि किसी न किसी प्रकार संविद के दलों को छोड़ कर कांग्रेस के कैम्प में आ जांय। जिस ढंग से वहां पर गवर्नर ने काम किया और जैसा कि आज भी कर रहे हैं वह लोकतन्त्र के लिये बड़े अपमान की बात है। आज उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इसका विरोध कर रहा है।

इसलिये मैं पुन : आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि वह उत्तर प्रदेश के गवर्नर को इस बात के लिये तम्बीह करे कि वह किसी भी चुने हुये नुमाइन्दे की कुर्सी पर बैठकर काम न करें बल्कि राज्यपाल भवन में ही, सारी फाइलों को मंगाकर कार्य-संचालन करें। और यदि उन्होंने लोकतन्त्र के विरुद्ध काम किया तो उनका विरोध किया जायेगा। उनका जो भी कार्य अवैधानिक होगा उसका विरोध किया जायेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अधिष्ठता महोदय, उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल को जिस प्रकार से विधान सभा भंग करने की और राष्ट्रपति शासन लागू करके मध्यावधि चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है वह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसी राजनीतिक स्थिति हमारे राज्य में पैदा हुई कि आम चुनावों के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर ही इस गरीब प्रान्त की और इस गरीब देश की 8 करोड़ जनता को फिर से मध्यावधि चुनाव में जाने की स्थिति पैदा हो गई। इस स्थिति पर हम को भावनाओं से नहीं अपितु जो वस्तुस्थिति है और जो परिस्थितियां हैं उन के ऊपर विचार करना चाहिए कि वस्तुतः कौन सी ऐसी बातें थीं कि जो आज हमारे देश की राजनीति में अस्थायित्व पैदा करने के लिये जिम्मेदार हैं ! कुछ ऐसी चुनौतियां पैदा की जा रही हैं उन का मुकाबला हम कैसे करें ?

यह बात सही है कि पिछले 20 वर्षों में इस देश में कांग्रेस की राजनीतिक इजारेदारी जिसको कहना चाहिये एक प्रकार से पूरे देश में उसका शासन था। इस देश को आगे ले जाने के लिये कार्यक्रम के आधार पर बहुत सी बातें

[श्री चन्द्रजीत यादव]

कहीं गई थीं लेकिन फिर भी जनता के मन में असन्तोष की भावना थी, जनता एक विकल्प ढूंढ रही थी और जब बहुत से प्रदेशों के अन्दर कांग्रेस बहुमत में इस बार नहीं आई तो ऐसी पार्टियां जिन में राजनीतिक और सैद्धान्तिक किसी भी प्रकार का ऐका नहीं था, न उन के दृष्टिकोण में और न उन के कार्यक्रम में, लेकिन इस नाम के ऊपर कि चूंकि जनता कांग्रेस से नाराज है, जनता एक विकल्प ढूढ़ती है, वह पार्टियां भी शासन के अन्दर सत्तारूढ़ हुई। अब उन के आने के बाद जो स्थिति पैदा हुई उसके ऊपर हम गम्भीरता से विचार करें केवल कांग्रेस को दोष देने से या परिस्थितियों पर परदा डालने से काम नहीं चलेगा।

उत्तर प्रदेश के अन्दर एक स्थिति पैदा हुई। कांग्रेस की सरकार वहां पर थी और जब वहां के राज्यपाल के भाषण के ऊपर विचार किया जा रहा था तो कांग्रेस के कुछ सदस्य विरोधी दल में जा बैठे। कांग्रेस के नेता ने बग़ैर संविधान की व्यवस्था का सहारा लिये उन्होंने इस बात को उचित समझा और एक कांस्टीट्यूश्नल प्रोपराइटी और डैमोक्रेटिक प्रोपाराइटी के नाम से त्यागपत्र दे दिया। वहां वह त्यागपत्र नहीं दे सकते थे वह मंत्रिमण्डल चला सकते थे जैसा कि पंजाब के विरोधी दल के मुख्य मन्त्री ने चलाया था। वह मंत्रिमंडल की बैठक करके प्रस्ताव पेश कर सकते थे मध्यावधि चुनाव करवाने का और इस तरह विरोधी दल को वहां सरकार बनाने का अवसर वह नहीं दे सकते थे। लेकिन उन्होंने वैसा करना उचित न समझा और देश के अन्दर की परिस्थितियों का ख्याल करते हुए उन्होंने ख्याल किया कि कुछ प्रजातांत्रिक परम्पराओं का निर्माण करना चाहिए अर्थात् विरोधी दल को भी यह अवसर मिलना चाहिये। विरोधी दल ने सरकार बनाई। ऐसी पार्टियां जिनके कि कार्यक्रम एक नहीं थे, जिनके कि राजनीतिक दृष्टिकोण एक नहीं थे, जिनके कि सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों में गम्भीर अन्तर्विरोध था उन्होंने मिल कर कांग्रेस के विरोध के नाम पर, उन की एक ही नीति समान थी और वह था कांग्रेस का विरोध करना, कांग्रेस का अन्ध विरोध उन का कार्यक्रम था उस के ऊपर वहां सरकार बनी। जो सरकार वहां बनी उस सरकार को निरन्तर संकट पैदा होता चला गया। वह संकट इसलिए पैदा हुआ कि परिस्थितियां उन्हें मजबूर कर रही थीं। इस देश में जनता की समस्याएं केवल भावनाओं पर नहीं किसी अन्ध विरोध के ऊपर नहीं, गुस्से के ऊपर नहीं अपितु वह एक कार्यक्रम, एक राजनीति और एक सिद्धान्त के ऊपर हल हो सकती हैं। उत्तर-प्रदेश की गैर कांग्रेसी सरकार समस्याएं नहीं हल कर पाई। उस के उस के 10 महीने और 10 दिन के शासन में जनता का रोष निरन्तर बढ़ता गया। जो संविद सरकार कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती थी कि उसने राज्य कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं कीं और उन के साथ सख्ती के साथ पेश आई हम ने देखा कि उसी संविद सरकार ने जब वह सत्तारूढ़ हुई तो उस ने उन्हीं राज्य कर्मचारियों के नेताओं को नजरबन्दी कानून के मातहत गिरफ्तार कर के जेल भेजा और उन्हीं राज्य कर्मचारियों को नौकरी से हटाया। उस समय यही मित्र संविधान का सहारा लेकर कहा करते थे कि यह कांग्रेस सरकार नजरबन्दी कानून लागू करके संविधान की हत्या कर रही है और ऐसा करके उसने संविधान को ताक पर फेंक दिया है उन्हीं मित्रों ने बाद में जब वह सत्ता में आये तो उसी नजरबन्दी कानून का उन्होंने सहारा लिया। यही लोग पहले कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस मजदूरों पर गोली चलाती है कांग्रेस विद्यार्थियों पर गोली चलाती है उसी संविद की सरकार ने बाद में उत्तरप्रदेश में मजदूरों पर गोली चलाई, विद्यार्थियों पर गोली चलाई, उत्तरप्रदेश में किसानों का लगान बढ़ाया, उन की सिंचाई की दर बढ़ायी और

उन की सारी सुविधाएं छीनीं। निरन्तर वहां जनता की परेशानियां बढ़ती गई। कोई समस्या हल नहीं हो पायी। जनता का रोष बढ़ता गया उस प्रदेश के अन्दर और फलस्वरूप उत्तरप्रदेश की गैर-कांग्रेसी सरकार के अन्दर निरन्तर अन्तर्विरोध उन का बढ़ता गया। 10 महीने के शासन काल में गैर कांग्रेसी सरकार ने एक काम किया। उन्होंने शासन की सत्ता का प्रयोग जनता की समस्याओं को हल करने के लिये नहीं किया, जनता के हित में उस का प्रयोग नहीं किया। पार्टी के हित में उन्होंने सत्ता का प्रयोग उत्तरप्रदेश के अन्दर किया। श्रीमन, जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफ़ा दिया। चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि इस एस० वी० डी० के अन्दर ऐसे दल हैं जो राष्ट्र हित में काम नहीं करते हैं जो जनहित में काम नहीं करते हैं और जो दलीय स्वार्थ के हित में काम करते हैं, चूंकि उन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया इसलिए ऐसी स्थिति में मैं ने इस्तीफ़ा दे दिया। चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा देते हुए गवर्नर को पत्र लिखा कि अगर एक हफ्ते के अन्दर संयुक्त विरोधी दल एकसर्वसम्मत नेता का चुनाव कर लेते हैं तो उन को सरकार बनाने का अवसर दिया जाय और अगर नहीं कर पाते तो मध्यावधि चुनाव करवाये जायं। मध्यावधि चुनाव के लिये खुद संविद सरकार ने पहले सिफारिश की थी। चौधरी चरण सिंह इस्तीफा देते हैं 17 फरवरी को और 21 फरवरी को एस० वी० डी० की बैठक होती है। कुछ लोग मिल करके रामचन्द्र विकल को नेता चुनते हैं और उस के दो घण्टे के अन्दर चौधरी चरण सिंह का दल बी० के० डी० और हरिश्चन्द्र जो कि सर्वसम्मत नेता थे वह जाते हैं गवर्नर के पास कि हम विकल को नेता नहीं मानते। यह हमारे नेता नहीं हैं। कौन उस के लिये जिम्मेदार है? इस चीज को बीते हुए एक हफ्ता नौ दिन और दस दिन हो गये। जब संविद सरकार के कोई एक सर्वसम्मत नेता का चुनाव नहीं हो पाया, अन्तर्विरोध बढ़ता गया। गवर्नर ने प्रतीक्षा की चौधरी चरण सिंह की सलाह को मान कर। चौधरी चरण सिंह ने एक दूसरी बात और कही। उन्होंने 9 फरवरी के मन्त्रिमंडल के एक प्रस्ताव का हवाला दिया और कहा कि हम ने 9 फरवरी के मन्त्रिमण्डल की बैठक में यह निश्चय किया है कि हम मध्यावधि चुनाव करने वाले हैं। उत्तरप्रदेश के अन्दर संविद के मन्त्रिमण्डल ने यह प्रस्ताव पहले पास किया था। उन्होंने कहा था कि हम शासन नहीं चला सकते लेकिन हम कांग्रेस को शासन में नहीं आने देंगे और हम मध्यावधि चुनाव करवायेंगे। 9 फरवरी को मन्त्रिमण्डल में वहां निर्णय हुआ। चौधरी चरण सिंह ने उस को गवर्नर के पास भेज दिया फिर जनसंघ के उपमुख्य मंत्री श्री राम प्रकाश ने उस को कंट्रैडिक्ट किया और कहा कि मंत्रिमण्डल का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है। वहां ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि किसी भी बात पर उन में आपस में परस्पर एका नहीं रहा। मजबूर होकर 26 फरवरी को विधान सभा को मुअत्तिल किया गया और उसे मुअत्तिल इसलिये किया गया ताकि यहां एक जिम्मेदार सरकार की सम्भावना फिर से देखी जाय कि कोई एक स्थायी सरकार यहां पर बन सके।

अभी श्री डांगे ने कहा कि वहां पर यह माध्यावधि चुनाव क्यों करवाते हो? श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि चन्द्रभान गुप्त को क्यों नहीं मुख्य मन्त्री बना दिया? 26 फरवरी को जब विधान सभा मुअत्तिल की गई तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री भूपेश गुप्त ने बयान दिया कि विधान सभा को मुअत्तिल नहीं करना चाहिए था बल्कि उसे भंग कर देना चाहिए था। प्रधान मन्त्री और चन्द्रभानु गुप्त द्वारा कांग्रेस सरकार को लाने के लिए यह षड़यंत्र किया जा रहा है। यह भंग करने की मांग गवर्नर की रैकमेंडेशन से पहले श्री भूपेश गुप्त कर चुके थे और उन का यह आरोप था कि यह भंग न कर के जो विधान सभा को सस्पैंड किया गया है वह चन्द्रभान गुप्त को शासन में बैठाने के लिए किया गया है।

[श्री चंद्रजीत यादव]

प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया। आप जिम्मेदारी देते हैं कांग्रेस पर उन का प्रस्ताव है। जो आप की उस यूनिट की एक ईकाई थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, उस ने क्या कहा था :

> "Circumstances leading to the Proclamation had already shown that some of the non-Congress parties have clearly failed to respond to the challenging political situation posed before them and have been responsible for robbing the State of a democratic government."

किस ने जनतांत्रिक सरकार को वहां से हटाया ? कांग्रेस के ऊपर चार्ज नहीं था। आप की पार्टी के एस० वी० डी० की ईकाई के अन्दर जिस के कि मंत्री प्रताप सिंह जी थे और जो कि संयुक्त दल के महामंत्री होते थे उन्होंने कहा था कि आप ने हमारी डेमोक्रेसी को उस प्रदेश से छीन लिया। इन के प्रधान मन्त्री श्री भसीन साहब कहते हैं कि यह जो स्थिति पैदा हुई है यह एस० वी० डी० की इकाइयों के कारण पैदा हुई है। हम इस लायक नहीं हैं कि आपस में मिल कर कंधे से कंधा मिला कर चल सकें।

अब श्रीमन्, आगे सुनिये। हरिश्चन्द की बात कही गई। हरिश्चन्द सर्वसम्मत नेता मान लिये गये उन की क्या राय थी। जब वहां यह कहा गया कि हम रामचन्द विकल को नेता नहीं मानते और वह प्रेसीडेंट रूल किया गया और असेम्बली को सस्पैंड किया गया तो उस के बाद हरिश्चन्द ने अपना रिएक्शन देते हुए अखबार वालों को कानपुर में कहा था :

> "Jana Sangh is responsible for all that has happened and the President rule is the only right step."

यह आप के नेता हैं जिन को कि आप ने सर्वसम्मत नेता चुना था। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रेजिडेंट रूल के अलावा कोई चारा नहीं था इस लिये ऐसा किया गया।

अब आप दूसरी बात देखिये। कहा जाता है कि सारा काम अप्रजातान्त्रिक तरीके से होता है। 22 दिसम्बर को विधान सभा स्थगित की गई। श्री भारखंडे राय यहां बैठे हैं, वह गवाही दे सकते हैं। वह पन्द्रह वर्ष तक विधान सभा के सदस्य रहे हैं, मैं भी दस वर्षों तक वहां का सदस्य रहा हूं। उस समय यह होता था कि विधान सभा की साल भर में औसत 130 बार से लेकर 135 बार तक सिटिंग होती थी। दस महीने एस वी डी की सरकार ने काम किया। दस महीनों के अन्दर कम से 125 बैठकें होनी चाहिये थीं। लेकिन हुई कितनी ? कुल 31 बैठकें। 20 परसेंट भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ? आप प्रजातान्त्रिक तरीके से काम करना चाहते थे, आप चाहते थे कि जनता की हर समस्या पर विधान सभा विचार करे। लेकिन आप विधान सभा को फेस नहीं करना चाहते थे, आप अपने अन्तर्विरोधों से डरते थे इस लिये केवल 31 दिन तक ही बैठकें हुई। और उस 31 दिनों के अन्दर आप ने क्या किया ? क्या आप कोई कानून बना सके उत्तर प्रदेश विधान सभा में ? एक भी कानून नहीं बना। केवल एक कानून पेश हुआ जनसंघ के एक सदस्य की डिस्क्वालिफ़िकेशन को रिमूव करने के लिये, लेकिन लगातार वह विधान सभा के फ्लोर पर हारते रहे।

अभी श्री वाजपेयी ने कहा कि इस के लिये बाई एलेक्शन्स जिम्मेदार हैं तो जब पहले कौंसिल के चुनाव हुए तो सारे के सारे एक वी डी के लोग हार गये। अगर आप इस को लेते हैं तो कहां गया आप का बहुमत ? इस लिये केवल इस प्रकार के दोषारोपण से काम नहीं चलेगा।

अब आप आगे देखिये। जो स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई क्या उस के लिये कांग्रेस जिम्मेदार है ? अप्रैल के पहले हफ्ते में जब कि यह तलाश हो रही थी कि कौन स्थायी नेता सरकार बना सकता है, यह उन दिनों की बात

है। अगर गवर्नर साहब देखते तो उन को मालूम हो जाता कि विधान सभा भंग करने से पहले जनसंघ के तीन सदस्य तीन दिन पहले चले आये कांग्रेस के अन्दर, बी के डी के तीन सदस्य आठ दिन पहले चले आये कांग्रेस के अन्दर, पी एस पी के तीन सदस्य त्रिलोकी सिंह के साथ चले आये कांग्रेस के अन्दर, एस एस पी के एक सदस्य चले आये कांग्रेस के अन्दर। लगातार विरोधी दलों की संख्या घटती चली जा रही थी। और उन के ओर से कांग्रेस की ओर आने वालो की संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद...

एक माननीय सदस्य : नाम बतलाइये।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय सदस्य नाम की बात कहते हैं। किस ने पहले रिफ्यूज किया ? गवर्नर ने कहा कि वेरिफिकेशन कराना है। श्री डांगे ने जो कहा कि मैं उस से सहमत हूँ कि विधान सभा के सदस्यों की शहादत लेना, कागज पर दस्तखत कराना इस तरह से प्लेज दिलाना, ठीक नहीं है। लेकिन साथ-साथ वेरिफिकेशन रिफ्यूज किया एस बी डी ने। निरन्तर रिफ्यूज करती गई कि हम वेरिफिकेशन के लिये तैयार नहीं हैं। जब गवर्नर ने सिफारिश कर दी, तब कहने लगे कि हम वेरिफिकेशन के लिये तैयार हैं, किसी तरीके से गद्दी पर बैठना चाहते हैं।

इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि जो स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हुई उस में राज्यपाल महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 163 (1) के अन्दर स्वविवेक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्दर दुःखद स्थिति है, कोई स्थायी सरकार नहीं बना सकता, किसी का बहुमत नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि 20-25 सदस्य ऐसे हैं जिन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह किधर जायेंगे और क्या करेंगे। कोई भी जिम्मेदारी से ऐसा नहीं कह सकता। खेद की बात यह हुई कि एक सरकार फेल हुई, कांग्रेस की सरकार फेल हुई तो गवर्नर साहब ने विरोधी दलों के नेता से कहा कि आप गवर्नमेंट बनाइये। वह फेल हुई। उस के बाद विरोधी दल के नाते एक और सरकार बनी। लेकिन उन्होंने देखा कि उस से कोई लाभ होने वाला नहीं है। परिस्थिति ऐसी खतरनाक हो गई है कि स्थायी सरकार बन नहीं सकती। ऐसी स्थिति में क्या किया जाय ?

मैं एक चीज बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ। मैं इस से सहमत नहीं हूं कि गवर्नर को यह अधिकार दिया जाय कि वह कहे कि फलां मुख्य मंत्री के साथ बहुमत है या अल्पमत है। बंगाल के गवर्नर ने जो कुछ किया मैं उस से सहमत नहीं हूँ कि अगर कोई मुख्य मन्त्री है तो उसे गवर्नर हटा दे। यहां तो कोई मुख्य मंत्री था नहीं, लेकिन अगर कोई हो, तो उस को डिसमिस कर देना, दूसरे को मुख्य मंत्री बना देना, यह गलत है। यह संविधान की मान्यता के खिलाफ है, उस के औचित्य के खिलाफ है। लेकिन इस के साथ-साथ बंगाल के स्पीकर ने भी जो कुछ किया वह भी गलत है। स्पीकर को भी यह अधिकार नहीं है कि वह हाउस में कहे कि यह सरकार गैर-कानूनी है या संविधान के खिलाफ बनी हुई है। आज यह प्रश्न देश के सामने है और मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लोगों को बैठ कर इस पर विचार करना चाहिये। पिछले दो सालों में देश को जो अनुभव हुआ है उस की रोशनी में संविधान के अन्दर इस प्रकार का संशोधन किया जाय, इस प्रकार धाराओं को स्पष्ट किया जाय जिस से पता चले कि गवर्नर का अधिकार कहां तक जायेगा, और स्पीकर का अधिकार कहाँ तक जायेगा, वर्ना गवर्नर मनमानापन कर सकता है और डिक्टेटरशिप की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है अथवा स्पीकर जनता की चुनी हुई विधान सभा को बुलाने नहीं दे सकता है, उस को रोक सकता है, यह खतरा भी इस देश के अन्दर बढ़ सकता है।

मैं कहना चाहता हूँ कि आज यह स्थिति है कि हम को पार्टी से ऊपर उठ कर इन सारी

[श्री कन्नजीत शादव]

बातों पर ठन्डे दिल से और गम्भीरता से विचार करना चाहिये। श्री वाजपेयी ने कहा कि संविधान सभा के अन्दर डा० अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। उन्होंने क्या कहा था, इस की बात नहीं है। संविधान के अन्दर जो व्यवस्था है, जो धारायें हैं, उन के अनुसार जो कुछ गवर्नर ने उत्तर प्रदेश में किया है वह संविधान के खिलाफ नहीं है, वह संविधान के अनुच्छेदों के अनुकूल है। परिस्थितियां ऐसी थीं जिस में गवर्नर को मजबूर हो कर इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा। ऐसी स्थिति कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है, लेकिन मैं जनतन्त्र के अलम्बरदारों से कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाये जिस के अन्दर विधान सभा में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाय और शासन को दल हित के लिये प्रयोग करने की खुली छूट दी जाय और सरकार को तथा विधान सभा के चलने न दिया जाये, तो हमारे देश की जो जनता है, वह इस देश के प्रजातन्त्र को कायम रखने के लिये जिम्मेदार है, जिस की अल्टिमेट रिस्पांसिविलिटी है इस मुल्क में डिमाक्रेसी की रक्षा करने के लिये, अगर हमें उस के सामने जाना होता है तो हम को ऐसे निर्णय का स्वागत करना चाहिये। हमारे देश की जनता इस तरह का निर्णय लेने में समर्थ है, अपने देश का संकट हल करने में समर्थ है। ऐसी स्थिति में जो निर्णय किया गया है मध्यावधि चुनाव का, मुझे यकीन है कि उस में इस परिस्थिति को जनता हल करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उस का समर्थन करता हूँ और श्री वाजपेयी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उस का विरोध करता हूं।

SHRI J. B. KRIPALANI (Guna) : Mr. Chairman, Sir, I have been listening to this discussion. The previous speaker from the Congress asked us to be non-partisan but his whole speech was partisan. We have been blaming each other. The United Front Government in Bengal did not want the interference of the Governor and they wanted that there should be fresh elections. In U.P., they do not want fresh elections. And the Congress people accuse different parties that have made up United Fronts of being divided among themselves. It was natural for so many parties to be divided. But is it natural for the Congress to be a divided among themselves ? Is that not a fact ? Take, for example, U. P. There, the congress was hopelessly divided. The previous speaker said that Gupta Government resigned automatically and he commended that. I also commend it. But Gupta Government lasted for how many days ? I am obliged to say that Charan Singh. Government lasted much more than Gupta Government.

So far as defections are concerned, I think, all the parties are tarred with the same brush. Nobody can say he is free from inducing people to change sides. This is not the question. The fundamental question is who is to decide whether a particular party or a set of parties have a majority, may be of one or two. That does not matter. The Labour Government had mojority of two and even with the majority of one, it was carrying on the Government. It is not a question of a big majority. I do not know what thermometer this Governor has to find out where the majority lay. He did not call those people; he did not get their signatures. Nothing of the sort. He had some psychological inspiration : Suppose a stable Government can not be formed, but that is not the question. The question is who has the majority. The Governor is not a soothsayer; he is not Haveli Ram to decide who shall be the Prime Minister or the Home Minister; he has no thermometer.

Why did we condemn the Speaker of the Bengal assembly ? It was because he constituted himself as an authority to take a decision on behalf of the Assembly. He abrogated the right of the Assembly. Here. the Governor has abrogated the right of the Assembly. The straight course would have been to call the Assembly. In Punjab also, call the Assembly and put the question of minority and majority before it. If there are slippery people here, there are slippery people there also; there are slippery people on both the sides. Who defected

from the Congress ? Who is this Mr. Charan Singh ? My friend was praising Mr. Charan Singh. He said that he was right. When he left the Congress, was he right ? Why does he not answer that ? Was he right ? We have all along been doing wrong things. The game began in 1941 when the Congress had no majority in the United Provinces of Andhra and Tamilnad; the majority was not with the Congress and they called Mr. Rajagopalachari to form the Government and he was made a member of the Upper House...

AN HON. MEMBER : in 1952.

SHRI J.B. KRIPALANI:...and he never fought an election; Mr. Rajagopalachari never in his life fought an election. These young people may not know old history. But I know the whole history. So, it is no use one party blaming the other. We are all same stuff. We all came from the Congress; we all participate in the defects of the Congress. Our Communist leader, Mr. S.A. Dange, was also in the Congress; All of us were in the Congress. We all participated in the sins of the Congress. There is no doubt about that. We carry our past also to some extent when we go to the other party; it is the original sin that we take to the other side.

So, the whole question is very simple. Is the Speaker to decide whether a Government is properly constituted or not ? Is the Speaker to defy the Legislature ? Is he to defy the High Court ? Does he become the Government in himself ? Here, in U.P. the Governor becomes the Government. He has absolutely no right to decide who has the majority or who has no majority. Only the Assembly can decide that. An hon friend said that the people are very happy that there is the President's rule. You go to the Coffee house and I tell you, you will hear this; people will be very happy if the Central Government is dismissed and Presidents rule is imposed *(Interruptions)* I do not know whether you go to the Coffee House. If you go to the Coffee House, you will hear people saying that this is a wretched government, the sooner it goes the better, So, it is not in the Coffee House that these things are to be decided. This has to be decided on the floor of the House. It is a very simple question and it should not be complicated.

DR. SUSHILA NAYAR : *rose-*

MR. CHAIRMAN : I had called Shri P. Ramamurti earlier. Let him speak now....

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi) : Then you would be calling two Opposition Members together. You should call one Member from our side and then call one Member from the other side.

SHRI S. K. TAPURAIAH (Pali) : Acharyaji is an all-party Member.

MR. CHAIRMAN : In any case, I shall call Dr Sushila Nayar after Shri P. Ramamurti. She may speak after Shri P. Ramamurti. *(Interruptions)* Let not the Members of the Opposition make it a point for their decision. Let it be left to the Chair to decide who will speak.

SHRI P. RAMAMURTI (Maduri): You may decide as you please.

MR. CHAIRMAN : I would suggest that Dr. Sushila Nayar may speak after Shri P. Ramamurti.

SHRI S. M. BANERJEE : What a defeat for the Congress !

SHRI P. RAMAMURTI : Acharya Kripalani was saying that all parties in this House were tarnished with the sin of defections. I would like to point out to him that as for as our party is concerned...

SHRI J. B. KRIPALANI : I am sorry : I did not mean the communists.

SHRI P. RAMAMURTI : As for as our party is concerned, we are not worried about this problem of defections.

SHRI S. K. TAPURAIAH : He does not recognise the hon. Member's party.

SHRI P. RAMAMURTI : We are not worried about this problem of defections because we do not take anyone as a member of our party if he comes and simply says 'I am prepared to join your party' give me a Ministership'. We enrol members to our party after a period of two years' testing. There is a probationary period of two years, and it is only after that that we enrol a member inside our party.

SHRI J.B. KRIPALANI : The Congress has also such a system.

SHRI P. RAMAMURTI : Therefore, we have no such problem.

SHRI SHASHI BHUSHAN BAJPAI (Khargone) : He is also a Congressman.

SHRI P RAMAMURTI : I was in the Congress, but I Joined the Communist party after two years' Probation.

My party is not opposed to elections as such. We ourselves had demanded elections in West Bengal and in Punjab. Therefore, it is not a question of mid-term elections or any such thing that is worrying me. But the simple question is : What should the powers of the Governor be ? What should the Governor do ? Much has been made of the term 'stable Ministry', 'stable government' and so on. I do not know who can decide whether a particular ministry will be stable or not.

Has the Congress Party been able to provide stable Ministries in all the States ? In 1946 in the Madras State, the Congress Party had an absolute majority with about three-fourth of the elected members in their party. But within one year, Mr. Prakasam was overthrown, and Mr. O. P. R. Reddiar was elected Chief Minister, but wthin one year he was also overthrown and another person was elected.

Therefore, where is the question of stability ? In Travancore, in 1946 or 1947, out of 108 seats, the Congress had won all the 108 seats, and Shri Pattom Tahnu Pillai became the first Chief Minister. But within one year he was overthrown, in spite of the fact that the Congress had all the seats and not a single Opposition member was there.

Therefore, let us not now talk in terms of stability and all that. After all, if there is instability in this country, where does it come from? Political instability is not something which comes from a vacuum or from air. It is after all reflection of the tremendous economic and social instability that is there inside this country. After all, this social and economic instability in this country has been created not by us, not by the Opposition parties, but has been created precisely because of the policies that the Congress Government has been pursuing during the last 22 years. The Congress has not been able to provide a stable economic life to the people. Social stability has not been provided to the people. The people had tremendous faith in the Congress Party during all these years, and naturally when the people are fed up with the Congress Party, unfortunately their political development has not been such that they would be able to distinguish between the Opposition parties. The programmes of the Opposition parties have not yet been properly understood by the peole. After all, people get an understanding of the political implications of the various parties not by just reading their manifestoes and things of that type but from their experience. The people come to understand the nature of the various political parties out of their experience even as they have come to understands what the Congress Party is.

After having had experience of the Congress Government all there years, out of their bitter experience the people have come to reject the Congress Party.

16.39 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker *in the chair*]

Therefore, under these conditions, it is for the people to go through that experience and reject whichever Opposition parties they do not want. Out of their bitter experience they will do that. Then something stable will emerge in this country. After all, this is a process that has to be gone through. You cannot avoid it.

Therefore, the question is : who is the Governor to say 'I am convinced the SVD is not in a position to give a stable government'? He does not say that it does not have a majority. That is the trouble. He only says that it is not possible for it to provide a stable government. Why ? He says :

"In my judgment, the Samyukt Vidhayak Dal is not in a position to give a stable government to the State. The uncertainties in the SVD functioning as a united party are too glaring to be ignored."

Why ? Because it is a conglomeration of so many parties, they do not agree among themselves, they will fall out among themselves; therefore, they cannot provide a stable government. Therefore, there

should be President's rule and mid-term elections.

My point is : is this any criterion for the Governor to adopt ? Can his judgment be substituted for the experience of the common people of U. P. have got to go through ? If the SVD cannot give a stable government, ultimatly the people will understand it and throw it out and it is for them to decide which party they will chose for Government.

SHRI J. B. KRIPALANI : May I say neither the Governor nor the Speaker in West Bengal could decide that ?

SHRI P. RAMAMURTI : If the Governor had acted properly, the Speaker would not have done it.

SHRI J. B. KRIPALANI : One wrong does not justify another.

SHRI P. RAMAMURTI : That was the only way it could be corrected. There was no other way. Therefore, he had to do it. But that is a different matter.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA (Raiganj) : Did the Speaker act in consultation with him ?

SHRI S. M. BANERJEE : When he was in the Chair, he was all right.

SHRI J. B. KRIPALANI : All are selfish parties, speaking with their tongue in their cheek.

SHRI P. RAMAMURTI : After all, these different norms had been set up by the Congress Party to suit their own exigencies. Acharya Kripalani spoke about what happened in Madras in 1952. In the composite State of Madras, when the Congress had only 152 in a House of 375, the Governor invited Shri Rajagopalachari to from a government even though he was not a member of either House of the Legislature. And he did form a government.

People are talking of defections. Who originated it and encouraged it ? Right in 1952 when the congress was in a minority in Madras, they invited Shri Rajagopalachari who threatened the members, 'If you do not support me, I will advise the Governor to dissolve the Assembly and order re-election.' Thereby he got some members from the other side. So defection had been encouraged rigth from the 1952 by the Congress Party.

Then what happened in Andhra. What happened to Prakasan ? He was won over from some other party. Then they induced Shri Pattom Thanu Pillai to join them. This is something they have been doing all these years. But today Shri Chavan says that hereafter he will not support minority governments. This is not born out of any desire or a principle that minority governments should not be supported. Only he finds that this game of supporting minority governments does not work. In Travancore-Cochin it did not work in 1956. Later in Bengal, they tried it with a *Shikhandi* Ministry. It did not work. Again they tried it in Bihar with another *Shikhandi* Ministry. Same result. In Punjab also, what is the position ? They would certainly like to support the *Shikhandi* Ministry, out unfortunately their Rarewala comes in the way; they cannot unite their own party on the question.

Therefore, let not the Home Minister talk of high principle. Today I am only concerned with this : I am concerned with this simple question. For example, when Mr. Charan Singh resigned, he resigned on account of internal party loyalties. When he resigned he told the Governor, he wrote to the Governor that if within a week they were not able to elect a leader, in that case, he would advise the Governor to dissolve the Assembly and have fresh elections. I would have had no quarrel if the Governor had accepted that advice. But at that time he did not accept it. Who asked him at that time to keep the Assembly in suspension and allow time for the party ? At that time he said about political stability; so that loyalties could become stable. What is the point ? At that time probably he thought that an opportunity must be given to Mr. Chandrabhan Gupta to win over some people and see if the Congress party would be able to form a ministry at that time. That is probably the reason why he gave them a month. But then, it was not possible, and it has not been possible for them to win over sufficient number of people from other parties so that the Congress party could form the ministry. Therefore, can he come to the conclusion

[Shri P. Ramamurti]

that a stable ministry cannot be formed ? "I have 18 people." Who are the people, the Governor is not prepared to see. It is a wonderful thing. How is the Governor able to ascertain, I cannot understand. How is he to ascertain the loyalty of the people ? Has he got a CID report ? Is he having a special CID to go and find out the loyalties of the different people ?

SHRI J. B. KRIPALANI : The CID is under him.

SHRI P. RAMAMURTI : The CID is under him, but is he to act on the advice of the CID, and is the loyalty of the Members of the legislature to be decided by getting a special report of the CID, the police authority ? That is the simple question. The Governor has no such machinery. In the ultimate analysis, the only machinery which should be utilised is the legislature. That is the only machinery that can be utilised. You call the people and if you are not satisfied—he could have called even Shri Chandrabhan Gupta. I have no objection. He could have been called, and he could have asked him to face the Assembly straightaway. Instead of doing that, the Governor has substituted his own individual subjective judgment to the vote of the legislature. It is something which is obnoxious.

At least hereafter, now that they have experienced all these things, if the Government is even now prepared to accept some of these broad principles in the functioning of these parliamentary institutions, then I think we would have done a good thing.

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would agree with Mr. Ramamurti in this, that immediately after Mr. Charan Singh resigned and the SVD was not in a position to have a leader the Governor should have either asked the opposition leader, Shri C. B. Gupta, to form the government or dissolved the Assembly. He did not do it because as everybody knows the elections are not a joke ; they cost a lot of money ; a lot of trouble and a lot of energy. Further, may I ask, when the Governor suspended the Assembly, did the SVD or any of those fellows who criticise the Governor now, complain at that time ? No. They all sat quiet because they all wanted a chance to win over support and form the government. It is very unfair to impute motive all the time to the Congress and to the Governor for siding with the Congress. The truth of the matter is that all these Governors have bent backwards to be partial to and to favour the Opposition the non-Congress groups, and the Government of India—the Home Ministry here—has also done its best because, after all, we want success of democracy. In a democracy different parties will come into power, should come into power. Provided they run the administration democratically there can be no objection to their taking over from the Congress or the Congress taking over from them.

But what has happened ? Mr. Vajpayee, while blaming the Congress...

SHRI S. M. KRISHNA (Mandya) : Sir, on a point of order. This is the newest defection : Shri Piloo Mody from the Swatantra party has gone to the Congress Benches.

MR. DEPUTY-SPEAKER : He is a mobile Member of the House.

DR. SUSHILA NAYAR : He needs some mobility to shed his excessive weight. Sir, Mr. Vajpayee this morning was criticising the Congress for bringing the downfall of the non-Congress governments.

What has brought about their downfall? The Congress has not moved its little finger to topple them. Let the devil be given its due. Where we are wrong, we will accept it. Where opposition are wrong, they should also accept it. When they got an opportunity to run the government, each one wanted to strengthen their own party while in government. They used the Government machinery to build up their party, so that next time they alone will come to power. That has brought about their downfall.

SHRI J. B. KRIPALANI : Mr. Gupta's downfall came in 18 days.

DR. SUSHILA NAYAR : But Mr. Gupta had the grace to give his resignation immediately ; he did not try to make a majority again with defectors.

SHRI J. B. KRIPALANI : Mr. Charan Singh also resigned at once.

DR. SUSHILA NAYAR : Mr. Charan Singh, who was a defector was made Chief Minister. Is this not corruption ? (*Interruption*). I would request Dadaji not to interrupt me. I can answer his interruptions, but you ; Sir, will not give me time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I would request Suchetaji to exercise her restraining influence on him.

SHRI J. B. KRIPALANI : She is egging me on !

DR. SUSHILA NAYAR : After the fall of the Gupta ministry, we looked forward with hopes to this new ministry of Mr. Charan Singh. It is no sin that Congress has committed for which after 20 years, it lost majority in some States. After all, it is well known that when any party is in power for a very long time, people want a change. There is nothing strange about it. We were hoping that the non-Congress governments may evolve a common programme and out of that they may evolve a common party, so that we can steadily move towards a two-party system. But unfortunately those hopes were belied. They were all opportunistic and tried to help their own parties. The people were disappointed and disillusioned. Ultimately the people heaved a sigh of relief when the SVD Government, wherein different ministers talked different polices, left and President's rule was imposed. The same people who were raising slongans against the Congress in the last election were now raising slogans against the S V D and in favour of the Congress. I go round the villages and I know what is happening. The greatest good that could have happened to us was that this S V D came to power and people could compare and contrast the two Governments. Now they know that whatever its defects, the Congress still has something better to offer to the people.

As I said, the Governor did trip in the first instance. It was his duty to call Mr. Gupta to form a Government immediately. I have not the shadow of a doubt that Mr. Gupta would have formed a stable government. But the Governor gave some time, which means he himself was hoping that some defections would take place. It is not for the head of a State to encourage this type of attitude. When finally the lists started coming to him, he could see that there were same common names in both lists. When he said, "I will verify whether they belong to S V D", the S V D said, "No". They were not prepared for it.

It may be that it is not necessary to parade the legislators before the Governor. I would have nothing to say against that in normal circumstances. But, Sir when, it is an obvious thing in front of the Governor that there are people figuring on both sides and he does not know where they really belong and when the Governor had seen the phenomenon of 'ayaram' and 'gayaram' in Haryana, is he to be blamed if he said that the situation being what it is, it is not possible to have a stable government and therefore fresh elections should take place ?

Mention was made of minority ministries here and minority ministries there. One thing is definite, that if there is no clear majority in the House the leader of the largest group should be invited to form the government and not a splinter group here or there. The leader of the largest group in U. P. was Shri C. B. Gupta. Everybody knows that. Why was he not called ?

AN HON. MEMBER : What about Mandal ?

DR. SUSHILA NAYAR : Mandal has come and gone. The fact that these minority governments did not survive, is an obvious judgement and verdict of the people and their represenations against them. Why do you blame the Congress ? The unfortunate part is, if these fellows do even a wrong thing it becomes right and if we do even a right thing it becomes wrong. If they can have strange partners like Jan Sangh, Swatantra Communists and others .....(*Interruption*).

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, I rise to a point of order. My point of order is under rule 376. The hon. lady Member while referring to us said "if these fellows". It is very wrong in the sense.....

DR. SUSHILA NAYAR : I meant 'these fellow members'.

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, I am on my legs. She said "these fellows". Here everybody is not a fellow. There may be fellow travellers. Here every Member is an honourable Member. When I say hon. lady Member I say she is honourable even though she is in the Congress. That is the custom here. That is our parliamentary tradition.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. lady Member has already said that she wanted to say that the supporters of SVD who are sitting on this side etc. etc. but in a flourish she used the words "these fellows". She did not mean it.

DR. SUSHILA NAYAR : They are my fellow colleagues and Members. If they like to be called 'hon. Members' I will call them 'hon. Members' and not 'fellow Members'. There is not the least intention of being disrespectful to anybody. These 'fellow Members' means 'these hon. Members'.

SHRI S. M. BANERJEE : What about 'those johnnies' ?

DR. SUSHILA NAYAR : That may be his language, not mine. But 'fellow Members' I am capable of using ; I never thought that it was disrespectful or unparliamentary.

I was just saying that these minority ministries have gone. Why do we think of them again and again ? Why do not we think of the situation that has developed today ? It was stated by two or three hon. Members, how does the Governor know who has the majority. Well, Sir, the Governor is given the lists of Members. He does not need the CID help. There are written lists submitted by both sides. He sees the same names figuring in both the lists. Naturally he will know that there is something wrong somewhere.

Therefore, being faced with this situation, what was he to do ? The only course left to him was to advise the President that there should be a mid-term elections. It is not a matter of joy to us. We do not feel very happy that there should be mid-term elections. But there is no other alternative.

17.00 hrs.

Now comes the test for all the political parties. What are they going to do ? Are they going to give tickets to those fellows who crossed from this side to that side or from that side to this side ? Should I call them also hon. Members ? They have not acted honourably. Still, if my hon. friend, Shri S. M. Banerjee, wants them to be called honourable, I am prepared to do that. It is going to be a test for all the political parties as to what type of people they want in legislatures. Do they want to give tickets to those people who can be purchased, who are prepared to change sides for lure of office, or do they want to have such people in whose hands the interests of the common people, the masses of this country will be safe ? I hope and pray that all the political parties will bear this in mind and make proper selections and the people of UP will give their verdict. I have no doubt in my mind that they will give their verdict in favour of the Congress.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : The most important point of this debate is not which party will win at the polls or which party is responsible for the present situation or which party is completely free from all wrongs. I completely agree with Acharyaji when he says that we are passing through such a crisis, some sort of moral and political crisis, that we cannot take sides on such an issue. Since we all swear in the name of the Constitution, this debate would have been much more fruitfull if only the hon. Members belonging to the Congress Party had given some thought to the constitutional aspect of this problem.

The only question before the House is whether the action of the Governor of UP was constitutionally proper in dissolving the Assembly when that Assembly twice during its brief tenure had given sufficient

proof of its confidence in the Government by defeating the no-confidence motion. We have to judge the issue from this point of view. Once in the month of July and then late in February a vote of confidence was adopted by the Assembly which convincingly proved that the government enjoyed the confidence of a majority of the Assembly Members. Then, how does it lie in the mouth of the Governor to say that such a Government has lost its majority in the Assembly and, therefore, he is going to dismiss it, without referring the matter to the Assembly to decide it ? If we are going to give that power to the Governor it is going to be a dangerous threat to democracy in this country. The authors of the Constitution never thought that a Governor, who is a mere servant of the President, a civil servant, appointed by the Central Government will ever think of dismissing one Government had forming another Government. elected by the people. Can it be conceivable that some people will go and secretly whisper to Shri Zakir Hussain that Shrimati Indira Gandhi has lost the majority in Parliament and tomorrow the President will instal some member from the opposition as Prime Minister ? If that happens, what will be the fate of our Constitution and the image of democracy about which we are boasting so much ? So, the point is that the Governor of Uttar Pradesh, just like the Governor of Bengal and also or Bihar, bungled and committed a grave constitutional impropriety by dissolving the Assembly without testing the strength of the Government on the floor of the Assembly. That is the most important point.

Now I would like to refer to some of the points mentioned by the Governor in his letter to the President. He says that it was his desire and hope that during the period of suspension of the Assembly the political parties will take to a reorientation.

It is not the work of the Governors, who are appointed persons, to work as quislings and to take sides to see that a certain political party has majority against others. In cases of doubt he has always to refer the matter to ths Assembly which can be the only forum to decide whether a party has the majority or not.

Just like a judge, he gives a judgement here. He says, "In my judgement"—he is not called upon to give a judgement.—as if a Daniel has come and delivered the judgement. And what does he say in this judgement ? He says in this judgement, "I do not find that there is a stable ministry". He starts with the word "stable". Then he says that it should be a popular ministry. And he does not stop there. He qualifies it by saying what is the meaning of a stable and popular ministry.

Here I would just like to refer to certain hints which were given by the Congress Members on the floor of this Lok Sabha, if we would recall the speeches which were made by the Congress Members when the UP Budget was discussed here on the 25th March probably. I remember correctly that Shri Shukla said that in UP perhaps there would be a stable ministry. Now, look at the incidents from the 25th March onwards to the 10th April. In the guise of having a Congress ministry the Governor of UP started saying, "I want a stable and popular ministry."

It is most unfortunate that the Governor's authority should be used as a guise to reimpose through the backdoor one party which has lost the majority verdit of the people in the elections. We have said it many times that it should not be decided in the drawing rooms of Governors or in the big parlours of the Governors' palaces as to who has the majority. This is the most important thing. All along the Congress Party is evading this issue on a deliberate wrong interpretation of the Constitution that it is at the pleasure of the Governor the Governments run in different States. It is a completely wrong interpretation.

Why do I say this ? Here I would also like to quote certain provision from the Constitution. This matter, *i.e.*, what is the pleasure of the Governor has been decided long time back. It is not the personal pleasure of the Governor but according to the article the Constitution, the party which will come into power and the leader of which will be appointed Chief Minister by the Governor, must enjoy the confidence of the House and be responsible to the House. That is the most important thing.

Basu, one of the great constitutional experts, when he discusses about the discretionary functions of the Governor, says clearly :—

> "There is no other matter in respect of which a Governor is 'required by or

[Shri S. Kundu]

under the Constitution,' to act in his discretion. The expression 'in his discretion' in Art. 166 (3) should also be read accordingly. Unless a particular Article *expressly* so provides, an obligation of the Governor to act 'in his discretion' cannot be inferred by implication. Art. 163 makes it quite clear that except in cases where the Governor 'is *required* to act in his discretion', he is to act on the advice of ministers."

In our Constitution it has been specifically laid down as to where the Governor can act in his discretion. Only in two cases—firstly, when he acts in Assam while administering the Tribal areas as the agent of the President and, secondly, according to some of the Schedules where it has been specifically defined in the Constitution—he can act in his discretion. Because he enjoys certain immunity from legal action—no action of the Governor can be challenged in a court—this Congress Government goes on repeating the folly and the mistakes, particularly knowing that the matter cannot be agitated in the Supreme Court or the High Court. Had that sanction not been there, all the actions, whether it is instituting the Mandal Government or the P. C. Ghosh Government or any other government by this Congress, would have been declared *ultra vires* by the High Courts. There are no two opinions about that.

Now I want to go to another question.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member has only two minutes more.

SHRI S. KUNDU ; I would just quote a few lines from a report in the *Hindustan Times* dated the 8th March about what the Governor thinks about the stability and popularity of the ministry. It says :—

> "Expressing his anxiety that there should be a stable popular ministry in the State while the Fourth Plan was being formulated the Governor in his letter to the SVD leader says that only a popular ministry could take the steps necessary for augmenting the State's financial resources."
>
> "According to the Governor, a 'stable Ministry' connotes cohesion and unity of approach among the constituent units and has comfortable majority in the House to undertake legislative work including taxation measures."

What does it mean ? It means these Legislative Assemblies cannot function independently. It is the Governor, who as a dictator will decide which is a popular Ministry and it is he who will decide and be satisfied himself who can carry out the of taxation measures whether there is unity and cohesion of constituent parties. Then, he will say that this is a popular Government and this is a stable Government and then only he will allow it to form a Ministry. If we allow the Governors to practise these habits, virtually we arrogate to him the role of dictator and with a more Constitutional head. Let the Congress people not think that they will be in power for all times to come. They should have at least got a pointer from the last General Elections. There has been terrific transformation, I should say, a revolution; going on in the country and they must read the writing on the wall and they must count their days.

The only thing we can do is to see that the image of democracy is not tarnished and the Constitution is not murdered, if you can do that, at least some hope will be left for our future generation to build a good democracy. I am reminded of the story of the Animal Farm of George Orwell. It is some sort of a story which makes a caricature of democratic functioning and its institution of the world. One day all the animals got together and drove out the manager who was a human being saying, "This fellow is eating all the fruits of our labour." Next day, a jackal was elected as the leader of the revolutionary government of animals and the jackal pronounced ten commandments saying, "I will do this and that." Next morning, when other animals saw that out of these ten commandments, a few commandments were completely wiped off, there was a sort of discontent and that led to an inner revolution and they went and called back the Manager again.

I would like to say that all these Congress people, by their misdeeds, by their deliberately murdering the Constitution, are only going to call the manager, the manager of dictators, the manager of bureaucrats, who are waiting to seize power by the misdeeds of the Congress people.

In this connection, I Congrtulate the

Speaker and you, Sir, the Deputy Speaker and all the Speakers of of the State legislative bodies for the Resolution that you adopted. You have showed the way and it is you who have said :

> "That a Governor shall summon or prorogue the Legislature on the advice of the Chief Minister."

And you call it a convention. You at least look at the sad side of the things. When you say this, after you have passed this judgment, they should have accepted it. But now they do not accept. It is a challenge to you; it is an affront to you. You are the guiding champion of democracy which has been licked by the Congress people. I would like to just urge upon the Congress people not to go on like this.

Mr. DEPUTY SPEAKER : Please conclude now.

SHRI S. KUNDU : Yes. One comrade of the Congress Party who is not here very vociferously said that the PSP people also wanted mid-term elections. Yes. We had the courage of conviction to say that. We meant that whenever there is a doubt, if a Ministry is defeated on the floor of the House, if it has no majority, it is the people who should decide it, not the Governor. That gentleman said that it was a mistake that the Congress people dismissed Ajoy Mukerjee Government. Where was he hiding at that time ? He had not the courage of conviction to take to task the Congress Party and resign on that issue. There, a misdeed was done. But he did not say anything at that time. After that misdeed had been done, now he says this is good and that was bad.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA (Raiganj) : The land of Rama and Krishna is in agony. We in Parliament are called upon to share in that agony, and Shri Vajpayee has given expression in his on way to the agony that is agitating the sacred land which has produced both Rama and Krishna.....

SHRI S. M. BANERJEE : Sakuni also.

SHRI C. K. BHATTACHARYYA : Why he did so ? It is because there has been a loss of integrity not only in the character of political parties but also in individual characters. That is the crux of the whole problem which has led to the agony from which the entire India is suffering today.

We have successfully conducted four General Electios cn a scale which was most stupendous. It has evoked the admiration of the entire world that elections in this process, with adult suffrage as the basis, could be conducted so successfully and so peacefully in such a vast land. After having conducted the Fourth General Elections, we thought that the democratic system was firmly established and would have a smooth sailing in future. But we seem to be faced with a sudden crisis; the crisis that has developed is proceeding from one end to the other, from the east to the western-most corner. This crisis has to be faced, this crisis has to be checked and remedied. Each one of us should look upon it not merely from the party point of view, not merely from the narrow point of view, but from the point of view, from the perspective, of an all-India character and the future of democracy in this country, and looking at it in that way, we should try to restore the integrity, not only in the conduct of the political parties but also in the conduct of the individuals, as I said.

I am reminded of Shri Vajpayee's repeated charge against the Congress Party of 'Lokatantra-ki-hathya'. When was the 'Lokatantra-ki-hathya' carried out first ? Why did Mr. Charan Singh leave the Congress on the ticket of which he had been elected ? He left the Congress, and, I might say without using the English proverb, and just got the Chief Ministership in exchange. (*Interruption*) I put this question to Mr. Vajpayee and pause for a reply. When was 'Lokatantra-ki-hathya' carried out first ? It was when Mr. Charan Singh suddenly left the Congress and accepted the Chief Ministership by creating a conglomeration of different groups, different parties, particularly for that purpose. In any case, I shall repeat again that we have got to look to maintenance of the character of the parties and individuals. That is what Gandhiji taught us throughout his entire life. The best thing that he gave to India was character. Everybody knew what an Indian would be when he knew

[Shri C. K. Bhattacharyya]

Gandhiji. We have got to maintain that character and also restore it if it has suffered in any way, if his ideal has been tarnished anywhere. I mention it because of this. My hon. friend belonging to the PSP just now stated that one Congress member had quoted from PSP, and he got irritated over it. I am just now stating that there is loss of integrity in the character of political parties. I remember, the leader of the PSP in U. P. has announced that he is going to join the Congress with his entire group, while the PSP in my constituency, Raiganj, was concentrating its forces to have their hold, in that area. Their own Partymen in U. P. are just leaving them and going over to the Congress. I was contrasting what was happening in Raiganj and what was happening in U. P.

Then, take the SSP. Today in the papers we read about the threat of Mr. Joshi that if the Kerala Branch of his party does not fall in line with what the Central Party has dictated, that Branch will be dismembered; the effect will continue on the conduct of the parties in all other States of India.

This is the process which has set in and this process has got to be checked without trying to find fault with a Governor here or with a Governor there, with what the Congress Party thinks the Governor was expected to do and with that the friends in the Opposition think he is not expected to do.

SHRI S. M. BANERJEE : He should explain how the Governor is concerned. There may be dissensions in the party, but how is the Governor concerned with that ?

SHRI C. K. BHATTACHARYYA : Shri J. B. Kripalani was referring to West Bengal and asked how the Governor of West Bengal came to the conclusion that the ruling United Front group had lost the majority ; he said that the Governor had not done any counting and he had not taken any list from the different parties. I believe that he was not correct in that. In fact, the Governor had received a representation from 17 Members of the UF group that they had left the UF group and they were going to act on their own and they wanted, therefore, a separate arrangement for themselves. That statement by a branch of the UF group led by Dr. P. C. Ghosh convinced the Governor that the group had lost the majority. That was why he proceeded to the next step of asking the Chief Minister to call the Assembly to test his majority and prove that the House had confidence in him.

Then, the question has been raised whether the Governors could act in the way they have been acting. Under certain circumstances, the Governors are justified in acting as they have done, and one of the circumstances is when there is a loss of majority demonstrable to the satisfaction of the Governor, and if that be so, then he is free to act on his own.

17.23 hrs.

[Mr. Speaker *in the Chair*]

My hon. friend who preceded me referred to the resolution of the Conference of Presiding Officers. That resolution has left one blank, and even in the speech of the chairman of the conference, namely the Hon. Speaker of the Lok Sabha that blank has not been filled. The question is whether the Governor has at all the authority of dismissing the Ministry. That question should be considered and a conclusion should be arrived at on that.

The resolution of the Conference of Presiding Officers has raised that question. Among the other things that the resolution asked the parties and the Government to consider was whether the Governor could summon, or prorogue legislatures or dismiss the Ministries. This question of dismissal has not been answered in that resolution. That question was raised in Bengal. The West Bengal Speaker stated that in his opinion the Governor had not the right to dismiss the Ministry. But the Calcutta High Court held that the Governor had that right. That judgement of the Calcutta High Court has not yet been overruled by any judgment of the Supreme Court. So long as that judgment stands, the Governor has the right and authority vested in him to dismiss the Ministry under article 163 of the Constitution.

Shri S. Kundu referred to Basu's commentary on the Constitution. Of course,

that is a standard work accepted as authority by the Supreme Court and even in other parts of the world. I would suggest to him to consult the latest edition of Basu and see Basu's note on article 163. There he narrates a list of causes for which the Governor would be authorised to dismiss a Ministry, and loss of majority is one of them.

So long as that article stands that way, the authority of the Governor to dismiss a Ministry be cannot be challenged. It may not be right to do so with the Constitution as it is and the interpretation of it made by a Constitutional Bench of one of the leading High Courts of India remaining as it is.

As I have stated, the problem now before us is how to check the tendency that is growing all around of parties and persons moving in a way not according to the declarations they make at the time of election but according to the convenience which suits them at the time when they are acting. I believe this has got to be checked.

The Home Minister has said that he is also unhappy over this position. This position has got to be taken into considerations. We are all thankful to you, Sir, that you have taken the lead and suggested to the Central Government certain things. One of the salutary recommendations you have made—I am not sure if it can be brought into effect without amending the Constitution—is that a majority of the members will have the right to requisition a meeting of the Assembly to decide whether the Government has the majority, even if the Speaker is not with them That is a very important recommendation you have made for which people will be thankful to you, In fact, this was being discussed in the newspapers when helpless members of an Assembly which was being thrattled by the Speaker were feeling or grouping for a way out. This has been suggested in your speech and in the resolution adopted at your conference. There have been suggestions in newspapers that this can be done by amending the rules of procedure, I am not sure whether it can be done that way, If it can be, it is very easy and it should be adopted by all the different legislatures in the country. If that is not possible, I belive the Central Government will have to come forward with an amendment to the particular article of the Constitution which authorises the Governor to call or prorogue the Assembly. If that is done, I believe the actual grievance of members who are being denied expression of their views in this way and the crises being created by questioning the Governor's authority to dismiss the Ministry, and the Speaker trying to throttle a legislature—all these will be solved. I should request you to take some more initiative in this matter and to have this question seen through, persuading the Government and also the opposition parties, and then both sides will agree to carry it out.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व इतिहास में क्या रहा है, मैं उस ओर इस समय विस्तार से नहीं जाना चाहता। लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि देश का यह सब से बड़ा राज्य है और परिपक्व बुद्धि के राजनीतिज्ञों का राज्य प्रारम्भ से कहलाता आया है। लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के साथ पिछले कुछ वर्षों से जो खिलवाड़ चल रही है और केन्द्र के संकेतों पर उत्तर प्रदेश के अन्दर शासन में जो अस्थिरता व्याप्त है उससे हम अपनी निगाह नहीं मोड़ सकते हैं। जहां उत्तर प्रदेश अपने साथ एक श्रुत इतिहास लिए हुए हैं वहां केन्द्र के हस्तक्षेप से उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो दमनीय इतिहास है उससे भी इस सदन में बैठे हुए अधिकांश सदस्य परिचित हैं। पंडित पन्त के मुख्य मन्त्री पद से हटने के बाद जितने भी मुख्य मन्त्री उत्तर प्रदेश में रहे उन में से एक एक करके सब को किस तरह से हटाया गया, यह एक लम्बी कहानी है जिस को हमारे कांग्रेसी मित्र अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे वह सम्पूर्णानन्द जी को हटाने की बात हो, चाहे सी वी गुप्त को हटाने की हो, चाहे बहन सुचेता जी को हटाने की हो और चाहे अब चौधरी चरण सिंह को हटाने की हो। केन्द्र से जिस तरह सब को डोरी हिला हिला करके एक

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

एक करके मुख्य मन्त्री पद से हटाया गया, वह बहुत ही दुखद इतिहास है। यह देश के सब से बड़े राज्य के विकास में भी बाधक हुआ है और राज्य के अन्दर राजनीतिक स्थिरता लाने के अन्दर भी बाधक हुआ है।

चौथे सामान्य निर्वाचनों के बाद देश ने एक सामान्य सी करवट बदली और कुछ प्रदेशों में कांग्रेस का शासन समाप्त हुआ और गैर कांग्रेसी मन्त्रीमंडल बने। मेरा अनुमान था कि हमारे कांग्रेसी मित्रों को इस दृष्टि से प्रसन्न होना चाहिए था कि मद्रास और केरल को छोड़ कर जितने भी राज्यों में गैर-कांग्रेसी मंत्रि-मंडल बने थे, चाहे वह बिहार हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, हरयाणा हो, या कोई भी अन्य राज्य हो, उन के प्रमुख अधिकांशतः उन्हीं भाइयों में से थे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जिस दिन से ये गैर-कांग्रेसी मंत्रि-मंडल बने, तब से इन्होंने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उनकी नींद हराम हो गई। सीधे आड़े जिस प्रकार से भी हो, ऐसी स्थिति बनाने का यत्न किया गया, जिस में ये गैर-कांग्रेसी मंत्रि-मंडल आसानी से शासन न चला सकें।

उदाहरण के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। आप को जानकारी होगी कि जिस समय चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उस समय वहां पर सरकारी कर्मचारियों का एक आन्दोलन चला था। अभी कुछ दिनों पहले मुझे अपनी चुनाव-याचिका के सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा। मैंने वहां देखा कि जो इन कर्मचारियों के नेता थे, वह प्रान्त के एक सब से बड़े कांग्रेसी नेता के पक्ष में गवाही देने के लिए गए। इस से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कर्मचारियों के उस आन्दोलन के पीछे कौन से सूत्र कार्य कर रहे थे और किस प्रकार से प्रान्त की राजनीति को इस तरह हिलाने का प्रयत्न किया जा रहा था।

लेकिन जहां मैं अपने कांग्रेसी मित्रों के सम्बन्ध में कह रहा हूं, वहां मैं दूसरे राजनैतिक दलों से भी अवश्य कुछ कहना चाहूंगा। उन लोगों से तो मेरी कोई शिकायत नहीं है, जिन का जनतंत्र में विश्वास ही नहीं है और जिन की कार्य-पद्धति यह है कि किसी प्रकार भी गैर-कांग्रेसी मंत्री-मंडलों को थोड़ी देर तक तो टिकाओ और इस बीच में अपनी पार्टी की शक्ति को बढ़ाओ। फिर उन मंत्रि-मंडलों को भी गिराओ और उस की आड़ अपनी शक्ति को और बढ़ाओ। इन लोगों से तो किसी प्रकार की शिकायत करने का मुझे अधिकार नहीं है।

लेकिन जिन लोगों की जनतंत्र में आस्था है, मैं विशेष रूप से उन से कहना चाहता हूं कि वे क्यों नहीं सोचते किन्हीं राजनैतिक पार्टीयों को सत्ता से हटाने की प्रक्रिया में अगर कहीं इस देश में जनतंत्र की जड़ें ही हिल गई तो आगे चल कर इस देश का भविष्य क्या होगा? मेरे मित्र, श्री भट्टाचार्य, और एक दो अन्य मित्रों ने चौधरी चरण सिंह के दल बदलने की बात कही। जिस समय चौधरी चरण सिंह दल बदल कर आए, तो कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वघात किया है। चौधरी चरण सिंह ने बड़ी दृढ़ता के साथ उत्तर दिया कि मैंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया है या नहीं, लेकिन मैं इस प्रान्त की जनता के साथ विश्वासघात नहीं किया, जिस ने हमें चुन कर भेजा है।

मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले बीस वर्षों में यह स्थिति रही कि जब किसान के घर अनाज आता था उस के दाम सस्ते हो जाते थे। गुड़ आता था, तो उसका लदान बन्द हो जाता था और इसी प्रकार गन्ने के दाम भी गिर जाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला वर्ष है, जब कि किसान को अपने अन्न, गन्ने और गुड़ के उचित दाम मिले। अगर आप

उत्तर प्रदेश के गांवों में जायें, तो वहां पर आप को ऐसे किसान मिलेंगे, जो हृदय की शुद्धता से कहते हैं कि अगर हमको यह पता होता कि कि कांग्रेस गवर्नमेंट को हटाने का यह लाभ होता है, तो हम पन्द्रह साल पहले ही इस को हटा देते। श्री चरण सिंह के मुख्य मंत्री बनने के बाद इस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हुई।

अब देश में मध्यावधि चुनावों की जो नई शृंखला प्रारम्भ हुई है, उसके सम्बन्ध में, मैं कांग्रेसी मित्रों से कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि आज वे केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के रूप में विराजमान है। हरियाणा में मई में चुनाव होने जा रहे हैं उसके बाद पश्चिमी बंगाल चुनाव के अखाड़े में उतरेगा और फिर उत्तर प्रदेश को भी इसी कसौटी पर कसा जायेगा। लेकिन हरियाणा की राजनैतिक स्थिति को देखते हुए कुछ लोगों को अभी से यह सन्देह होने लगा है कि वहां पर इन चुनावों के बाद भी कहीं पहले जैसी ही स्थिति न हो। कहीं फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की नौबत न आ जाए। इसी प्रकार शायद पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी डांवाडोल परिस्थिति उत्पन्न हो। इस लिए मैं अपने इन मित्रों से कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार के परिवर्तनों और अस्थिरता से देश में जनतन्त्र की जड़ें ही हिल गई और यहां के शासन में कोई दूसरी प्रवृत्ति आगे आ गई, तो नहीं कहा जा सकता है कि इस देश का भविष्य क्या होगा। इस लिए यह आवश्यक है कि वे दल के स्तर से थोड़ा ऊपर उठ कर देश के हित में कोई उचित निर्णय लें और ज्यादा अच्छा यह होगा कि कि उस उसका प्रारम्भ केन्द्र से करें।

उसका एक प्रकार यह है कि जैसे कि कुछ दिन पहले श्री जय प्रकाश नारायण, ने कहा है, केन्द्र में एक राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया जाये और शेष राज्य उसका अनुकरण करें। या फिर देश के सब कुशल विचारक एक स्थान पर बैठें और दलीय स्तर से ऊपर उठ कर सोचें कि क्या हमारे राजनैतिक दलों की वर्तमान प्रवृत्तियों और इस प्रकार मध्यावधि चुनावों की परम्परा से देश में जनतंत्र का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा? अगर रह सकेगा, तो हम इस परम्परा को आगे बढ़ायें, नहीं तो, जैसा कि हैदराबाद कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था, हम अपने देश में अमरीका जैसी शासन-पद्धति प्रारम्भ करें, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और वह देश के कुशल मस्तिष्कों को ले कर सरकार बनाता है। आज जबकि हम जनतंत्र के परीक्षण के चौराहे पर खड़े हुए हैं, हम इस समस्या को देर तक अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकते।

उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की राजनैतिक स्थिति से जो समस्या इस देश में उत्पन्न हुई है, उसके सम्बन्ध में जहां मैंने सत्तारूढ़ दल या बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस के मित्रों से यह बात कही है, वहां मैं अपने विरोधी भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि वे भी इस सम्बन्ध में थोड़ा सा विचार करें। जहां तक दल-बदल की प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि ज्यादातर निर्दलीय सदस्यों—चूंकि "स्वतंत्र" शब्द स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों के लिए प्रयुक्त होने लगा है, इस लिए मैं "निर्दलीय" कह रहा हूँ—द्वारा इस प्रकार की परम्परा प्रारम्भ हो रही है, जो इस देश में राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न करने में सहायक हो रही है। मेरा अपना विचार यह है कि कोई व्यक्ति निर्दलीय रूप से चुन कर आया हो, अथवा किसी दल की ओर से, जनता ने जिस रूप में उस को चुन कर भेजा है, जब तक वह उस का प्रतिनिधित्व करता है, तब तक उसको उसी रूप में रहना चाहिए और उसको अपने राजनैतिक जीवन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

अभी पीछे संविधान के निर्माताओं में से एक, श्री के० सन्तानम्, ने दल-बदल की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में एक लेख में यह कहा है कि जो सदस्य दलों से चुनकर आते हैं, उन को तो दल-बदल का अधिकार नहीं है, लेकिन जो निर्दलीय रूप में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

चुन कर आते हैं, उनके सम्बन्ध में तो एक बार यह सोचा भी जा सकता है। लेकिन जहां तक मेरा सम्बन्ध है, देश के राजनैतिक भविष्य-निर्माण की दृष्टि से मैं उस पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहता हूं।

लेकिन इस सम्बन्ध में सब से बड़ा प्रश्न यह है कि मान लीजिए, दल-बदल की प्रवृत्ति पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध लगा भी दिया जाये, लेकिन अगर कांग्रेस पक्ष में बैठे हुए सदस्य मतदान के समय अपने दल के खिलाफ ही मत दें—वे रहें तो उसी दल में, लेकिन मतदान में उसके खिलाफ मत दें, तो उस समय क्या स्थिति होगी ? इस लिए मेरा कहना यह है कि हमें अपने देश में राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से कुछ इस प्रकार की परम्पराएं स्थापित करनी चाहिए, ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिस में जनता के चुने हुए किसी प्रतिनिधि को इस प्रकार का साहस ही न हो। हम सब मिल कर इस प्रश्न पर विचार करें।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, वहां की विधान सभा भंग होने से पहले इस संसद की एक सलाहकार समिति बनी है। समाचार पत्रों को देखने से पता चलता है कि शायद वहां पर सितम्बर-अक्तूबर या नवम्बर-दिसम्बर में मध्यावधि चुनाव होंगे। मेरा निवेदन यह है कि उस समय तक आठ करोड़ लोगों के भाग्य को केवल सरकारी कर्मचारियों के हाथ में छोड़ देना मुझे कोई उचित परम्परा नहीं मालूम पड़ती है। मैं यह चाहता हूँ कि यहां पर संसद की जो समिति बनाई गई है, वह केवल राज्यपाल के लिए सलाहकार समिति का कार्य न करे, बल्कि जिस प्रकार से सारे प्रश्न विधान सभा के सामने आते थे, उसी प्रकार वे इस सलाहकार समिति के सामने भी आयें और इस समिति की राय से ही राज्यपाल निर्णय करें, ताकि प्रान्त की जनता को यह अनुभव हो कि भले ही हमारी विधान सभा भंग हो गई, लेकिन हमारे अधिकारों के रक्षक अभी भी राज्यपाल के साथ बैठे हुए हैं और जनता की भावना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय और विधि मन्त्रालय को सोचना चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार कानून के विस्तार करने की आवश्यकता हो, तो वे भी किये जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, विधान मंडलों के अध्यक्षों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए आप ने यह राय दी थी कि बहुमत के निर्णय का अधिकार राज्यपालों को न दिया जाये, बल्कि इसके लिए विधान सभा के सदस्यों की शक्ति का परीक्षण होना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में अपने मित्र, श्री भट्टाचार्य की सम्मति से सहमत हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह परम्परा केवल समाचार पत्रों में विचार का विषय बनकर न रह जाये, बल्कि सरकार उस को वैधानिक रूप देने की व्यवस्था करे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अवांछनीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

कई माननीय सदस्यों ने इस चर्चा के दौरान इलाहाबाद के साम्प्रदायिक उपद्रवों का उल्लेख किया है। यह केवल इलाहाबाद का प्रश्न नहीं है। मुझे यह कहने में कोई हिचकचाहट नहीं है कि अगर इलाहाबा में हिन्दू दोषी हैं, तो उनके साथ सख्ती के साथ वर्ताव किया जाये। और अगर वहां पर मुस्लिम दोषी हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ भी सख्ती के साथ वर्ताव किया जाये। लेकिन इस प्रकार के साम्प्रदायिक उपद्रवों को किसी पार्टी के प्रापेगेंडा का माध्यम न बनाया जाये। वहां पर जाकर कुछ लोग एक वर्ग के पक्ष में वक्तव्य देते हैं और कुछ दूसरे वर्ग के पक्ष में वक्तव्य देते हैं।

आप को पता होगा कि कुछ दिनों पहले मुरादाबाद में एक घटना घटी थी। वहां पर कुछ लोग मुहर्रम का जलूस निकाल कर ताजियों को दफनाने के लिए जा रहे थे। उन्होंने यह कहते हुए ताजियों को रेलवे लाइन पर रख दिया कि रेलवे के तार बहुत नीचे हैं; जब तक वे नहीं कटेंगे, तब तक यह प्रोसेशन पास नहीं हो सकेगा।

नौ घन्टे तक दोनों ओर की मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां रुकी रहीं। दिल्ली में रेलवे मंत्रालय का आदेश गया कि तार काटे जायें, उसके बाद तार काटें गये और तब वह मुहर्रम का जलूस वहां से पास हुआ। अब इन घटनाओं के पीछे जो इलाहाबाद में घटी हैं या और जहां भी साम्प्रदायिक उपद्रव हो रहे हैं, जरा इस बात को गम्भीरता से देख लिया जाये कि कहीं इस में पड़ोस के किसी देश का हाथ तो नहीं है, जो जान-बूझ कर हमारी आन्तरिक समस्याओं को बिगाड़ना चाहते हैं। कहीं कुछ इस प्रकार के व्यक्ति तो नहीं हैं जो राजनीतिक दलों के इस प्रकार के कुछ लोगों को लोकप्रिय बनाने के लिए इन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं इसका चुनावों में इस्तेमाल तो नहीं करना चाहते हैं? अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति है तो उसको गम्भीरता से देखना होगा और इस ढंग से देश के सबसे बड़े राज्य की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम को कुछ विचार करना होगा।

श्री मु० अ० खां (कासगंज): अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने जो प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है, मैं उस का समर्थन करने के लिये और वाजपेयी जी ने जो मोशन रखा है, उस की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वाजपेयी जी ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि कहानी वहां से शुरू होती है, जब कि गवर्नर ने हाउस को सस्पेण्ड किया। मैं यह अर्ज करूंगा कि कहानी वहां से शुरू होती है जहां से चौधरी चरण सिंह जी ने अपनी सारी जिन्दगी की सेवाओं को, जो कि कांग्रेस के प्रति थीं, अपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिये—चीफ़ मिनिस्टरी का ख्वाब, जिसे वह एक मुद्दत से देख रहे थे, अपने कुछ साथियों को साथ लेकर कांग्रेस से डिफेक्ट कर के और अपोजीशन से मिल कर नेतृत्व अख्तियार किया—असल में उत्तर प्रदेश की कहानी वहां से शुरू होती है।

उस के बाद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में मुखतलिफ़ ख्यालों के, मुखतलिफ़ आवाजों के, मुखतलिफ़ तरीकों से सोचने वालों की सरकार बनी और इस सरकार के पिछले 10 महीनों में उत्तर प्रदेश में जो कुछ किया, उस को उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। गुण्डापरवरी की मिसालें, नफ़ाखोरी की मिसालें इन 10 महीनों में इस कदर ज्यादा बढ़ी हैं, कि उत्तर प्रदेश की जनता तोबाह बोल गई।

अध्यक्ष महोदय, इस सत्ता के लिये जिस दिन से उन्होंने कुर्सी सम्भाली, उसी दिन से सत्ता के लिये, ताकत हासिल करने के लिये उन के अन्दर एक किस्म का संघर्ष छिड़ गया। उन्होंने अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, पार्टी के नाम पर चन्दा वसूल किया, जनता से गलत तरीके से रुपया हासिल किया, जिस की मिसाल अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कांस्टीचूएन्सी कासगंज को ही पेश करता हूं। जहां एक सदस्य ने, जिस ने कांग्रेस से डिफेक्ट कर के बी० के० डी० ज्वाइन किया था, चौधरी साहब के साथ उस तरफ़ गया था, उस ने यह एलान किया कि 7 फरवरी को जब कि 17 फरवरी को चौधरी साहब इस्तीफा देने जा रहे थे, मैं उस का नाम भी बताऊंगा चौधरी साहब अलीगंज तहसील के कस्बा पटेली में विराजमान हो रहे हैं, लिहाजा उन को थैली नजर करने के लिये कुछ रुपयों की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस रुपये की वसूली के लिये वहां पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया—पुलिस के जरिये, हमारे यहां चकबन्दी हो रही है, चकबंदी के अधिकारों के जरिये—क्योंकि किसी को छोटा खेत देना है, किसी को बड़ा खेत देना है, किसी को अच्छा खेत देना है, किसी की मेड़बन्दी होनी है—लिहाजा उन अधिकारों का चीफ़ मिनिस्टर को थैली पेश करने के लिये इस्तेमाल किया गया। जिन के केसेज इन अधिकारियों के यहां मौजूद थे, उन को उस चन्दे की रसीदें काट-काट कर दी गईं, इस तरीके से उस नाम पर 50 हजार रुपये इकट्ठे किये गये। यह रकम

[श्री मु० अ० खां]

एटा जिले में हुआ और जिस ने इकट्ठा किया चौधरी तिरमल सिंह, एम० एल० ए०, जिसको हमारी भूतपूर्व मुख्य मंत्री अच्छी तरह से जानती हैं।

जिन लोगों के पास मुखतलिफ़ पोर्टफोलियोज थे, उन्होंने आते ही सब से पहला काम यह किया कि जितने लोग मुखतलिफ़ कमेटियों में गवर्नमेंन्ट की तरफ से नौमिनेटेड थे, उन को बरखास्त कर के अपनी पार्टी के लोगों को उन कमेटियों में नौमिनेट किया, बहुत सी नई-नई कमेटीज का निर्माण किया अपनी पार्टी के लोगों को उन में एडजस्ट करने के लिये। जिस की मिसालें एजूकेशन डिपार्टमेन्ट में हैं, कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट में हैं और दूसरे डिपार्टमेन्ट्स में हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन लोगों से साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अपने गलत कामों को अपने इल्जामों को इस तरह से कांग्रेस के जिम्मे थोप कर इस हाउस में आप इस तरह की बातें कह सकते हैं, लेकिन याद रखिये 6 महीने के बाद इलैक्शन होने वाला है, 5 महीने बाद इलैक्शन होने वाला है, 7 महीने बाद इलैक्शन होने वाला है, आपके काले कारनामे आप को नहीं बक्सेंगे।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, वह आपके काले-कारनामों को कह रहे हैं।

श्री मु० अ० खां : मैंने संयुक्त विधायक दल के काले कारनामों के लिये कहा है, अध्यक्ष महोदय की शान में मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय, एक सब से गम्भीर बात की तरफ, जिसको हमें इस हाउस में उठाने से रोका जाता है, आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। आज हमारे प्रदेश में, बल्कि सारे देश में, कम्यूनल डिस्टर्बेन्सेज की एक बड़ी भारी बला फैल रही है, जिससे इस मुल्क की एक सबसे बड़ी माइनौरिटी कम्यूनिटी को बहुत भारी धक्का लगा है, एक किस्म का डर सा उन के ऊपर गालिब हो गया है। इलाहाबाद में एक महीने के करीब हो गया, जिस दिन के बल्वा शुरू हुआ, जिसमें चार आदमी मारे गये। वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की यह हालत है कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गलत स्टेटमेन्ट देते हैं कि वहां की हालत ठीक है, कन्ट्रोल में है, जब कि अभी कल और परसों की बात है वहां पर सात आदमियों की जानें जाया हुई हैं। कई आदमी जख्मी हुए। मगर अखबारों में सिर्फ चार आदमियों की खबर है। मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूं—वहां पर सात आदमियों की जानें जाया हुई हैं। जहां बल्वा शुरू होने के बाद यह हालत है, वहां का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहता है कि हालत काबू में है। रोजाना वहां पर बम केसेज होते हैं—लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हालत कंट्रोल में है। कई मेम्बर पालियामेन्ट वहां मुआअना करने के लिये गये, मैं भी उन में से एक था, हम लोगों ने स्टेटमेंन्ट दिया और वहां की सारी स्थिति को बताया। हम लोग प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, इलाहाबाद का डेलीगेशन भी यहां आया, वह भी मिला और हम ने यह रिक्वेस्ट की कि वहां का एडमिनिट्रेशन इस में इन्वाल्व्ड है। यह बात सिर्फ इलाहाबाद के सिलसिले में ही नहीं है, जहां-जहां कम्यूनल डिस्टरबेन्सेज हुए हैं, वहां से शिकायतें मिली हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में कई ऐसे कम्यूनल माइन्डेड लोग हैं, जो इस किस्म की चीजों में इन्वाल्व्ड होते हैं, इस लिये हम ने गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया से बरख्वास्त की कि इस सिलसिले में फौरी कदम उठाये। जहां गवर्नमेंन्ट आफ इण्डिया इस जिम्मेदारी से बचना चाहती है—यह कह कर कि यह स्टेट का सवाल है, वहां मैं यह अर्ज करूंगा कि यह नासूर इतना बड़ा हो चुका है कि अब इस बात को कह कर कि यह स्टेट मैटर है, हम अपनी जान नहीं बचा सकते। इस को नैशनल प्राबलम समझना

होगा और नशनल प्राबलम समझकर इस का फैसला करना पड़ेगा ।

हम ने प्राइम मिनिस्टर साहबा से रिक्वेस्ट की कि कम से कम जहां इस बात का पता चलता है कि इस किस्म के कम्यूनल डिस्टरबेन्सेज में एडमिनिस्ट्रेशन इन्वाल्व्ड है, वहां फौरन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक्शन लिया जाय, उन को सजा दी जाय, उन को जिम्मेदार ठहराया जाय, जहां भी कम्यूनल डिस्टरबेन्सेज होंगे, उस के लिये तुम जिम्मेदार होगे । जब तक इस तरह का इफैक्टिव कदम नहीं उठाया जायगा, तब तक इन हालात पर काबू पाना बहुत मुश्किल है ।

इलाहाबाद में सैकड़ों घरों में आग लगाई गई, उन को लूटा गया, जानें जाया हुई हैं, दरख्वास्तें करते हुए एक महीना गुजर गया कि इन हालात पर काबू पाया जाय, लेकिन आज तक, बड़े शर्म की बात है, अफसोस की बात है, एक महीना गुजर जाने के बाद भी इलाहाबाद में हालात पर काबू नहीं पाया गया, आज तक इस के सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछा गया, उन को सजायें नहीं दी गई । वहां कलैक्टर और एस० पी० को, जो रोज बड़े-बड़े बयान देते हैं, झूठे स्टेटमेन्ट देते हैं, उन को मजबूर नहीं किया गया उन को सजा नहीं दी गई, उन का ट्रांस्फर नहीं किया जाता । अब आपको इस तरफ फौरी कदम उठाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर दिया ।

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : Mr Speaker, Sir, Shri B. Gopala Reddi, who is the Governor of Uttar Pradesh, is always unfortunate.

MR. SPEAKER : I thought, he was the most fortunate.

SHRI TENNETI VISWANATHAM : He has been very much criticized here. Generally he pays for the doings of others,

AN HON. MEMBER : Voice of America.

SHRI TENNETI VISWANATHAM ; Yes, once it was the Voice of America; now it is the voice of jacob but the hand is that of Saul. No doubt, he has prepared the report and sent it here, but everything has been managed from this place and this place alone. It is true, the language of the statement is Shri Gopala Reddi's. I have absolutely no doubt about it. But in the preparation of the statement he has not been very clever. That is the trouble and that is why he has been criticized.

In one portion he says, "Unless I am absolutely clear that it is not possible to have the democratic process I should not advise mid-term elections." At first that is what he said, two months ago. Today in this statement what he says is, "The position is doubtful; the condition is fluid." That is what he says today. He is not absolutely clear but all the same he has changed his decision; that is, the decision does not follow the reasoning. That is why I said that the decision belongs to Delhi, the reasoning belong to Lucknow.

Shri Chavan, the Home Minister, himself was good enough to say that we must look at the whole history. And what is the whole history ? Other Members, who spoke from the Congress side, narrated it. They have been narrating the politics of U. P. But today the question is whether a Governor was right in making the recommendation and whether the Central Government here was right in accepting it. That is the simple point.

According to the Governor, there is no change in the majority and the minority. The situation is only fluid. But at one place he says, "Although it is true that Shri Charan Singh had the majority at the time of resignation, now people are changing side to side and I find some people whose name is found on both sides." If that was a fact, it was very easy for him to cancel those names and then take the majority and the minority. It was a very simple process. If the same name is found in both the lists, he should have struck it off and then seen who is in the majority and he should have simply offered the government to the party which is in majority. It would

[Shri Tenneti Viswanatham]

have been easy for them to face the Legislature and get the verdict. There was absolutely no difficulty.

Perhaps, if he was left to himself, he might have done it. In ordinary voting also several times, when we get invalid votes what do we do ? When a member votes for two persons and there is only one seat, the vote is cancelled and the rest of the votes are counted. Why did he not do it ? He could not do it because only the voice was his, the hand was somebody else's.

Therefore, in this case Shri Vajpayee was right in saying something very strong. Of course, the language is strong that democracy has been murdered. But here there was a case not of murder but of throttling. For two months there was throttling and now the life has gone. Today, of course, people say, "What is there ? We can have the mid-term elections and can settle it." It is all right, but what happens to the process of democracy in this country is what is troubling us.

This morning the Home Minister was saying, "We have tried many experiments in all the States and now we find that this is the best." Will he at least stick to it ? These things may happen again and again. Still, there are some States where the Congress Party is ruling and the chance might come to him to stick to this. I only want him to stick to it.

श्री नागेश्वर द्विवेदी (मछलीशहर) : अध्यक्ष-महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करने के लिए और माननीय गृह मन्त्री ने जो प्रस्ताव अथवा संकल्प उपस्थित किया है उस का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

उत्तर प्रदेश की जो स्थिति हो गई थी उस स्थिति में महामहिम राज्यपाल ने जो रिपोर्ट दी और उस पर महामहिम राष्ट्रपति ने जो निर्णय लिया वास्तव में उत्तर प्रदेश के लिए वही एक रास्ता था। उत्तर प्रदेश में पिछले एक साल में जो घटनाएं घटी हैं और जिस तरीके की स्थिति आई है उस को देखते हुए कोई और रास्ता नहीं था और इस के अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता था। पिछले चुनाव में कोई भी पार्टी इतने बहुमत में नहीं आई कि अपनी सरकार बना सकती थी। कांग्रेस वालों ने कुछ दिन इंतजार किया और इसके बाद कुछ निर्दलीय सदस्यों को लेकर सरकार बनाई। वह सरकार कुछ ही दिन चल पाई थी कि कांग्रेस पक्ष के ही एक ऐसे वरिष्ठ सदस्य को जिस को पिछले 20 वर्ष में 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेसी शासन में किसी न किसी पद पर रह कर शासन करने का अवसर मिला था उस को यह प्रलोभन देकर तोड़ा गया कि हम आप को चीफ़ मिनिस्टर बनायेंगे और वह उस प्रलोभन के चक्कर में आ गये। लेकिन उस के पहले यह तक सूचना नहीं दी गई कि क्या क्या कदम उठाये जायेंगे। अगर यह जानकारी होती और चौधरी चरण सिंह जी इस बात को पहले कहे होते कि इस तरह का हम ऐक्शन लेने जा रहे हैं, इस तरह के क़दम हम उठाने जा रहे हैं, तो सम्भवतः इस तरह की घटना न होने पाती। लेकिन यकायक आश्वासन देकर कि कोई बात नहीं है सब साथ रहेंगे लेकिन आखरी दम में ऐलान करते हैं कि हम 17 आदमियों को लेकर उधर जा रहे हैं। इस बात के ऐलान पर गुप्ता जी ने जो एक क़दम उठाया, वह एक आदर्श कदम था। उन्होंने देख लिया कि हमारा हाउस में बहुमत नहीं है, तुरन्त इस्तीफ़ा दे दिया। उसके दूसरे ही दिन संविद की सरकार बनी। यह 31 सूत्री कार्य-क्रम को लेकर आप ने मोर्चा कायम किया लेकिन जब सरकार बनने की नौबत आई तो 31 सूत्री कार्य-क्रम के स्थान पर 19 सूत्री कार्य-क्रम पर उन की एकता क़ायम हुई लेकिन पिछले 10 महीने में जो उन की सरकार चली तो वह 10 सूत्री कार्य-क्रमों में भी एकमत न रह सके और वह एक दूसरे को ही काटते रहे। अगर इन में कुछ एकता थी तो केवल एक बात पर थी कि कांग्रेस की हुकूमत किसी तरीके से न आने पाये।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो हारी हम को इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस वालों की आपस की लड़ाई से और कांग्रेस वालों द्वारा आपस में जो एक दूसरे की मुखालफ़त की गई उस के ही परिणाम से वह हुआ । लेकिन पिछले 10 महीने में जो अनुभव उत्तर प्रदेश की जनता को हुआ, कांग्रेस वालों को हुआ और जिस तरीके की हुकूमत विरोधी पार्टियों ने इन 10 महीनों में करके वहां दिखलाई है जो चुनाव आयेगा उस में उसकी परिक्षा हो जायगी और वह लोग देख लेंगे कि वहां की हुकूमत कैसी थी बाकी इतना जरूर मैं कहे देता हूं और विश्वास के साथ कह देना चहाता हूं कि पिछला अध्याय वहां पर नहीं दुहराया जाने वाला है । जो इस बात को कहते फिरते थे कि कांग्रेस हुकूमत ने 20 वर्ष में क्या किया है, स्वयं उन्होंने इन 10 महीनों में सरकार में रह कर जो कुछ किया है, जनता के सामने उस का स्पष्ट चित्र आ गया है । वास्तव में कांग्रेस क्या कर सकती थी और कितना किया, संविद ने क्या किया सब सामने है । आखिर मेरे यह मित्र इतने घबड़ाते क्यों हैं ? चुनाव का नतीजा सामने आने वाला है । चुनाव के मैदान में सब आयेंगे । आप लोग भी आयेंगे । अगर जनता आप को वोट देती है । और आप जीतते और सरकार बनाते हैं तो उस पर हम कोई ऐतराज नहीं करेंगे और जनता की इच्छा के आगे अपना सिर झुका देंगे । लेकिन जनता अगर आप को मंजूर नहीं करती है तो फिर आप भी जनता की इच्छा का आदर करना सीखिये और कांग्रेस को शान्ति से शासन करने दीजिये । आप ने 7-7 दल इकट्ठे करके स्टेशन की रेलगाड़ी बनाकर चला ली है तो मेरा कहना है कि वह इकठ्ठा तो कर लिये गये थे लेकिन वह अनेक दिशाओं में जाने वाले थे । ऐसे लोगों के संगठन शहर नहीं बन सकते हैं, स्टेशन के रूप में भले ही हो जायें । जो कारनामे उन्होंने किये हैं उन को उत्तर प्रदेश के किसान जानते हैं । 1967 के चुनाव में उत्तर प्रदेशों में जो सब से बड़ी विरोधी पार्टी असेम्बली के अन्दर थी वह जनसंघ की थी । उन जनसंघ वालों ने महंगाई और गोवध बन्दी के दो नारे लगा कर चुनावों में सफलता पाई थी । लेकिन दस महीने में गोवध बन्दी के मामले में और महंगाई के मामले में उन्होंने क्या करके दिखलाया है ।

18.00 hrs.

अध्यक्ष महोदय, : अब माननीय सदस्य का समय पूरा हो गया ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी : इन शब्दों के साथ मैं गृह मन्त्री जी के संकल्प का समर्थन करता हूं और श्री वाजपेयी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री बैं० ना० कुरील (रामसनेहीघाट) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत जो कार्यवाई हुई है अर्थात् विधान सभा को भंग किया गया है और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई है तथा मध्यावधि चुनाव का जो सुझाव दिया गया है, उससे किसी को खुशी नहीं है, किसी को प्रसन्नता नहीं है । हम सब दुखी हैं, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों । परन्तु देखना यह है कि यह किन परिस्थितियों में हुआ और वह परिस्थितियां कैसे आई । साथ ही यह भी देखना है कि जो मौजूदा परिस्थितियां थीं उन में और कौन सा विकल्प था, गवर्नर ने जो सुझाव दिया है, अथवा रिपोर्ट दी है, उसके अतिरिक्त और क्या विकल्प होना था ।

जैसा अभी बतलाया गया 1967 के आम चुनावों के बाद जो उनके नतीजे निकले उनके अनुसार किसी का बहुमत वहां नहीं था । कांग्रेस ने किसी तरह से सरकार बनाई, लेकिन उसको अपदस्थ करने के लिए जितनी भी विरोधी पार्टियां थीं, चाहे उनके सिद्धान्त मिलते थे या नहीं, विचार धारा मिलती थी या नहीं, सब प्रयत्न करने लगीं । एक तरफ कम्यूनिस्ट हैं जो धर्म में विश्वास नहीं करते, दूसरी तरफ जन

[श्री बैं० ना० कुरील]

संघ है जो धर्म का नारा लगाता है। इस तरह से वहां पर गुटबन्दी शुरू हुई कांग्रेस को अपदस्थ करने के लिए। उनकी सरकार बनी। हम लोग भी प्रसन्न हुए कि जो चुनाव के दिनों में नारे लगाते थे, हरे बाग दिखा रहे थे, वे जनता का कुछ काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या ? नारा यह लगता था कि "रोजी रोटी दे न सकी वह सरकार निकम्मी है"। उस वक्त कांग्रेस सरकार थी वह निकम्मी थी क्योंकि रोजी रोटी नहीं दे सकती थी। लेकिन उन्होंने क्या किया जिन लोगों को रोजी रोटी मिली हुई थी उनको हटा दिया। कर्मचारियों को हटा दिया, जो औरतें काम कर रही थीं, उन सब को हटा दिया गया। जब औरतों ने चीफ मिनिस्टर के यहां धरना दिया तब उनके बाल पकड़ कर उन को खींचा गया, उनकी धोतियां फाड़ी गई, उन को घसीटा गया, यह अत्याचार हुए। वहां गोलियां चली और कर्मचारियों को जेलों में ठूंसा गया। जो उनके नारे थे वह सब बदल गये।

यही नहीं किया। जो कमजोर सेक्शन था, हरिजन थे, उनके लिये जो स्कीमें थीं, जितनी गरीब महिलाओं के कल्याण की स्कीमें थी, उन को बन्द कर दिया। कल प्रधान मन्त्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वीकार किया कि यह योजनायें संविद की सरकार ने बन्द कर दी थीं। यही नहीं उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर श्री चरण सिंह को भी बहुत दुखी कर दिया था। उन्होंने दुखी होकर जो वक्तव्य दिया था मैं उसको पढ़ कर आप को सुनाना चाहता हूँ :

"यह बहुत दुःख की बात है कि संविद में सम्मिलित किसी भी दल को देश की, राष्ट्र की चिन्ता नहीं है। वह अपने-अपने दलों को मजबूत करने में लगे हुए हैं, और इस तरह से अपने गुट को मजबूत करना ही उनका आज लक्ष्य है।"

यह मैं 19 फरवरी के "हिन्दुस्तान" से पढ़ रहा हूँ। यह बहुत बड़ा वक्तव्य है लेकिन इस में मैं नहीं जाना चाहता। यह उन का सर्टिफिकेट है जो इकाइयां जुड़ी हुई थीं उनके लिये। इस तरह की स्थिति हो गई थी। न कोई सरकार चल पा रही थी और न वहां कोई शासन रह गया था। तब इस के अलावा गवर्नर साहब के पास क्या विकल्प था ?

इधर जब चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया तब फिर घटनायें होती रहीं। कोई नेता चुने जाने के लिये नहीं मिला। दो लोग कांग्रेस में मिल गये। कांग्रेस से तो कोई जाने वाला था नहीं और उनके पास कोई नेता नहीं था। तब रोज कहीं समन्वय मीटिंग होती है, कहीं अनन्वय मीटिंग होती है। आप जानते हैं कि उन मीटिंगों में क्या होता था। उस सायं अखबार में निकलता था "तबेले का लतिहाव"। इस तबेले के लतिहाव को देखने यहां के लोग भी जाते थे। हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं वह भी उस लतिहाव में सम्मिलित होते थे। लेकिन वहां पर कुछ नहीं बन पड़ा। उस लतिहाव का नतीजा निकला कि उन्होंने इस्तीफा दे ही दिया। फिर उन्होंने एक विकल को अपना नेता चुना। कुछ लोगों ने कहा कि विकल को नहीं लेना चाहिये और विकल अकड़ गये कि वहां से हरिश्चन्द आये। तीन दिन पहले हमें नेता चुना गया था अभी उन्होंने सेंट्रल हाल में कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई। कुछ फैसला नहीं हुआ था कि दूसरा नेता चुन लिया। मैं हटने वाला नहीं। जब इस प्रकार की स्थिति हो गई तब गवर्नर महोदय करते क्या ? मेरा कहना यह है कि ऐसी परिस्थिति में गवर्नर साहब ने जो रिपोर्ट दी है और जो यहां मानी गई है, वह उचित ही है। ऐसी हालत में और कुछ हो नहीं सकता।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

SHRI R. K. SINHA (Faizabad) : In the matter of Uttar Pradesh it appears that in spite of the fact that the Congress may be right, the Opposition will always

find fault with us. If any injustice has been done, it has been done to the Congress Party of U. P.

The S. V. D. of U. P. was leaderless for weeks together. In the morning a news item used to appear that the co-ordination committee was going to appoint the leader. The next day, it used to appear that like an angry wife Mr. Charan Singh was migrating from the S. V. D. The next day the news would appear that one section of the SSP was in revolt against the SVD leadership. The whole set of leadership and the conspiracy against the Congress broke as under because it was without principles. When the SVD came together did they have any principles ? This afternoon, it was the great Shri S. A. Dange who was telling us about principles.

Principles are all right when they are thrown back at the Congress. But when it is a question of the practice of principles what is the position ? Our friends in the Opposition have talked of socialism ? When he talked of West Bengal and Kerala he said that the Central leadership was in conspiracy against socialism. Shri S. A. Dange can be in alliance with the Bhartiya Jan Sangh and the Swatantra Party and there cannot be any conspracy against socialism ; when we of the Congress Party are in alliance, then it is said that we are against socialism. Those who throw stones at others must take a mirror in the morning and look at themselves.

Those who talk of murder of democracy in U. P. should consider this also. The great Mr. Charan Singh was contemporaneously with me on the 14th of this month in my constituency of Faizabad, and a purse of Rs. 50,000 by the worst black-marketeers was presented to him. That is socialism and that is democracy and that is idealism. When they go for the murder of democracy, it is idealism. When we do something it is not idealism.

My hon. friends opposite say that we in the Congress Party wanted to murder democracy. Did we start the movement for the ban on cow slaughter against the Central Government and all types of other agitations just on the eve of the elections ? At that time, the Congress Party was being accused that they were going to postpone the elections, and we had a conspiracy against the people of India, and yet the Congress Party under the leadership of Shrimati Indira Gandhi did hold an election and fairly enough wherever the Opposition came to power, their Ministers and Chief Ministers were sworn. So, how could it be said that we were against democracy ? In spite of the fact that we have had 20 years monopoly of power. we have been conceding election petitions and we have been conceding all democratic rights to our friends opposite. Even those elements which have been accused of being anti-national have had representation in this Parliament. So, how does it lie in their mouth to say that we have not been the elements that want to work democracy ?

Again, I would say, look at their ten-month old record of democracy. In Punjab, the Government was voted against and yet the Chief Minister did not resign ; and it is democracy ; In Punjab, the Speaker wanted to hold the people of Punjab to ransom and the Assembly party to ransom, and it is democracy for them.

Two Ministers of U. P. will come to Delhi and offer satyagraha, and it is democracy for them. All the conventions and rules of Parliamentary democracy are being practised by them ! The Chief Minister of Bihar, who had imposed sec. 144, I mean Shri Mahamaya Prasad Sinha, goes out and flouts section 144 imposed by his own Government, and it is democracy for them. Their sense of democracy is only one. What they consider as justice and right must be conceded to them. What they consider wrong, even if it is true and objective, if it is not agreed to as they want, then it is wrong.

I want to tell you a rural story of my district. It is said a man was angry with his wife. He said to her : 'Did you spread my cot in the room ?' She said, 'Yes, sir'. Then she was asked : 'Did you spread the cot in the veranda ?' The answer was, 'Yes, sir'. Then she was asked 'Did you spread it in the lawn ?' Answer 'Yes, sir'. The woman was very rural. She was asked 'What are you looking at ?' She said 'At the cows of God, the stars'. Then he started beating her because he said, 'The stars will quarrel and fall on me'.

This is the story of the Opposition. They are the murderers of democracy. They have no conventions and no sense of values. In this House, they have talked

[Shri R. K. Sinha]

of principles. Principles would have been there if the two communist parties were united into one ; principles would have been there if the PSP and the SSP had united into one party ; principles would have been there if the rightist parties had united into one (*Interruptions*).

If they have any faith in parliamentary democracy, there must be lesser and lesser number of parties. There must be certain conventions which they must swear by and must agree to. There must be certain rules.

In an address from you which was brilliant for the future of Indian parliamentary democracy, we have been given certain guidelines. But I assure you that they who want to convert potential Congress defectors into heroes shall have none in future because in Uttar Pradesh we are united. Whether it is Chandra Bhan Gupta or Kamlapati Tripati, we shall remain united and shall teach them a lesson. They shall never be permitted to take away the land of Rama and Krishna. Utter Pradesh shall justify the leadership of the Congress.

MR. SPEAKER : Shri Vajpayee (*Interruptions*).

SHRI S. M. BANERJEE : Their Congress leader has joined as HEC Chairman ! (*Interruptions*). We know what they are doing.

SHRI R. K. SINHA : Shri Banerjee is an 'Independent'.

SHRI S. M. BANERJEE : When did he join Congress ? I know what they are doing. I can prove to them. Read your own newspaper. I shall produce the *Delhi Times*.

MR. SPEAKER : Let Shri Vajpayee be allowed to start.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : इस चर्चा में सदन को यह विचार करना था कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश की विधान सभा को भंग करने के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दी वह रिपोर्ट उचित थी या नहीं और केन्द्रीय सरकार ने उसको स्वीकार करके क्या संविधान के अनुसार आचरण किया है ? मुझे खेद है कि अधिकांश सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करने के बजाय ऐसे मुद्दे प्रस्तुत किये हैं जो चुनाव सभा के लिए तो उपयुक्त हो सकते हैं लेकिन इस चर्चा से सीधा सम्बन्ध नहीं रखते । उदाहरण के लिए गृह मंत्री महोदय ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने दस प्रश्न रखे थे, उनका क्या उत्तर दिया गया । यह बात राज्यपाल ने भी कही है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चौ० चरण सिंह के प्रश्न और उनके उत्तर, इसके आधार पर राज्यपाल के आचरण को कसौटी पर कसा जायेगा ? वही प्रश्न संविद में शामिल दलों से पूछे गए थे और दलों ने उनके उत्तर भी दिये हैं । गृह मंत्री महोदय उनसे संतुष्ट हो सकते हैं, असन्तुष्ट हो सकते हैं । लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर पर उत्तर प्रदेश में संविधान का, लोकतंत्र का भविष्य निर्भर नहीं किया जा सकता है ।

देखना यह होगा कि राज्यपाल ने यह कठोर कदम उठाने के लिए जो कारण दिये हैं वे कारण वास्तविक हैं या नहीं ? गृह मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके हैं और कांग्रेस के किसी सदस्य ने तो इस प्रश्न को स्पर्श करने की आवश्यकता भी नहीं समझी । राज्यपाल ने दस अप्रैल का दिन अपनी रिपोर्ट करने के लिए क्यों चुना ? जब उन्होंने विधान सभा स्थगित की तब कहा कि हम मध्यवर्ती चुनाव नहीं चाहते । हम चुनावों को टालना चाहते हैं । उन्होंने कहा कि मैं पूरा समय देने के लिए तैयार हूं । किसी जल्दबाजी में नहीं हूं । मैं किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करूंगा । लेकिन दस अप्रैल को उन्होंने रिपोर्ट दे दी । यह दस अप्रैल की तिथि किस तरह रिकॉरिल की गई ? क्या गृह मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे सकते हैं ?

उससे पहले राज्यपाल ने कहा था :

"I am not in a hurry. I want to satisfy myself about the respective claims. I shall not favour anybody. I shall not do anything which would not satisfy the people."

उस समय वह धैर्य रखने के लिए तैयार थे, वह समय देने के लिए तैयार थे। अगर वह और कुछ दिन रुक जाते तो उत्तर प्रदेश में कोई भूचाल आने वाला नहीं था। हां एक बात हो सकती थी। फिर उनके लिए यह कहना मुश्किल हो सकता था कि अब संविद बहुमत में नहीं है। संविद ने राष्ट्रपति से मिल कर दो दिन का समय मांगा था। उसको दो दिन का समय नहीं दिया गया। इतने दिन दे दिये गए इस बात के लिए कि लोकतांत्रिक ढंग से सरकार बन सके लेकिन जब संविद बहुमत की स्थिति में आया और अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए तैयार था तो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया।

गृह मन्त्री महोदय कहते हैं कि अपने मतभेदों के कारण संविद की सरकार गिरी है। संविद के मतभेद छिपे हुए मतभेद नहीं हैं। हमने जो भी गठबंधन किया है वह प्रमाणिक मतभेदों के आधार पर किया है, एक न्यूनतम कार्य-क्रम बनाकर किया है, एक नेता चुन कर किया है। हमने कठपुतलियां नचाने का शौक नहीं पाला। पंजाब में कांग्रेस गिल और उनके साथियों के साथ एक दल बनाने को तैयार नहीं है, न्यूनतम कार्य-क्रम तय करने को तैयार नहीं है, गिल को अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं। पंजाब में कांग्रेस कठपुतलियां नचा सकती है, पश्चिमी बंगाल में कठपुतलियों का खेल-खेल सकती है। लेकिन उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि हमने जो भी गठबंधन कि है, प्रामाणिक मतभेदों के आधार पर किए हैं और जितने दल कांग्रेस के बाहर हैं उससे ज्यादा दल कांग्रेस के अन्दर हैं।

मुझे सन्तोष है कि अनेक कांग्रेस के सदस्यों ने कहा है कि राज्यपाल ने कांग्रेस के साथ अन्याय किया है। लेकिन उन्होंने इस प्रश्न की तह में जाने की आवश्यकता नहीं समझी। राज्यपाल ने राजस्थान में कांग्रेस के साथ अन्याय नहीं किया, राज्यपाल ने हरियाणा में कांग्रेस के अन्याय नहीं किया, राज्यपाल ने पंजाब और बंगाल में कांग्रेस के साथ अन्याय नहीं किया, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कांग्रेस के साथ अन्याय क्यों किया ? कारण यह है कि वह कांग्रेस के एक गुट के साथ जो गुट आज केन्द्र में सत्तारूढ़ है। न्याय करना चाहते थे। उसकी ही कृपा से वह राज्यपाल के पद पर बैठे हैं। इसलिये उन्होंने दूसरे गुट के साथ अन्याय कर दिया। सचमुच में इस राज्यपाल के इस आचरण के विरुद्ध और केन्द्र में बैठे हुये कांग्रेस के नेताओं के इस आचरण के विरुद्ध कांग्रेस में आवाज उठनी चाहिये। केवल इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है कि राज्यपाल ने कांग्रेस को नहीं बुलाया। इसकी तह में जाना होगा। राज्यपाल ने कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया ? श्री चन्द्र भान गुप्त को मुख्य मंत्री बनने से क्यों रोका गया ? कांग्रेस का बहुमत स्पष्ट है। हम अपने मतभेद प्रामाणिकता से मानते हैं। मगर कांग्रेस मतभेदों पर पर्दा डाल कर एकता का नाटक रचती है। हम में और कांग्रेस में यह अन्तर है और इस अन्तर के कारण उत्तर प्रदेश में ऐसा कदम उठाया गया, जो आवश्यक नहीं था, जो लोक-तन्त्र-विरोधी है, जो संविधान के प्रतिकूल है और जो जनता को कठिनाईयों में डालने वाला है।

गृह मन्त्री यह कहते हैं कि चौधरी चरण-सिंह ने इस्तीफा दे दिया, तो एक क्वालिटेटिव चेंज हो गया। वह यह मानेंगे कि संयुक्त विधायक दल विधान सभा में कभी हारा नहीं। वह यह भी मानेंगे कि संयुक्त विधायक दल के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव ला कर कांग्रेस संयुक्त विधायक दल को परास्त नहीं कर सकी। राज्य सभा और विधान परिषद् के चुनावों में कांग्रेस का बहुमत प्रमाणित नहीं हुआ। राज्य सभा के चुनावों में कांग्रेस को 190 मत मिले ज्यादा से ज्यादा 198 हो सकते हैं, मगर कांग्रेस कभी

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

बहुमत में नहीं थी। अगर बहुमत में था, तो संयुक्त विधायक दल था और उसे शासन बनाने का मौका देना चाहिये था।

क्या क्वालिटेटिव चैंज का अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एक नई स्लेट पर लिखावट शुरू कर सकते थे? आम चुनाव के बाद किस व्यक्ति को मुख्य मन्त्री के पद के लिए बुलाया जाये, यह निर्णय करना राज्यपाल के डिस्क्रीशन में हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आम चुनाव के बाद की स्थिति नहीं थी। एक सरकार चल चुकी थी। उस के मुख्य मन्त्री ने त्यागपत्र दिया था, मगर संयुक्त विधायक दल का बहुमत बरकरार था। मैं नहीं समझता कि जब गृह मन्त्री कहते हैं कि क्वालिटेटिव चैंज हो गया था, तो वह क्या कहना चाहते हैं।

इस चर्चा में इलाहाबाद के दंगे का जिक्र किया गया है। मेरे पास एक तार आया है इलाहाबाद से, जिस के अनुसार इलाहाबाद में एक सरकारी कर्मचारी और एक होम गार्ड की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई। यह कल की बात है। यह राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत हो रहा है। यह हत्या किन्होंने की, यह तार में लिखा है, मगर मैं उस को पढ़ना नहीं चाहता। मैं इस सदन में ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता, जिस से साम्प्रदायिकता फैले, लोगों की भावनायें भड़कें। लेकिन मुझे अफ़सोस है कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इस बात को इस तरह से, उठाया है, जिस से साम्प्रदायिक दंगें की तह में जाकर उसके ठीक तरह से उपाय करने की भावना को बल नहीं मिलेगा।

प्रयाग में जो कुछ हुआ, वह बड़ा खेदजनक है, लेकिन मैं सरकार और गृह मन्त्री से एक बात कहना चाहता हूं कि इन मध्यावधि चुनावों के अवसर पर अल्पसंख्यकों का विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाये, अगर इस संदर्भ में वे इलाहाबाद के दंगे की फिर से भड़कती हुई आग को देखेंगे, तो उन्हें पता लगेगा कि इस के पीछे ऐसे तत्व काम कर रहे हैं, जिन से सावधान रहने की जरूरत है।

अगर मेरी आवाज़ सारे देश तक पहुंच सकती है, तो मैं कहना चाहता हूं, और मैं इस बात से सहमत हूं, कि दंगे कोई भी शुरू करे, लेकिन वे फैलने नहीं चाहिये; दंगाइयों को दृढ़ता से दबाया जाना चाहिये। लेकिन देश में यह भावना पैदा करना कि सारा दोष बहुसंख्यक सम्प्रदाय का है, यह दंगे रोकने का तरीका नहीं हैं। यह चुनाव में वोट प्राप्त करने का ढंग हो सकता है, लेकिन यह साम्प्रदायिक सौहार्द और सद्भावना जगाने का तरीका नहीं है।

इलाहाबाद में जो अधिकारी दोषी हैं, उन को दंडित किया जाये, लेकिन सारे अधिकारियों पर यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि उन्होंने अपना कर्त्तव्य-पालन नहीं किया है। गृह मंत्री बतायें कि उन की रिपोर्ट क्या है। हम किसी अधिकारी का पक्ष नहीं लेना चाहते हैं। मैं अपने दल की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। हम देश में साम्प्रदायिक शान्ति चाहते हैं। हम देश में सद्भावना बनाए रखना चाहते है। ये दंगे देश के माथे पर कलंक हैं। ये दंगे देश की एकता को दुर्बल करने वाले हैं। अगर दंगों को रोकने के लिए कोई कदम उठाया जायेगा, बशर्ते कि वह कदम पक्षपात से रहित होगा और दलबन्दी की भावना से प्रेरित नहीं होगा, तो हम उस में साथ देने के लिये तैयार हैं।

लेकिन गृह मंत्री महोदय सब तत्वों पर अपनी कड़ी नज़र रखें। अब तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है। अब केन्द्रीय सरकार दंगे की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है।

एक प्रस्ताव चल रहा है राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् को पुनरुज्जीवित करने का। लेकिन उस को पुनरुज्जीवित करना तभी अर्थ रख सकता है, जब हम साम्प्रदायिक दंगों की समस्या को राजनैतिक और दलगत स्तर से ऊपर उठ कर देखेंगे, अन्यथा हम राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् में बैठ कर साम्प्रदायिक प्रेम की बात करेंगे और

बाहर निकल कर छोटे राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिये दंगे भड़कायेंगे और उस का दोषारोपण एक दूसरे पर करने का प्रयत्न करेंगे। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय इलाहाबाद की घटनाओं के बारे में सदन को विश्वास में लें।

अन्त में मैं सदन से एक अपील करना चाहता हूं। प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है। प्रश्न केवल संयुक्त विधायक दल को सरकार में आने से रोकने का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि राज्यपाल के पद पर बैठे हुए व्यक्ति किस तरह का आचरण करें। पहले कांग्रेस के मित्र स्पीकर के अधिकारों पर बंधन लगाने की बात मानने के लिये तैयार नहीं थे। जब विरोधी दल के स्पीकर होने लगे, तो उन्हें यह आवश्यकता महसूस हुई कि स्पीकारों के अधिकारों की व्याख्या होनी चाहिये। क्या राज्यपालों को भी तब बंधन में बांधा जायेगा, क्या राज्यपालों के कर्त्तव्यों के सम्बन्ध तब स्वस्थ परम्परायें डाली जायेंगी, जब विरोधी दल राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेंगे ? उस समय बहुत देर हो जायेगी। दूरदर्शिता का तकाजा यह है कि इस सम्बन्ध में सरकार आज विचार करे।

उत्तर प्रदेश में जो कुछ किया गया है, उस से लोकतन्त्र मजबूत होने वाला नहीं है। हम जनता के पास वापिस जाने के लिये तैयार हैं। राज्यपाल रेड्डी ने कहा कि राजनैतिक दलों को जनमत की गंगा में डुबकी लगानी चाहिये। उन का उपदेश ठीक है। राजनैतिक दल तो जनमत की गंगा में डुबकी लगायेंगे, मगर राज्यपालों को ऐसा आचरण कर के दिखाना चाहिये, जिस पर कोई उंगली न उठा सके। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ऐसा आचरण करने में विफल रहे हैं। इस लिये हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को ससम्मान वापिस बुला लिया जाये।

इस के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये। विदेशी आक्रमण और आन्तरिक गड़बड़ के कारण अगर केन्द्र किसी राज्य का शासन सम्भालता है, तो हम समझ सकते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा, अगर यह बहाना बना कर विरोधी दलों की सरकारें अपदस्थ की जायेंगी, तो लोकतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा; जनता का लोकतंत्र पर से विश्वास उठ जायेगा और वह घड़ी देश के लिये बड़े संकट की घड़ी होगी। उत्तर प्रदेश की चेतावनी हम सुनें, यही मेरी सब से प्रार्थना है।

मैं सदन से अपील करूंगा कि वह मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे और गृह मंत्री के प्रस्ताव को ठुकरा दे।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : Sir, I have heard very interesting speeches in the course of this debate and I was trying to find out whether I could get a reply to the basic question that I had raised. But I can say with regret that unfortunately I did not get any reply to that basic question which I would like to repeat again. I did say that after the takeover in February by the Governor when the legislatures were suspended, there was a qualitative change in the situation. When I said that it was a statement made in terms of the Constitution. I would like to explain it further.

Sir, the Speakers' Conference was mentioned when you were not here. I said here that whatever the Speakers' Conference has said is something very important which we will have to accept ultimately. I have no doubt about it in my mind. What happend here is this. There was no Chief Minister on whoes advice a legislature could be called and a decision of the Assembly could be obtained whether a Chief Minister or a leader had a majority or not. If this basic point is forgotten, what is the use of my replying to it again and again ? When I said that there is a qualitative change, it was not an election speech. It was a proposition under the Constitution that when the Legislature is suspended, there is no provision to go to the Legislature to find out who has a majority or not because the Constitution provides that the Governor cannot call a meeting of the

[Shri Y. B. Chavan]

Legislature on his own; it can be summoned only on the advice of the Chief Minister, which right you have all defended here in the case of Bengal. So, when I said that there was a qualitative change, the change was such that the Governor had to find again who commands the majority in the House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : The SVD commanded the majority.

SHRI Y. B. CHAVAN : That was the position when you took over. I did mention about the differences. I did say that there were differences. Every party has differences, because when dynamic political situations are discussed and decided, there are bound to be differences. There is nothing wrong about having those differences. But if the hon. Member, Shri Vajpayee, wants those inside the party differences to be fought on the streets, it is his choice. But I do not want it, and I would not advise those of my party to do that. It is for them to decide what they should do. In this case, the differences were of such a nature that the Chief Minister had to come out publicly and say that he is not getting the co-operation of his colleagues and other parties and, therefore, he cannot run the administration and he, in the alternative suggested mid-term elections. He went to that length.

SHRI S. M. BANERJEE : Shri Nandaji also said the same thing.

SHRI Y. B. CHAVAN : I will come to Nandaji when we will discuss Nandaji and Banerjee, both. Now we are discussing the Governor and Shri Vajpayee, both.

This basic thing is forgotten. Nobody wants to rush to mid-term elections. When we did not want mid-term elections, we were told that we were afraid to go to the people. Here, in this case, when the Governor has recommended, and we have accepted that recommendation, to have mid-term elections, we are asked : why mid-term elections ?

The hon. Member mentioned that we are trying to have *katputli*. He did mention *katputli*, puppet. He warned the Government, as if the Jan Sangh is not aware of what it has done in Haryana. Have they forgotten about it ? They remained outside the Government and they saw the game of this Aya Ram and Gaya Ram.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : We were party to the common programme and we accepted Shri Rao Birendra Bahadur Singh as our leader.

SHRI Y. B. CHAVAN : You certainly accepted him as a leader. But you did not support him as a Chief Minister ; that is also a fact. Are you going to disown that position ?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : That is a fact.

SHRI Y. B. CHAVAN ; Sometimes you have an agreement with a minimum programme ; sometimes you have agreement without a programme. But I do not want to go into that. What tactics his party adopts, it is their concern. I am not concerned about it.

Coming back to UP, again, two types of arguments were made. One was constitutional and the other was political. Some of the local political arguments have been answered from this side. So, I do not want to repeat them. But I want to make a reference to what Shri Dange has said, because he tried to raise the debate to a little higher political level ; I must say that. He raised certain points and he asked the question : are we prepared to accept any norms for the running of democracy ? It is a very relevant question and I certainly would like to answer that question and say here and now that whatever we have done so far we have done on the basis of certain norms of democracy. If you do not want to agree..... *(interruptions)* Unfortunately, the difficulty at the present moment is your norms are different from our norms. If you want to have a consensus of norms, we are prepared to sit with you.

SHRI S. M. BANERJEE : Your norms are abnormal.

SHRI RANDHIR SINGH : Their norms are subtle.

SHRI Y. B. CHAVAN : They have no norms at all. That is the difficulty. I am prepared to discuss this question completely, impersonally and in terms of what happened in the last year and a half.

The whole trouble started with defections. He said that the result of the last general elections was that the monopoly of Congress rule was broken.

Well, it was broken and we had accepted that. But then, insted of breaking the monopoly of the Congress through the elections, it was the Opposition in this country which started the abnormal norm of defecting people.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Remember Rajasthan.

AN HON. MEMBER : UP.

SHRI Y. B. CHAVAN : It was started in UP and in Madhya Pradesh.

SHRI ONKAR LAL BERWA (Kota): Rajasthan.

SHRI Y. B. CHAVAN : In Rajasthan it was not defection in that sense..... *(Interruption)*, that is, inviting people, who are elected on other parties' tickets, to come and become chief ministers. If you want to know the real meaning of defection, it is defection. Crossing of the floor was always there, but organised defection in the form of inviting people to hold big offices, not merely the office of a parliamentary secretary or a deputy minister but inviting somebody to become a chief minister and then say that we are going to have agreements with them on some minimum programme..... *(Interruptions)*

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar) : What about B. P. Mandal ?

SHRI Y. B. CHAVAN : The Opposition began the game. We are sitting in a meeting as a result of the Resolution passed by this House and we are certainly struggling to find out the solution for this. But how can I accept as a member of a political party that every other political party can go on disintegrating our party by defections ?

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : So, you agree. ?

SHRI Y. B. CHAVAN : It is not likely to happen. As a partyman I cannot say that my party only should resort not to have defections when organised defections were resorted to by other political parties. Unfortunately, this party also reacted to that position.

SHRI BHOGENDRA JHA : With the help of Governors.

SHRI Y. B. CHAVAN : You only raised the question of norms and asked me, "What are our norms ?" I have said it before and I would like to repeat it that whenever the chief ministers of the Congress Party lost their majority and saw the proof of it, they resigned without hasitating for a moment. And what is your norm ? Stick on to the office, refuse to resign refuse to call the session and wait for dismissal ! Is it a political norm ?

I am prepared, if at all there is a desire, to have some sort of a norm for all these activities. Let us sit together, think collectively and find out some sort of an agreed solution for this question of norms. I am willing for that. If we are discussing questions in an impersonal manner of the political difficulties that we are facing in the working of democracy, certainly we are prepared to show the willingness of sitting with you and finding out the norm. But what is the norm ? Whenever it suits the political parties, they say, "Have mid-term elections". Sometimes they say, "Invite our leader in order to form the government." It is not that they are talking about norms.

It is not only that to topple non-Congress governments article 356 was resorted to. In Bengal the Congress was in power and even there we had to resort to article 356.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : You lost the majority.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : Congress was not in power there.

SHRI Y. B. CHAVAN : Congress was in power at that time. You have forgotten history. You very conveniently forget facts which are not convenient to you.

So, it is not whether party A was there or party B was there.

Here, I am absolutely convinced that the Governor was keen to have a government again, but naturally he wanted to find out whether there was a stable majority there. I was asked, "What is the meaning of a stable majority ?"

AN HON. MEMBER : Political meaning.

SHRI Y. B. CHAVAN : Of course, it has a political meaning. I do not say that there is no political meaning about it. There is a political meaning.

When the Governor know that a party which had form the government and which had functioned for ten months, how it functioned and how it had to break, when he was again going to form a government, he had to satisfy himself that the government that would be formed would have stable support so that they could look into the problems of the people in a constructive manner. That was really speaking his responsibility. When the Governor is forming a government afresh, it is his responsibility. If he does not do it, he will be failing in his responsibility. He has to choose a person who will form the government and who will be directly responsible to the Legislature. That is what the Constitution says. So, naturally, it was his responsibility to see that it was stable. Claims were made by the Congress leaders... *(Interruption)*

SHRI YOGENDRA SHARMA (Begusarai) : Did Ghosh and Mandal have stable majority ?

SHRI Y. B. CHAVAN : Mandal has seen the end of his government......... *(Interruption)*

I was not responsible for Mandal Government being formed there.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : What about Gill Government ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I am not responsible. He will remain there as long as he has a majority there. He can remain there as long as he has the support there. The moment he loses the support, he will go. I do not think he should bother or I should bother about it.

श्री भारखंडे राय : ऐसी स्थिति यू० पी० में कैसे हो सकती थी कि किसी की मेजारिटी न हो, न एस० वी० डी० की और न कांग्रेस की ? यह कैसे हो सकता है, इसको जरा आप बताइये ।

SHRI Y. B. CHAVAN . Normally, it should not happen. But my case is that there was an abnormal situation. There were a number of people who were claiming to belong to both the sides. That is the main thing. I have said it. When a group of people tried to go and tell the Governor that they belonged to one side, again, they said that they belonged to the other side. It is this element which is rather fluctuating element, unstable element, which brings the instability in the formation of Government and in the running of Government. It is exactly that thing which the Governor had to avoid while forming a Government. This is the basic position. It is no use getting lost into all other details. This is the basic thing on which the Governor's assessment of the whole political situation in U. P. was based. I have no doubt that that was a *bona fide* recommendation based on his own honest assessment of the political forces functioning there and actuated by a feeling of doing, ultimately, the service to democracy of U. P. legislature. This is my own point about it.

Shri Dange, certainly, raised a question of basic instability......

SHRI D. C. SHARMA : How would you put a stop to floor-crossing when somebody is offered the Chief Ministership ? *(Interruption)*.

MR. SPEAKER : He has covered that point.

SHRI Y. B. CHAVAN : You may ask those questions sometime outside and I will answer them.

About the basic question of instability, Shri Dange brought in the value of the minimum programme, etc. in the formation of Governments. This is all high-sounding and good. But can he say that they have followed this ideology very correctly in having these coalitions ? May I ask Shri Dange about it ? Unfortunately, he is not here. How can you say that when his party is talking of economic transformation and other things and having understanding with Jana Sangh on the right side and Swatantra, still on the extreme right side ? How can we imagine this sort of a thing ? They are telling us about the ideological purity of concepts of stability and instability. I can understand if they stand ideologically on their programme saying, "This is my programme. Whether majority or minority, I will follow this line of action." I would, certainly, say. "Hats off to you, Mr. Dange." Unfortunately, they have also looked to the tactics of politics and they have also tried to see if they can have a share in Government. What is the use of telling me the philosophy of stability and instability ?

Lastly, I come to the question of Allahabad disturbances. You also expect me to give some facts about Allahabad. I am very sorry that things in Allahabad have deteriorated after a lapse of couple of weeks' time. It is true that from 12th onwards, the situation was more tense and on 16th and 17th, some stabbings took place as a result of which, I would say, roughly because there may be one less or one more, six persons died who belong to both the communities. I am very glad indeed that Shri Vajpayee came out with a categorical statement that he does believe in communal unity. I have no doubt about that. But, at the same time, I think, all political parties, including his political party, must try to create trust between the two communities. This is exactly what is being done. He said that the officers are not at fault.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : What I said was that all officers should not be blamed without there conduct being enquired into.

SHRI Y. B. CHAVAN : I quite agree with you. All the officers cannot be blamed. Naturally, I cannot say which officers committed a mistake because the whole matter is under inquiry as far as the first instalment of troubles is concerned. Immediately after the second instalment started, if I may call it so, which is an unfortunate thing, we have taken severe action about this matter. Besides declaring curfew in those areas, near the four police stations, the Inspector General of Police himself has proceeded to Allahabad with additional reinforcements of the Provincial Armed Constabulary. Also, a team of investigators from CID has been sent to investigate cases of explosion and stabbings.

Also an additional senior Superintendent of Police is being posted to Allahabad...

SHRI S. M. BANERJEE : Why don't you go there ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I would have gone today if this discussion was not here today. What can I do ? I am pinned down. My first duty is towards this House...(*Interruptions*). My first impulse was to go to Allahabad, but I could not go because my first duty is towards this House. Moreover, I have got certain experience of these troubles. I personally feel that Ministers should go a little later because the officers must be allowed to organize their work properly. I will choose the correct time and go there.....(*Interruptions*).

SHRI S. M. BANERJEE : Please go there immediately.

SHRI Y. B. CHAVAN : I will go, but I will choose my own time for it.

About Allahabad, the Allahabad riots are something which is giving me a very anxious time because it is something which is very sad. But I assure this House that we will take all the steps necessary to see that it is brought under control immediately. This is all that I would say..... (*Interruptions*).

AN HON. MEMBER : Only assurances.

SHRI Y. B. CHAVAN : It is not a question of assurance only. We have also

[Shri Y. B. Chavan]

acted on the assurances. If I do not give any assurance, they say that we are not responsible, and if I give assurances, the assurances are considered to be cheap. What am I supposed to do ?

This communal trouble is not merely a mattor of Allahabad only. They say that it is because of President's rule that it has started there. Some members did say that. Mr. Dange very eloquently asked me, "What is this President's rule ? Only communal riots !" It is not so. As a matter of fact. communal riots started in U.P. under the SVD Government, but I do not hold them responsible for it, because therc was some sort of a wave of communal riots—not only in U.P., in Bihar, in Assam, in Maharashtra and in some other areas also. So, it is a very unfortunate phase that we are facing in the life of our country and we will have to be patient about it. We have to be very principled in our expressions and in our doings about it. This is the only way of tackling this question.

I think, I have put my case before this hon. House, and I would say that the hon. House should give a careful consideration to the proposition of Mr Vajpayee and should also give a careful consideration to my proposition and take the best decision that it considers. I would not recommend like Mr. Vajpayee. मैं ठुकराने वाला नहीं हूं। मैं सोचने वाला हूं। I am a man who considers carefully and respectfully all the ideas and views that are given.

MR. SPEAKER : Now, may I put Mr. Vajpayee's motion to the vote of the House ?

MR. S. M. BANERJEE : Mr. Gopala Reddi should be dismissed.

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House regrets that the Government of India did not reject the report dated the 10th April, 1968, of the Governor of Uttar Pradesh to the President recommending the issue of Proclamation, laid on the Table of the House on the 16th April, 1968, seeking dissolution of the State Assembly and mid-term poll in the State, inasmuch as the S. V. D. in the State Assembly enjoyed majority in the Assembly and its leader ought to have been invited to form the Ministry."

The motion was negatived.

MR. SPEAKER : Now I put the motion of the Home Minister to the vote of the House.

The question is :

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 15th April, 1968, under article 356 of the Constitution in relation to the State of Uttar Pradesh, varying the earlier Proclamation issued on the 25th February, 1968."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER : The House stands adjourned till 11 A.M, tomorrow.

18.50 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 19, 1968/ Chaitra 30, 1890 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers 20, Daryaganj, Delhi-6.